चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 27 नवंबर– 03 दिसंबर 2017 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

गुजरात में क्या होगा

शशि शेखर

14 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा अहमदाबाद में थे. वहां उनका एक भाषण हुआ, जिसे सुनने के लिए युवा से ले कर बुजुर्ग तक काफी संख्या में पहुंचे. उन्होंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन तीन-चार बिन्दुओं पर ध्यान देना जरूरी है, ताकि गुजरात चुनाव को एक अलग नजरिए से भी समझा जा सके. सबसे पहले उन्होंने कहा कि मतभेद हो, लेकिन मनभेद न हो. अपने भाषण में यशवंत सिन्हा ने नरेन्द्र मोदी से सवाल किया कि आप जब यह कहते हैं कि पिछले 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, तब क्या आप उसमें अटल बिहारी वाजपेयी के 6 साल को भी जोड़ते है और अगर हां, तो इसका मतलब है कि आप अटल जी के सारे कामों पर पानी फेर रहे हैं. यानि, आप यह कहते हैं कि अटल जी ने भी प्रधानमंत्री के तौर पर कुछ नहीं किया. उन्होंने अरुण जेटली से सवाल किया कि अप्रैल 2014 में जब कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल से अधिक थी, तो किसे फायदा हुआ और वही कीमत जब दिसंबर 2014 में घट कर 60 डॉलर पर आ गई, तो उसका किसे फायदा हुआ? क्या उससे महंगाई कम हुई और उसका फायदा आम आदमी को मिला? नहीं, उसका फायदा सरकार को हुआ, व्यापारियों को हुआ. तेल की कीमत घटने के बाद भी जनता परेशान रही और ऐसे में अब अगर तेल की कीमत फिर से बढ़ जाए तब इस सरकार का क्या होगा?

क्या मोदी तुग़लक़ हैं!

अपने भाषण में यशवंत सिन्हा ने एक और महत्वपूर्ण मुद्दा ये उठाया कि यूपीए के समय जो 15 लाख करोड के प्रोजेक्ट थे, उसे भाजपा ने चालू क्यों नहीं किया? उन्होंने यह भी पूछा कि यूपीए के समय 205 लाख करोड़ रहने वाला एनपीए (नन परफॉर्मिंग एसेट) आज बढ़कर 8 लाख करोड रुपए क्यों हो गया है? अपने भाषण में उन्होंने यह भी कहा कि 8 नवंबर 2016 को जब नरेन्द्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की, तब 76 बार उन्होंने कालाधन की बात कही थी, लेकिन नतीजा क्या निकला? क्या कालाधन, टेरर फंडिंग और नकली नोटों पर कोई नतीजा निकला? सारा पैसा तो बैंकों में आ गया, फिर कालाधन गया कहां? यशवंत सिन्हा ने अपने भाषण में बताया कि कैसे नोटबंदी और जीडीपी में 2 फीसदी की गिरावट की वजह से करीब पौने चार लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. इस भाषण के बाद जब 15 नवंबर की सुबह अहमदाबाद में शंकर सिंह बाघेला से उनकी मुलाकात हुई, तो बाघेला ने उनसे कहा कि आप जिस पर (जेटली) हमला कर रहे है, वो तो कठपुतली है. जो इस सब के लिए असल दोषी है, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? उसी दिन यशवंत सिन्हा ने यह बयान दिया कि आज से 700 साल पहले भी एक शहंशाह मुहम्मद बिन तुगलक ने नोटबंदी की घोषणा की थी.

मोदी ने क्यों संभाली कमान

बहरहाल, इस भाषण का लोगों पर काफी गहरा असर हुआ. युवाओं की एक बडी संख्या उनके भाषण से प्रभावित हुई. भाजपा को यह लगा कि उसे यशवंत सिन्हा के भाषण से नुकसान हो सकता है. आनन-फानन में भाजपा ने पहले चरण के चुनाव से पहले के लिए नरेन्द्र मोदी की 30 सभाओं की घोषणा कर दी. अब नरेन्द्र मोदी पहले चरण के चुनाव के लिए 30 सभाएं करेंगे. सवाल है कि एक प्रधानमंत्री को विधानसभा चुनाव के सिर्फ एक चरण के लिए 30 सभाएं क्यों करनी पड़ रही है. दरअसल, मई 2014 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात छोड कर दिल्ली आ गए, तब से गुजरात में दो मुख्यमंत्री हुए. आनंदी बेन पटेल और विजय रूपानी. ये दोनों मुख्यमंत्री गुजरात की सरकार और प्रशासन को ठीक से संभाल पाने में नाकाम रहे. ये दोनों नेता यह नहीं समझ पाए कि पाटीदार समाज एक मजबूत समाज है. उन्हें पहचान चाहिए, सम्मान चाहिए. यही पहचान और सम्मान उन्हें ये दोनों मुख्यमंत्री नहीं दे पाए. नतीजा यह हुआ कि पाटीदार समाज और दलित समाज उद्वेलित हो गया. पाटीदारों के आरक्षण का आंदोलन हो या ऊना का दलित आंदोलन, इन दोनों आंदोलनों को ठीक से हैंडल करने में भी दोनों मुख्यमंत्री नाकाम रहे. यही वजह है कि आज जब गुजरात में चुनाव है, तब नरेंद्र मोदी को अपना गृह राज्य बचाने के लिए खुद मैदान में उतरना पड़ रहा है.

कांग्रेस की ताक़त और कमज़ोरी

दूसरी तरफ, कांग्रेस की स्थिति लगातार पहले से मजबूत होती चली गई. राहुल गांधी की सभाओं में बढ़ती भीड ने भी भाजपा के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी. कुल मिला कर राहुल गांधी की नवसृजन यात्रा सफल रही. उनकी सभाओं में भीड़ आई. उन्होंने खुद को (शेष पृष्ठ 2 पर)

इस तिकड़ी से किसका फ़ायदा, किसका नुक़सान

जिग्नेश मेवाणी : राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच के संयोजक. ऊना घटना के बाद दलित नेता के तौर पर उभरे. भाजपा के ख़िलाफ आक्रामक रूख अपनाए हुए हैं. फिलहाल भाजपा को हराना एकमात्र लक्ष्य. राज्य में 7 से 8 फीसदी दलित वोट. आमतौर पर दलित वोट कांग्रेस को मिलता रहा है. दलित-मुस्लिम एकता के पैरोकार. अगर दलितों का एकमुश्त वोट वे कांग्रेस की तरफ खींच सके, तो भाजपा के लिए मुश्किल हो सकती है.

हार्दिक पटेल : पटेल आरक्षण आंदोलन से उभरे नेता. भाजपा के ख़िलाफ आक्रामक. कांग्रेस की तरफ झुकाव. पटेलों का वोट 12 प्रतिशत. हार्दिक अगर इसमें से आधा वोट भी कांग्रेस को दिला पाए, तो कांग्रेस को बड़ा फायदा हो सकता है.

अल्पेश ठाकोर : अल्पेश ठाकोर ओबीसी नेता हैं. ठाकोर ने गुजरात में शराब के ख़िलाफ सफल राज्यव्यापी आंदोलन किया था और अपने आंदोलन में न सिर्फ ओबीसी बल्कि अन्य जातियों को भी शामिल किया था. इस आंदोलन की गूंज पूरे गुजरात में सुनने को मिली थी. गुजरात में करीब 50 फीसदी ओबीसी मतदाता हैं. भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए ये वोट अहम है. अल्पेश ठाकोर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं. वे कांग्रेस को 20 से 30 फीसदी ओबीसी वोट भी दिला पाए, तो कांग्रेस मजबूत स्थिति में रहेगी. जाहिर है, अल्पेश ठाकोर के कांग्रेस में जाने से भाजपा को झटका लग सकता है.

विधानसभा चुनाव 2012 में किसे कितनी सीटें

भाजपा	115	एनसीपी	02
कांग्रेस	61	जदयू	01
जीपीपी	02	निर्दलीय	01

3 भारत में फूड प्रोसेसिंग ...नीति ठीक करने की ज़रूरत है

4 मनरेगा : रोज़गार देने वाली योजना का 'खाता ख़ाती'

5 ...गैस चैंबर बनता देश

6 वार्ता से पहले कश्मीरियों का विश्वास जीतिए

गुजरात में क्या होगा

पृष्ठ 1 का शेष

लोगों से कनेक्ट किया. उनके संवाद का तरीका बदला, जिसका फायदा उन्हें मिलता दिख रहा है. गुजरात में कांग्रेस उभर कर सामने आई है. लेकिन अभी भी कांग्रेस और भाजपा में अंतर है. अभी भी भाजपा कांग्रेस के मुकाबले आगे है. कांग्रेस की दिक्कत यह है कि उसके पास एक भी ऐसा सर्वमान्य और मजबूत नेता नहीं है, जिसे पूरे गुजरात के लोगों का समर्थन हासिल हो. शंकर सिंह बाघेला जैसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस छोड चुके हैं. नेता की कमी ही कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है. जो 2-3 नेता हैं भी, उनमें आपस में ही इतना अधिक विरोधाभास है, जिसका समाधान निकालना राहुल गांधी के लिए भी मुश्किल साबित हो रहा है. शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने अभी तक मुख्यमंत्री का नाम घोषित नहीं किया है. कांग्रेस को पता है कि अगर वो यह काम करेगी, तो उसके नेताओं के बीच में ही आंतरिक मारकाट मच जाएगी. लेकिन एक अच्छी बात यह है कि गुजरात में राहुल गांधी और उनकी टीम के सदस्यों मसलन, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट जैसे नेताओं को गुजरात के लोग बेईमान नहीं मान रहे हैं. गुजरातियों की नजर में ये नेता अक्षम हो सकते हैं, लेकिन बेईमान नहीं हैं, जबकि मोदी को छोड़ कर भाजपा के जितने भी नेता हैं, उन्हें गुजरात के लोग शक की नजर से देख रहे हैं. हाल ही में अमित शाह के बेटे जय शाह का नाम जिस तरह से सामने आया, उससे भी लोगों की शंका बढ़ी है. यह तथ्य भी राहुल गांधी के पक्ष में गया. विकास को ले कर उन्होंने जिस तरह से सवाल उठाए, वो भी गुजरात के लोगों को पसंद आया और गुजरात के लोगों ने ही नारा लगाया कि 'विकास पागल हो गया है.' इससे भी भाजपा थोड़ा बैकफुट पर आने को मजबूर हुई.

राहुल की रणनीति

बहरहाल, भाजपा के लिए इस बार का गुजरात चुनाव इसलिए भी खास है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद वहां पहली बार चुनाव हो रहे हैं. नरेंद्र मोदी का गृह राज्य होने की वजह से यह चुनाव उनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है. यह चुनाव जीतना उनके लिए इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि इसका असर 2019 पर भी पड़ सकता है. यहां अगर हार मिलती है, तो मोदी के केंद्रीय नेतृत्व पर भी सवाल खड़े करने वाले बहुत सारे लोग आगे आ जाएंगे. लेकिन इस बार कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पहले के मुकाबले बेहतर रणनीति बनाई है. कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात में काफी पहले से अपनी यात्राएं शुरू कर दी थी और माहौल बनाने की कोशिश की, जिसका सकारात्मक असर होता दिखा भी. वे काफी सोच-समझ कर अपने पत्ते खोल रहे हैं. राहुल गांधी ने अपने गुजरात के चुनावी दौरों में सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन भी अपनाई. वे कई मन्दिरों में गए, पूजा की, तिलक लगा कर मंच पर पहुंचे और लोगों से रूबरू हुए. जिस तरह साल 2007 के चुनाव में कांग्रेस ने सीधे मोदी पर हमला किया था और सोनिया गांधी ने उन्हें मौत का सौदागर कहा था, उससे कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ था. इस बार राहुल गांधी ऐसी कोई गलती नहीं कर रहे हैं. पहले उन्होंने 'विकास पागल हो गया है' की बात तो की, लेकिन अब उससे भी परहेज कर रहे हैं. कांग्रेस नहीं चाहती कि भाजपा उसके किसी नारे को अपने खिलाफ चुनावी मुद्दा बना ले. कांग्रेस इस चुनाव को 'राहुल बनाम मोदी' बनाने के बजाय 'भाजपा बनाम गुजरात की जनता' बनाने की कोशिश कर रही है. राहुल गांधी अपने भाषण में व्यापार और रोजगार को तरजीह दे रहे हैं. वे नोटबंदी और जीएसटी की अधिकाधिक आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि गुजरात का व्यापारी वर्ग इससे नाखुश है. वे '5-10 उद्योगपतियों को फायदा और सब परेशान' का नारा दे रहे है. गुजरात चुनाव में अगर सोशल मीडिया की बात करें, तो इस बार कांग्रेस की मौजूदगी सोशल मीडिया पर भी बेहतर हुई है. इधर हार्दिक पटेल, ओबीसी नेता अल्पेश ठाकोर और दलित नेता जिग्नेश मेवाणी के साथ आने से भी कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं. कांग्रेस को यकीन है कि 'पोडा' यानि पाटीदार, ओबीसी, दलित और आदिवासी वोट के सहारे वो गुजरात की बाजी जीत लेगी.

मुद्दाविहीन चुनाव

अब तक के चुनाव प्रचार से इतना तो साफ हो गया है कि यह चुनाव मुद्दाविहीन चुनाव है. इस चुनाव में जनता की समस्याओं, मसलन, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, पानी, बिजली आदि पर कोई बात नहीं की जा रही है. रोज़गार, गुजरात चुनाव में आम लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा है. शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लोगों को रोज़गार चाहिए. इसी गुस्से को भांपते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्य के लिए कई घोषणाएं करते नज़र आए. उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए के निवेश और इससे 1 लाख नई नौकरियां पैदा करने की घोषणा की. इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने भी बेरोजगार महिलाओं और पुरुषों के लिए 4000 और 3500 रुपए की सहायता देने की घोषणा की है. लेकिन अभी भी शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए रोज़गार बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है. गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी ने 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपना संकल्प पत्र पेश करते हुए कहा था कि अगले पांच साल में 30 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे. अब5 साल बाद वे 30 लाख की जगह एक लाख नौजवानों को रोज़गार देने की बात कर रहे हैं. स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें, तो गुजरात सरकार ने पिछले तीन साल में स्वास्थ्य बजट में लगभग 6 प्रतिशत की कमी की है. कई अस्पतालों में डॉक्टर तक नहीं हैं. वर्ष 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक नवजात शिशु मृत्यु दर के मामले में भी गुजरात का रिकॉर्ड खराब है. यहां शिशु मृत्यु दर प्रति एक हजार 33 है, जबकि केरल में 12, तमिलनाडु में 19 महाराष्ट्र में 21 और पंजाब में 23 है. अब सरकार हरकत में आई है और आशा कर्मियों के वेतन में 50 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की गई है. जीएसटी और नोटबंदी के कारण पैदा हुए असंतोष ने भी चुनावी तस्वीर को दिलचस्प बना दिया है. राहुल गांधी ने कहा है कि यदि वे सत्ता में आते हैं, तो जीएसटी को बिज़नस फ्रेंडली बनाएंगे. पटेल आरक्षण, दलित उत्पीड़न जैसे मुद्दों को भी कांग्रेस भुनाना चाहती है. लेकिन जनता की समस्या पर कोई ठोस वादा किसी भी पार्टी की तरफ से होता नहीं दिख रहा है.

अमित शाह अगले सीएम!

इधर हार्दिक पटेल को लेकर भी भाजपा चिंतित है. पटेल आरक्षण को लेकर पाटीदार समुदाय काफी मुखर है और खुल कर भाजपा के खिलाफ है. हार्दिक पटेल कांग्रेस के करीब जाते दिख रहे है. ऐसे में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के चरित्र चीरहरण के लिए कई सेक्स सीडी बाजार में लाई गई. लेकिन गुजरात का पाटीदार समाज इससे प्रभावित होता नहीं दिख रहा है. उसके लिए इस सीडी का कोई मतलब नहीं है. यानि सीडी प्रकरण का चुनाव पर और गुजरात की जनता पर कोई असर होता नहीं दिख रहा है. गुजरात चुनाव में सरकार का नियंत्रण मीडिया आदि पर इतना अधिक है कि यशवंत सिन्हा के भाषण को नेशनल मीडिया ने जगह तक नहीं दी. एकाध अखबारों ने कहीं कोने में एक कॉलम की खबर छाप दी. जाहिर है, भाजपा के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है और वो इसे किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहती. बहरहाल, अगले कुछ दिनों में गुजरात का चुनाव परिणाम आ जाएगा. अब तक की चुनावी स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भाजपा की जीत का मार्जिन कम हो सकता है, इसकी सीटें घट सकती हैं, लेकिन अंततः भाजपा किसी भी तरीके से सरकार बनाने में सफल रहेगी. अगर भारतीय जनता पार्टी को साधारण बहुमत मिलता है, यानि बहुमत से कुछ सीटें ही अधिक मिलती हैं, तो संभव है कि अमित शाह गुजरात के अगले मुख्यमंत्री बन कर गुजरात चले जाएं. ■

गुजरात मॉडल में भी ज़ात की बात

विकास के जिस गुजरात मॉडल की बात की जाती है, वहां भी जाति एक ऐसा फैक्टर है, जिसे कोई राजनीतिक दल अनदेखा करने की हिम्मत नहीं जुटा सकता. जैसे उत्तर भारत, खास कर बिहार और यूपी में 'माई' और 'डीएम' जैसे जातिगत समीकरणों की बात होती है, वैसे ही गुजरात में भी कभी 'खाम' तो कभी 'पोडा' की बात हो रही है. 1985 में माधव सिंह सोलंकी ने 'खाम' समीकरण बना कर भारी जीत हासिल की थी. 'खाम' यानि क्षत्रिय, दलित, आदिवासी और मुस्लिम. वहीं इस बार कांग्रेस 'पोडा' यानि पाटीदार, ओबीसी, दलित और आदिवासी को मिला कर समीकरण बनाने की जुगत में है. वैसे नरेन्द्र मोदी के सीएम रहते हुए पिछले चुनावों में जाति बहुत बडा फैक्टर नहीं था, लेकिन पटेल और दलित आंदोलन के बाद जातिगत समीकरण दुरुस्त करना भाजपा की भी मजबूरी बन गई है. गुजरात में ओबीसी आबादी 50 फीसदी से अधिक है. आदिवासी 15 फीसदी, दलित 8 फीसदी, पटेल 12 फीसदी, मुस्लिम 8 फीसदी और अन्य जातियों की आबादी 4 फीसदी है. एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी ओबीसी समुदाय से आते हैं, वहीं गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी भी ओबीसी समुदाय से ही आते हैं.

आंकड़ों में गुजरात

- 6.04 करोड़ आबादी में से 57.4 फीसदी ग्रामीण और 42.6 फीसदी शहरी आबादी
- राज्य के 1 लाख 17 हजार घरों में बिजली नहीं है
- 10 लाख घरों में आज भी केरोसीन तेल से रात का अंधेरा दूर होता है.
- शिशु मृत्यु दर प्रति एक हजार 33. हिमाचल, तमिलनाडु, केरल से खराब हालत
- 5 साल से कम उम्र के 40 फीसदी बच्चें अंडरवेट (कम वजन)
- 10 फीसदी घरों में अभी भी साफ पीने का पानी नहीं

गुजरात की एक मुस्लिम बस्ती

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 09 अंक 38
27 नवंबर- 03 दिसंबर 2017

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय
एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन
सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999
6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-65500786
+91-8451050786
+91-9717002199
फैक्स न. 0120-2544377

पृष्ठ-16++ (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

भारत में फूड प्रोसेसिंग

निवेश जुटाने की नहीं नीति ठीक करने की ज़रूरत है

चौथी दुनिया ब्यूरो

सवाल है कि अगर हमें कुतुबमीनार पर चढ़ना है, तो हम नीचे से चढ़ेंगे या कुतुबमीनार के ऊपर से चढ़ना शुरू करेंगे और नीचे की तरफ आएंगे. दरअसल, हमारे देश में नीतियां बनाने वाले कुछ इसी तरह का काम करते हैं. नीतिगत सलाह देने वाले लोग आज सरकार को और प्रधानमंत्री को कुतुबमीनार पर ऊपर से नीचे चढ़ने की सलाह देते हैं और दुर्भाग्य की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री इस जाल में जल्दी फंस भी जाते हैं. हाल ही में उन्होंने कहा कि किसानों की उपज को खेत में ही प्रॉसेस करने के लिए, यानि फूड प्रोसेसिंग को किसानों के दरवाजे तक ले जाने के लिए जरूरी है कि निवेश जुटाया जाए. किसान की फसल प्रॉसेस होकर लोगों के पास पहुंच जाए और किसान को फायदा हो, उसे उसकी फसल का अच्छा लाभ मिले. जब निवेश आएगा तब फूड प्रोसेसिंग की यूनिट्स लगेंगी और तब किसान को दोगुना फायदा होगा. सवाल है कि ये किस तरह का आइडिया है. जाहिर है, हर आदमी हर क्षेत्र का माहिर नहीं होता है. प्रधानमंत्री भी कृषि क्षेत्र के बारे में कृषि मंत्रालय के अपने अधिकारियों से ही पूछते होंगे. ये अधिकारी ही हैं, जो अब तक इस देश को बर्बाद करते रहे हैं.

भारत मे फूड प्रोसेसिंग पर बात करने से पहले इन तथ्यों पर भी नजर डालना चाहिए. एक तथ्य यह है कि जितना खाद्य पदार्थ भारत में बर्बाद हो जाता है, वो ब्रिटेन जैसे बड़े देश के खाद्य उत्पादन के बराबर है. देशभर में फल-सब्जियों के भंडारण के लिए जितने कोल्ड स्टोरेज हैं, लगभग उतने ही और चाहिए. देशभर में हालिया समय में 6500 कोल्ड स्टोरेज हैं, जिनकी भंडारण क्षमता 3.1 करोड़ टन है, लेकिन जरूरत है 6.1 करोड़ टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज की. कृषि मंत्रालय की फसल अनुसंधान इकाई सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीफैट) की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में करीब 67 लाख टन खाद्य पदार्थों की बर्बादी हर साल होती है. इन खाद्य पदार्थों की कीमत 92 हजार करोड़ रुपए आंकी गई है. यानि, किसान की फसल बर्बाद न हो, इसकी व्यवस्था करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. इसके बाद नंबर आता है, प्रोसेसिंग का. इसके लिए एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला है. जिस ब्लॉक में जो मुख्य फसल उपजती है, उनकी प्रोसेसिंग यूनिट उसी ब्लॉक में लगाई जाए. इसके लिए निवेश जुटाने की जरूरत नहीं है. निवेश वहां पर है. सरकार को सिर्फ नियमों को ठीक करने की जरूरत है. मान लीजिए, एक ब्लॉक में अरहर, सोयाबीन, सूरजमुखी या सरसो की पैदावार होती है, तो वहीं पर उसकी प्रोसेसिंग की यूनिट लगा दी जाए.

आज सरकार अगर किसानों को नहीं बचाएगी, तो किसान कल महासंग्राम करेगा. सरकार आज इन किसानों को बचाने का काम करे, नहीं तो कल को वॉलमार्ट जैसी कंपनियां शुरू में भारतीय कंपनियों की आड़ में इस देश के किसानों का शिकार करेंगी, उन्हें अपने कब्जे में लेंगी और निवेश इकट्ठा करने के नाम पर यहां अपने उद्योगों का जाल फैलाएंगी. ये जाल भारत के लिए बहुत खतरनाक होगा. लोग कहते हैं कि इतिहास अपने को दोहराता है. अंग्रेज यहां व्यापारी बन कर ही आए थे. क्या वो इतिहास दोहराया जाने वाला है?

- **2015 में भारत में फूड प्रोसेसिंग का कारोबार 258 बिलियन डॉलर था, जिसके 2020 में 482 बिलियन डॉलर हो जाने की सम्भावना है.**
- **फूड रीटेल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर एसोचैम-ग्रांट थॉर्नटन की संयुक्त रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 2024 तक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 90 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है और राज्यों में प्रत्यक्ष तौर पर 8,000 तथा अप्रत्यक्ष तौर पर 80,000 रोजगार सृजन की संभावना है.**
- **कृषि मंत्रालय की फसल अनुसंधान इकाई सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीफैट) की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में करीब 67 लाख टन खाद्य पदार्थों की बर्बादी हर साल होती है. इन खाद्य पदार्थों की कीमत 92 हजार करोड़ रुपए आंकी गई है.**
- **जितना खाद्य पदार्थ देश में बर्बाद हो जाता है, उतना ब्रिटेन जैसे बड़े देश के खाद्य उत्पादन के बराबर है.**
- **देशभर में फल-सब्जियों के भंडारण के लिए जितने कोल्ड स्टोरेज हैं, लगभग उतने ही और चाहिए. देशभर में हालिया समय में 6500 कोल्ड स्टोरेज हैं, जिनकी भंडारण क्षमता 3.1 करोड़ टन है, लेकिन जरूरत है 6.1 करोड़ टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज की.**

जिले को एक यूनिट मान लीजिए और उस जिले के हर ब्लॉक में जो उपज सबसे ज्यादा हो, वहां पर उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के नियमों को सरल कर दीजिए. उन्हें लाइसेंस के लिए घूस देना या लाइसेंसिंग अधिकारी के पास सालों दौड़ना न पड़े, ऐसी व्यवस्था सरकार कर दे. किसानों को बिजली कैसे उपलब्ध हो, ये व्यवस्था की जाए. आज सरकारें किसानों को 24 घंटे बिजली देने का वादा तो करती हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों को 6-8 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिल पा रही है. इसका भी समाधान है. सरकार उस ब्लॉक या जिले के लोगों से कह दे कि आप अगर चाहें, तो अपनी जरूरत भर की बिजली का उत्पादन खुद ही कर सकते हैं. गौरतलब है कि सरकार ने सोलर एनर्जी की इजाजत दे दी है. बस जरूरत है उसमें लाइसेंसिंग प्रणाली को खत्म करने की. सरकार सिर्फ बिजली उत्पादन करने की छूट दे. अगर गांव में बिजली देनी है, तो उसकी लागत वहीं से वसूल हो सकती है. इस तरह बिजली भी सस्ती होगी और उपलब्धता भी जल्दी हो जाएगी. जो किसान अपने ब्लॉक में अपनी ऊपज से जुड़ा प्रोसेसिंग उद्योग लगाना चाहते हैं, उन्हें इसकी इजाजत मिले. किसान इसकी सूचना सिर्फ बीडीओ को दें. बीडीओ यह सुनिश्चित करें कि वहां पर इतनी यूनिट न लग जाएं कि फसल का उत्पादन अनुत्पादक हो जाए. इसलिए योजनापूर्वक, जितने ब्लॉक में जितनी यूनिट की जरूरत हो, उतने की अनुमति बीडीओ दें. ऐसा करने में क्या दिक्कत है? इसके लिए सरकार को किसी अडानी, किसी अंबानी, किसी अमेरिकन या किसी मॉनसेंटो की क्या जरूरत है?

2015 में भारत में फूड प्रोसेसिंग का कारोबार 258 बिलियन डॉलर था, जिसके 2020 में 482 बिलियन डॉलर हो जाने की सम्भावना है. बहरहाल, इस काम के लिए निवेश जुटाने का आईडिया जिस अधिकारी ने सरकार को दिया, कहीं उसका इरादा यह तो नहीं है कि मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथों में भारत की खेती दे दी जाए. सरकार कहीं किसानों को ये तो नहीं समझाना चाहती है कि वे कॉन्ट्रैक्ट दे दें और अपने ही खेत में मजदूर बन जाएं. वॉलमार्ट जैसी कोई मल्टीनेशनल कंपनी वहां पर उद्योग लगाए और वो फसल को प्रॉसेस कर देश में बेचे. क्या सरकार का ऐसा कोई इरादा है? अगर ऐसा इरादा है तो ये खतरनाक इरादा है. अगर ऐसा इरादा है तो इस देश की कृषि को और इस देश के इंसान को और इस देश के किसान को गुलाम बनाने का इरादा है. प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए कि इसमें एक पैसे का खर्चा नहीं है. सिर्फ नीतियों को ठीक करने की आवश्यकता है. केन्द्र सरकार से, राज्य सरकारों से या जहां-जहां आपकी सरकार है, उनसे ये नियम बनवा दीजिए कि अगर किसान ब्लॉक में अपनी मुख्य फसल को लेकर कोई उद्योग लगाना चाहे, तो उसके लिए किसानों को कहीं भागने की जरूरत नहीं है. वे सिर्फ बीडीओ के दफ्तर में जाएं, दरख्वास्त दें. अधिकारी सिर्फ इतनी प्लानिंग कर लें कि इस ब्लॉक में इस साल इतनी फसल हुई, अगले साल इतनी फसल होगी उसके अगले साल इतनी फसल होगी और उसके हिसाब से उसे यूनिट लगाने की अनुमति दे दें. ज्यादा फसल होने लगे तो ज्यादा यूनिट की अनुमति दे दें. इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी घूस या भ्रष्टाचार न हो. आप किसानों को सही ढंग से विकसित होने का अवसर तो दें. किसानों के पास पैसा है, उसी ब्लॉक में वे एक प्रोसेसिंग यूनिट लगा लेंगे और जब वो यूनिट लग जाएगी तो कंपनियां प्रॉसेस माल को खरीदने के लिए उस ब्लॉक में किसानों के दरवाजे तक जाएंगी. इससे अपने आप मार्केटिंग कॉपोरेटिव्स खड़ी हो जाएंगी. सरकार गांव में ही उत्पादन होने दे.

जिस अधिकारी ने या जिस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री को निवेश जुटाने का सुझाव दिया है, उस मंत्रालय या अधिकारी ने इस देश में अडानी और अंबानी जैसों के लिए एक नया विस्तृत क्षेत्र खोल दिया है कि वे किसानों को लूटें और वॉलमार्ट जैसी कंपनियां इनके पीछे रहकर इस देश के किसानों की खेती के ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कब्जा कर लें. फिर वे मनमाने ढंग से फसल पैदा करें और पांच साल होते-होते हम दुबारा नए सिरे से गुलाम हो जाएं, जैसे डंकल ने एक प्रस्ताव रखा था और हमसे हमारा बीज पैदा करने का अधिकार छीन लिया था. उसका विरोध 1993-96 में हुआ था, लेकिन कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय की सरकारें, खासकर नरसिम्हा राव की सरकार ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया. देवेगौड़ा और गुजराल सरकार एक-एक साल के लिए थी, उनके हाथ में कुछ था नहीं और फिर अटल जी की सरकार ने भी इसके ऊपर कुछ नहीं किया. हमारी खेती के लिए हम पहले अपना बीज पैदा करते थे. वो बीज अब मल्टीनेशनल के हाथ में चला गया. अब वो बीज पैदा करने वाली मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे देश में अपने बीज बेचती हैं, जिससे सिर्फ एक फसल होती है. प्रधानमंत्री जी अगर खेती से संबंधित होते या उनके यहां खेती होती या वे किसान परिवार से आए होते, तो उन्हें इसके पेच भी पता होते, इसका दर्द भी पता होता और इसका भविष्य भी पता होता कि इस देश की खेती का भविष्य कहां जाने वाला है. हम सारे देश के किसानों की जमीन मुफ्त में मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथों में देने की नींव आज डाल चुके हैं. इसलिए ये जरूरी है कि इस देश की खेती को मल्टीनेशनल्स के हाथों में जाने से बचाने के लिए सरकार को सोचना चाहिए. आज सरकार अगर किसानों को नहीं बचाएगी, तो कल किसान महासंग्राम करेगा. सरकार आज इन किसानों को बचाने का काम करे, नहीं तो कल को वॉलमार्ट जैसी कंपनियां शुरू में भारतीय कंपनियों की आड़ में इस देश के किसानों का शिकार करेंगी और उन्हें अपने कब्जे में लेकर निवेश इकट्ठा करने के नाम पर अपने उद्योगों का जाल यहां पर फैलाएंगी. ये जाल भारत के लिए बहुत खतरनाक होगा. लोग कहते हैं कि इतिहास अपने को दोहराता है. अंग्रेज जब यहां आए थे, तो व्यापारी बन कर. क्या वो इतिहास दोहराया जाने वाला है? अंग्रेजों ने भी पहले व्यापार करने की अनुमति मांगी थी और बाद में देश की सत्ता अपने हाथ ले ली. 200 साल से ज्यादा वो यहां पर रह गए. क्या वो इतिहास फिर दोहराया जाने वाला है. सरकार को इससे बचना होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

19 राज्यों को मनरेगा के तहत होने वाले फंड का भुगतान बंद

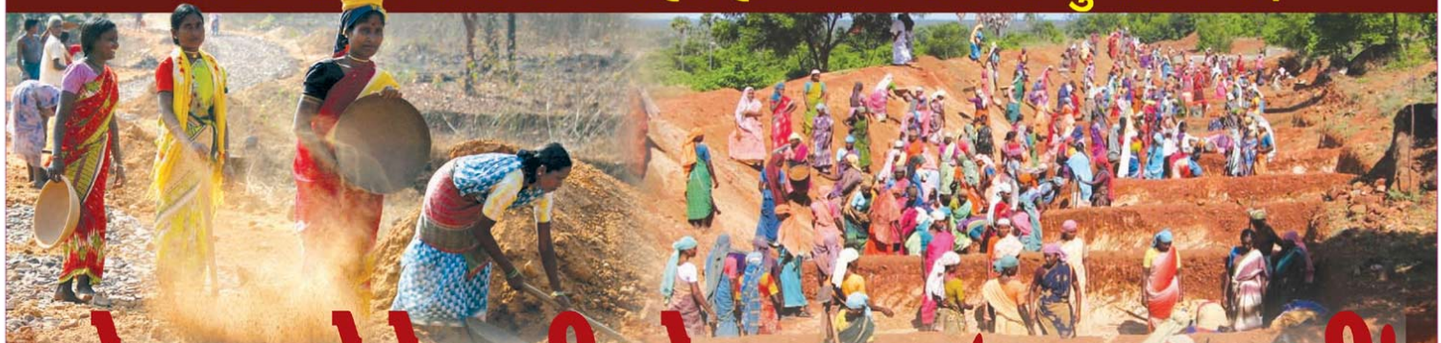

रोज़गार देने वाली योजना का 'खाता ख़ाली'

निरंजन मिश्रा

अब यह पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि मनरेगा जीती जागती स्मारक बनती जा रही है. मनरेगा के तहत मिलने वाले रोजगार में भारी कमी आने के बाद अब ये खबर आ रही है कि केंद्र सरकार पिछले कई महीनों से 19 राज्यों को मनरेगा के फंड का भुगतान नहीं कर रही है. इधर सरकार का तर्क है कि चूंकि इन राज्य सरकारों ने ऑडिटेड रिपोर्ट जमा नहीं की है, इसलिए इनका फंड स्वीकृत नहीं किया जा रहा है. लेकिन इधर मनरेगा के तहत होने वाले काम पूरी तरह से बंद हो गए हैं. काम के बाद मिलने वाली मजदूरी तो पिछले कई महीनों से नहीं मिल रही थी, लेकिन तब उम्मीद थी कि केंद्र से पैसा आने के बाद भुगतान होगा. लेकिन अब वो उम्मीद भी खत्म होती प्रतित हो रही है.

हालांकि भुगतान की प्रक्रिया में भी कई जटिलता है. दरअसल, मनरेगा के तहत कर्मियों के भुगतान की प्रक्रिया शुरू होती है, फंड ट्रांसफर ऑर्डर (एफटीओ) के जरिए, जो जिलों को भेजा जाता है और फिर राज्य के स्तर पर श्रमिकों के खातों में फंड के ट्रांसफर की मांग की जाती है. एफटीओ को ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास भेजने से पहले उस पर दो अधिकृत व्यक्तियों का हस्ताक्षर जरूरी होता है. चूंकि भुगतान बैंक खातों के जरिए होता है, इसलिए एफटीओ को पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) के पास भेजा जाता है, जो केंद्र सरकार की एक ऑनलाइन एप्लिकेशन है. लेकिन यहां परेशानी यह है कि अब तक एफटीओ ही लंबित हैं और जब एफटीओ लंबित हैं, तो इसका मतलब है कि पीएफएमएस ने उन पर कार्य नहीं किया है. यानि सरकार की तरफ से भुगतान की स्वीकृति नहीं मिली है. एक रिपोर्ट के अनुसार, मार्च-अप्रैल 2017 के दौरान 20 दिनों तक लगभग किसी भी एफटीओ पर कार्रवाई नहीं की गई थी, वहीं मई 2017 के दौरान 807 एफटीओ पर कार्रवाई नहीं हुई थी.

अलबत्ता, कारण चाहे जो भी हो, मनरेगा के तहत राज्यों को होने वाले भुगतान के बंद होने के बाद अब लाखों कामगार सड़कों पर आ गए हैं.

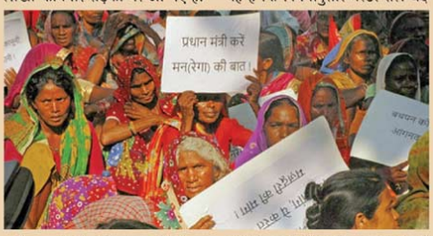

मनरेगा कर्मियों की दुर्दशा को लेकर आवाज उठाने वाले संगठनों में भी इसे लेकर भारी रोष है. अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु प्रताप सिंह ने चौथी दुनिया से बातचीत में कहा कि 'जिस योजना के कारण लाखों परिवारों के चुल्हे जलते थे, उस योजना के अप्रभावी हो जाने के कारण अब भूखमरी जैसी समस्या सामने आ गई है. सुदूर गांवों में हालत और भी खराब है. जब मनरेगा आया था, तब जमीनी स्तर पर इसका बहुत सकातरात्मक प्रभाव देखने को मिला था. इससे वृहद स्तर पर पलायन रुका था और लोगों को उनके गांव में ही राजेगार मिल रहा था, लेकिन बीते तीन-चार सालों में स्थिति खराब हुई है. अब तो शायद ही कोई हो जिसे सौ दिनों का रोजगार मिल रहा हो. सरकार भी इसे सुदृढ करने की जगह कमजोर करती जा रही है.' भुगतान में इस देरी के कारण 9.2 करोड़ से अधिक सक्रिय श्रमिकों को उनकी मजदूरी समय पर मिलने की संभावना नहीं है और देरी से भुगतान वाली मजदूरी की रकम करीब 3,066 करोड़ रुपए है. गौर करने वाली बात यह है कि नियमानुसार मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के भीतर श्रमिकों को भुगतान करना अनिवार्य है. ऐसा नहीं होने पर मजदूर प्रति दिन के हिसाब से हर्जाना मांग सकते हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार, 2016-17 के दौरान केवल हर्जाने की राशि लगभग 516 करोड़ थी. हैरान करने वाली बात यह है कि जनवरी 2017 तक इसमें से मात्र 6 फीसदी के भुगतान को स्वीकृति मिली है.

इन सबके बावजूद सरकार इस योजना को लेकर आंकड़ों के जरिए अपनी पीठ थपथपाने से बाज नहीं आ रही. 27 अक्टूबर को ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए एक बयान में यह बताने की कोशिश की गई थी कि कैसे सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में मनरेगा के फंड में भारी बढ़ोतरी की है. ग्रामीण विकास मंत्रालय के उस बयान में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि मनरेगा के फंड में 48,000 करोड़ की बढ़ोतरी ऐतिहासिक है. लेकिन आंकड़ों के खेल को समझें, तो पता चलता है कि फंड में हुई बढ़ोतरी से ज्यादा पिछले साल का एस्टिर ही था. कहा जाता है कि किसी भी पहल की सफलता का पता परिणाम से चलता है. इस बढ़ोतरी का हश्र यह है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत कामगारों की दिहाड़ी में अब तक का सबसे कम इजाफा हुआ है. ठीक एक साल पहले ही 2016-17 में यह बढ़ोतरी 5.7 फीसदी थी, लेकिन 2017-18 में यह मात्र 2.7 फीसदी है. यह हास्यास्पद है कि अप्रैल 2017 के बाद यूपी, बिहार, असम और उत्तराखंड में मनरेगा कामगारों की मजदूरी में सिर्फ एक रुपए की वृद्धि हुई है. वहीं ओड़ीशा में दो रुपये और पश्चिम बंगाल में चार रुपए मजदूरी बढ़ाई गई है. बेतहासा बढ़ रही महंगाई के इस दौर में मजदूरी बढ़ोतरी के ये आंकड़े मनरेगा कर्मियों के लिए किसी मजाक से कम नहीं हैं. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपने उस बयान में यह भी दावा किया था कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और जम्मू-कश्मीर से जुड़े मनरेगा के प्रस्तावों पर तुरंत कार्रवाई की गई है. लेकिन सरकार के आंकड़े ही इस दावे की पोल खोलते हैं. मनरेगा की वेबसाइट पर दिए गए स्टेट फैक्ट शीट (बॉक्स देखें) में बताया गया है कि 11 सितम्बर के बाद से उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का भुगतान बंद है. वहीं छत्तीसगढ़ को 12 सितम्बर और राजस्थान को 14 सितम्बर के बाद से फंड नहीं दिया गया है. सरकार जिन राज्यों के प्रस्तावों पर कार्रवाई की बात कह रही है, उनमें से मध्य प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है, जिसे अक्टूबर में अंतिम भुगतान किया गया है. ■

19 राज्य जिन्हें पिछले कई महीनों से केंद्र मनरेगा के फंड का भुगतान नहीं कर रहा है:

राज्य	जब से भुगतान नहीं हो रहा	सक्रिय कामगार (मिलियन में)
हरियाणा	31 अगस्त 2017	2.07
आसाम	6 सितम्बर 2017	0.66
कर्नाटक	7 सितम्बर 2017	6.22
पश्चिम बंगाल	7 सितम्बर 2017	13.79
पंजाब	11 सितम्बर 2017	1.02
तमिलनाडु	11 सितम्बर 2017	8.67
उत्तर प्रदेश	11 सितम्बर 2017	9.31
छत्तीसगढ़	12 सितम्बर 2017	4.91
राजस्थान	14 सितम्बर 2017	7.45
झारखंड	15 सितम्बर 2017	2.6
केरल	18 सितम्बर 2017	2.17
ओड़ीशा	18 सितम्बर 2017	5.1
हिमाचल प्रदेश	9 सितम्बर 2017	1
उत्तराखंड	2 अक्टूबर 2017	0.93
बिहार	3 अक्टूबर 2017	3.52
त्रिपुरा	6 अक्टूबर 2017	1.03
गुजरात	7 अक्टूबर 2017	5.57
मध्य प्रदेश	7 अक्टूबर 2017	8.81
महाराष्ट्र	7 अक्टूबर 2017	7.47

साभार : मनरेगा वेबसाइट

feedback@chauthiduniya.com

चित्रकूट में कांग्रेस की जीत के मायने

रूपेश गुप्ता

अपने पारंपरिक विधानसभा चित्रकूट में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने भारी जीत दर्ज की है. यह सीट कांग्रेस के विधायक स्व. प्रेम सिंह की मौत के बाद खाली हुई थी. यह कांग्रेस की बेहद मजबूत सीट मानी जाती है. 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की लहर के बावजूद कांग्रेस को यहां 10 हज़ार से ज़्यादा वोटों से जीत मिली थी. उस चुनाव के मुकाबले जीत का यह अंतर करीब डेढ़ गुना ज्यादा है. कांग्रेस यहां से 14 हज़ार से ज्यादा वोटों से जीती है. पिछले चुनाव के मुकाबले इस इस बार बढ़े हुए 4 हज़ार वोटों में कई सियासी संकेत छिपे हैं, जिन्हें समझना ज़रूरी है.

चुनाव परिणाम के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार चौहान ने कहा कि यह कांग्रेस की परंपरागत सीट है और कांग्रेस इस सीट से आगे भी जीतेगी. इस बयान से यही लगता है कि भाजपा मानती है कि यहां कांग्रेस को परास्त नहीं किया जा सकता. लेकिन बात अगर इतनी सी है, तो जीत का अंतर क्यों बढ़ा? इसके लिए तो फिर यह भी दलील दी जा सकती है कि चूंकि वहां के विधायक की मृत्यु हो गई थी, इसलिए सहानुभूति में ज्यादा लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया. इन दोनों दलीलों को मान लिया जाए, तो पहला सवाल यही खड़ा होता है कि जब पहले से पता था कि सीट कांग्रेस की है, तो फिर भाजपा ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रचार में उतारकर उनकी फज़ीहत क्यों कराई. शिवराज सिंह चौहान ने यहां आदिवासी के घर रात बिताया और योगी आदित्यनाथ तो प्रचार के लिए दो-दो बार आए. वहीं मध्यप्रदेश के कई मंत्रियों ने विधानसभा चुनाव के दौरान यहां लगातार डेरा-डंडा जमाए रखा था. भाजपा के लिए फजीहत की बात तो यह रही कि शिवराज के ससुराल और जहां उन्होंने रात गुजारी उस गांव में भी भाजपा को कांग्रेस से बहुत कम वोट मिली. यह शिकस्त और बड़ी होती, अगर आखिरी दौर में भाजपा उम्मीदवार ने वोटों के अंतर को न पाटा होता.

इसे समझना जरूरी है कि उपचुनाव में विरोधी दल के बड़े अंतर से जीतने के मायने क्या हैं. यह बताने की बात नहीं है कि उपचुनाव में सत्ताधारी पार्टी की ओर से सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि पूरी सरकारी मशीनरी चुनाव लड़ती है. ऐसे में कोई विरोधी दल उपचुनाव तभी जीत सकता है, जब जनता पूरी तरह से सरकार के खिलाफ खड़ी हो. तो क्या यह माना जाय कि चित्रकोट का चुनाव एक संकेत है. अगर संकेत है, तो किसके खिलाफ, शिवराज सरकार के खिलाफ या फिर केंद्र की भाजपा की सरकार. अगर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो संकेत राज्य सरकार के खिलाफ है, क्योंकि इससे पहले पूरा ज़ोर लगाने के बाद भी भाजपा अटेर उपचुनाव हार गई थी. भले ही उस जीत का अंतर 1 हज़ार से कम था, लेकिन हार तो हार होती है, वो भी उपचुनाव में सत्ताधारी पार्टी की हार. हालांकि चित्रकोट का उपचुनाव हारने से भाजपा की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. लेकिन इस जीत से कांग्रेस का मनोबल कई गुना बढ़ गया है. इस जीत ने गुजरात में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए टॉनिक का काम किया है. इसका सबसे बड़ा फायदा हाल में होने वाले गुजरात विधानसभा उपचुनाव में दिख रहा है. जहां कार्यकर्ताओं को यकीन हो चला है कि वे भाजपा को हरा सकते हैं. ये वाकई कांग्रेस के लिए उस प्रदेश में चमत्कार है, जहां पार्टी का संगठन खत्म हो गया था.

इस उपचुनाव परिणाम के आइने में हाल के अन्य उपचुनावों के परिणाम भी देखते चलें. इस चुनाव से पहले पंजाब में भाजपा गुरुदासपुर लोकसभा उपचुनाव बुरी तरह हार गई. यह सीट बीजेपी की परंपरागत सीट थी. चूंकि भाजपा सांसद विनोद खन्ना की मौत के बाद यहां चुनाव हुआ था. इसलिए सहानुभूति भाजपा के साथ थी. लेकिन फिर भी भाजपा यहां बुरी तरह से हार गई. दरअसल, इस वक्त देश में जो मुद्दे सियासी तौर पर हावी हैं, वो मुद्दे सरकार के नहीं बल्कि विपक्ष के हैं. जीएसटी, खराब आर्थिक हालात और नोटबंदी जैसे मुद्दों पर सरकार असहज है. भाजपा दावा कर रही है कि इन मुद्दों से लोगों का और देश का फायदा हुआ है. सरकार को गुमान हो चला है कि वो जो कहेगी, जनता उसे ही मानेगी. ऐसा सोचकर सरकार जनमानस की भावनाओं को पकड़ने में असफल हो रही है. सरकार के जिस कदम से जनता को परेशानियां हो रही हैं, उन कदमों का महिमामंडन करके सरकार जनता के ज़ख्मों पर नमक छिड़क रही है. यही कारण है कि कांग्रेस जनता को आवाज देकर उसके करीब आ रही है. इन उपचुनावों के ज़रिए जनता ने यह संदेश दिया है. इस संदेश को न समझकर अगर भाजपा यह मानती है कि चूंकि यह कांग्रेस की परंपरागत सीट है, इसलिए वो चुनाव हार गए, तो यह बात भाजपा के लिए बेदह खतरनाक है.

अगर खुदा ना खास्ता कांग्रेस गुजरात विधानसभा चुनाव जीत गई, तो इसका स्वाभाविक असर कर्नाटक में दिखेगा. इसके बाद अगले साल राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इन तीनों राज्यों में माहौल भाजपा के पक्ष में उस तरह से नहीं दिख रहा है, जैसा 2013 के चुनाव से पहले दिख रहा था. हालांकि इन राज्यों के चुनाव में अभी एक साल का वक्त बाकी है और यह समय कांग्रेस के लिए माहौल बनाने में काफी मददगार साबित होगा. वर्तमान स्थिति तो यही है कि चित्रकूट उपचुनाव में जीत ने कांग्रेस को लड़ने की ताकत दे दी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

ज़हर बनता पानी, शोर बनते शहर और गैस चैम्बर बनता देश

इस वर्ष भी प्रदूषण पर बहस उस समय शुरू हुई जब दिल्ली के आसमान को धुंओं की चादर (जिसे स्मॉग कहा गया) ने ढक लिया. लोगों की सांसें उखड़ने लगीं और आंखें जलने लगीं. दिल्ली सरकार ने एक बार भी ऑड-इवेन का राग अलापा, लेकिन दफ्तरी अड़चनों के कारण बात आगे न बढ़ सकी. हालत की गंभीरता को देखते हुए स्कूल बंद रखने के आदेश दे दिए गए. जो दिल्ली छोड़ सकते थे, वे छोड़ कर जाने लगे. दिल्ली स्थित कई दूतावासों ने अपने गैरज़रूरी स्टाफ को सिंगापुर भेज दिया. कोस्टा रिका के राजदूत को दिल्ली छोड़ बंगलौर में शरण लेनी पड़ी.

शफीक आलम

यह एक दस्तूर सा बन गया है कि जब उत्तर भारत में जाड़े का मौसम दस्तक देता है, तो दिल्ली में प्रदूषण पर बहस शुरू हो जाती है. पहले दीवाली के पटाखों को लेकर और बाद में आसपास के इलाकों में धान के पुआल जलाने के कारण उठे धुओं को लेकर. लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ दिल्ली ही भारत का एक मात्र शहर है, जहां प्रदूषण की ये स्थिति है? क्या देश के दूसरे शहरों की सुध लेने वाला कोई है? उन गांवों का क्या जहां तक मीडिया की नज़र नहीं पहुंचती? प्रदूषण के जो दूसरे प्रकार हैं उनपर बहस और उनका निदान कौन करेगा? अब रिपोर्ट्स आने लगीं हैं कि भारत में वर्ष दर वर्ष न केवल प्रदूषण स्तर में वृद्धि हो रही है बल्कि प्रदूषणजनित रोगों से मरने वालों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है.

फिलहाल बात दिल्ली से शुरू करते हैं. यहां इस वर्ष भी प्रदूषण पर बहस उस समय शुरू हुई जब दिल्ली के आसमान को धुंओं की चादर (जिसे स्मॉग कहा गया) ने ढक लिया. लोगों की सांसें उखड़ने लगीं और आंखें जलने लगीं. दिल्ली सरकार ने एक बार फिर ऑड-इवेन का राग अलापा. लेकिन दफ्तरी अड़चनों के कारण बात आगे न बढ़ सकी. हालात की गंभीरता को देखते हुए स्कूल बंद रखने के आदेश दे दिए गए. जो दिल्ली छोड़ सकते थे वे छोड़ कर जाने लगे. दिल्ली स्थित कई दूतावासों ने अपने गैरज़रूरी स्टाफ को सिंगापुर भेज दिया. कोस्टा रिका के राजदूत को दिल्ली छोड़ बंगलौर में शरण लेनी पड़ी. शायद ऐसे ही हालात के लिए शायर ने यह शेर लिखा था- सीने में जलन आंखों में तूफ़ान सा क्यों है/इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है. इसमें कोई शक नहीं कि स्मॉग के कारण दिल्ली का हर शख्स परेशान था. धुंध के कारण कई सड़क दुर्घटनाएं हुईं, रेल और हवाई यातायात बाधित हुआ.

दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य शहरों के वायु गुणवत्ता सूचकांक (एयर क्वालिटी इंडेक्स) के आंकड़े डब्लूएचओ द्वारा निर्धारित 60 यूनिट से कम पीएम-10 की सुरक्षित सीमा से कई गुना अधिक हो गए हैं. उदाहरण के लिए, उत्तर भारत के कुछ शहरों के प्रदूषण स्तर पर एक नज़र डालें, तो कई शहर ऐसे हैं जहां की स्थिति दिल्ली से भी खतरनाक है. 16 नवम्बर को दिल्ली और उत्तर भारत के कुछ शहरों का एअर क्वालिटी इंडेक्स इस प्रकार है: दिल्ली (198.7), गुरुग्राम (187.6), नोएडा (255.9), फरीदाबाद (291), ग़ाज़ियाबाद (286.6), मुरादाबाद (291.9), लखनऊ (217.6), आगरा (185.5). ये आंकड़े साबित करते हैं कि उत्तर भारत का प्रदूषण स्तर डब्लूएचओ के सुरक्षित सीमा से इतना अधिक हो गया है कि यदि इन्हें गैस चैम्बर कहा जाए तो अतिश्योक्ति नहीं होगी. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, दिल्ली का एक्यूआई आमतौर पर 300 से 400 के बीच रहता है और कभी-कभी 440 के स्तर तक पहुंच जाता है.

दुनिया और भारत

इस वर्ष के शुरू में प्रकाशित ग्रीनपीस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले पांच वर्षों में भारत में वायु प्रदूषण का स्तर 13 प्रतिशत बढ़ा है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, चीन के बड़े शहर जो हमेशा धुंध में डूबे रहते थे, वहां वर्ष 2010 से 2015 तक प्रदूषण स्तर में 17 प्रतिशत की गिरावट आई है. दुनिया में सबसे अधिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन करने वाले देश अमेरिका में भी पिछले पांच वर्षों के दौरान वायु प्रदूषण स्तर में 15 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जबकि यूरोपीय यूनियन में वर्ष 2005 और 2013 के दौरान 20 प्रतिशत की कमी देखी गई. इन देशों में प्रदूषण के स्तर यूं ही में सुधार नहीं हो गया, बल्कि इसके लिए काफी प्रयास किए गए. इस मामले में भारत के पिछड़ने का एक कारण मॉनिटरिंग व्यवस्था की कमी भी है. वर्ष 2016 तक भारत के 23 शहरों में केवल 39 प्रदूषण मॉनिटरिंग स्टेशन थे, जबकि चीन के 900 शहरों और कस्बों में 1500 मॉनिटरिंग स्टेशन हैं. अमेरिका के 450 शहरों में 770 मॉनिटरिंग स्टेशन हैं, जबकि यूरोपीय यूनियन के 400 शहरों में 1000 मॉनिटरिंग स्टेशन काम कर रहे हैं. इस पृष्ठभूमि में यह समझना मुश्किल नहीं है कि क्यों भारत अपने वायु गुणवत्ता सुधार के लिए अपने ही द्वारा स्थापित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका, जबकि चीन जिसके शहर बीजिंग को वायु प्रदूषण की राजधानी कहा जाता था, वो अपने वायु की गुणवत्ता में व्यापक सुधार की ओर अग्रसर है. भारत के अधिकतर शहर राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानक (एनएएक्यूएस) के लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल हैं.

शेनज़ेन कैसे बन गया साफ-सुथरा शहर

चीन वायु प्रदूषण से बहुत ज्यादा पीड़ित देशों में से है. इसने अपने शहरों से कार्बन कम करने की कवायद शुरू की. इसी कड़ी में शेनजेन शहर को लो कार्बन सिटी बनाया जा रहा है. शेनज़ेन की स्थिति बेहतर हुई है. अधिकारियों के मुताबिक, यहां 50 फ़ीसदी तक वायु प्रदूषण कम करने में कामयाबी मिली है. शेनज़ेन हांगकांग की सीमा पर बसा शहर है, इसकी आबादी 1.1 करोड़ है. यह देश का तेज़ी से बढ़ता शहर है. यहां दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट भी मौजूद है. इस पोर्ट पर सैकड़ों क्रेन समुद्री जहाजों पर माल को लादते-उतारते हैं. जब इस बंदरगाह में कोई डीजल इंधन से चलने वाला जहाज प्रवेश करता है, तो अपने इंजन बंद कर देता है, उसकी जगह उसे बंदरगाह से चलने वाले क्लीन इलेक्ट्रोसिटी केबल के जरिए ऊर्जा मिलने लगती है. इसी तरह से शहर के अंदर इलेक्ट्रिक बसें और टैक्सियां चलाई जा रही हैं, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग इकाईयों को बंद किया गया है. लेकिन सबसे प्रभावी क़दम, वायु की गुणवत्ता को लेकर बनाए गए सख़्त क़ानून का बनाया जाना है. क़ानून का उल्लघन करने वालों को कड़ी सजा मिलती हैं. यहां औद्योगिक इकाईयों से निकलने वाले प्रदूषण के आंकड़ों की निगरानी होती है. ■

ज़हर बनता पानी और शोर बनते शहर

दिल्ली में आई धुंध ने और उसके कारण वायु प्रदूषण स्तर ने समाचार पत्रों और टीवी चैनलों में सुर्खियां बटोर ली, लेकिन वायु प्रदूषण के साथ-साथ जल प्रदूषण की स्थित भी कम ख़तरनाक नहीं है. वाटर ऐड की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का 80 प्रतिशत सरफेस वाटर खतरनाक हद तक प्रदूषित हो चुका है. चौथी दुनिया ने नमामि गंगे और गंगा नदी के प्रदूषण पर कई रिपोर्ट्स प्रकाशित की है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, 75 से 80 प्रतिशत जल प्रदूषण का कारण घरों से निकलने वाले सीवरेज के दूषित पानी का जल के साधनों में बे-रोक-टोक मिलना है. इसके कारण वेक्टर जनित बीमारियों जैसे कॉलरा, हैजा, जौंडिस आदि रोगों के मामले बढ़े हैं. ध्वनि प्रदूषण का भी हाल कुछ ठीक नहीं है. अभी हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने राज्यसभा को बताया कि देश के 7 शहरों में ध्वनि प्रदूषण स्वीकार्य सीमा से ऊपर चला गया है. इन शहरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु, लखनऊ, हैदराबाद शामिल हैं. इस प्रदूषण का व्यापक प्रभाव पर्यावरण पर तो पड़ ही रहा है, इंसान को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है.

प्रदूषण की मार

मेडिकल जर्नल लांसेट द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक, भारत के कुल मरीजों में से 6 प्रतिशत मरीज़ वायु प्रदूषणजनित रोगों से ग्रसित हैं. हालांकि वर्ष 1990 और 2016 के बीच वायु प्रदूषण जनित रोगियों की संख्या में गिरावट आई है, लेकिन इसका कारण घरों में इस्तेमाल होने वाले इंधन का बदलाव है, जिसकी वजह से यह कमी आई है. इस अध्ययन के मुताबिक, बाहरी प्रदूषण के कारण होने वाले रोगों से सबसे अधिक प्रभावित उत्तर भारत के राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल हैं. प्रदूषण जनित रोगों के कारण हुई मौत के मामले में भारत दुनिया के 188 देशों में पांचवें स्थान पर है. लांसेट के अध्ययन के अनुसार, 2015 में दुनियाभर में 90 लाख लोग प्रदूषण जनित रोगों के कारण मारे गए, इनमें 28 प्रतिशत लोगों का सम्बन्ध भारत से था. ज़ाहिर है ये आंकड़े बहुत गंभीर संकेत दे रहे हैं. अगर त्वरित रूप से इन पर काबू नहीं पाया गया, तो और अधिक भयानक परिणाम सामने आ सकते हैं.

समस्या का निदान कितना आसान

दिल्ली में स्मॉग के आक्रमण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने हेलीकॉप्टर द्वारा पानी के छिड़काव से लेकर ऑड-ईवन जैसे उपायों पर विचार किया और कर रही है. चूंकि दिल्ली देश की राजधानी है और देश के सभी बड़े टीवी चैनल्स यहीं से ख़बरें प्रसारित करते हैं, इसलिए सबकी नज़रें यहां जमी हुई हैं. लेकिन जैसा कि आंकड़े ज़ाहिर करते हैं, वायु प्रदूषण के मामले में भारत के कई शहर दिल्ली से भी आगे हैं. ज़ाहिर है, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया है. बहारहाल, विश्व के अधिक प्रदूषण वाले देशों ने कुछ उपाए कर अपना प्रदूषण रोकने में कामयाबी हासिल की है. प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सबसे पहले अधिक से अधिक शहरों में मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित करना चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रदूषण की स्थिति क्या है. इसके अलावा दुनिया के दूसरे देशों में मल्टी-फंक्शन डस्ट सेप्रेशन ट्रक, वेंटिलेटर कॉरिडोर, स्मॉग पुलिस, कोयले की खपत में कमी, यातायात नियंत्रण (जैसे ऑड-ईवन का तरीका और पार्किंग में कमी, आदि), सार्वजनिक परिवहन बेहतर करना, आदि शामिल हैं.

ज़ाहिर है कि प्रदूषण एक बड़ी समस्या है. प्रदूषण केवल वायु प्रदूषण नहीं होता है. दुनिया के बड़े और विकसित देशों, जहां प्रदूषण एक बड़ी समस्या थी, ने यदि प्रदूषण पर काबू पा लिया है, तो कोई वजह नहीं कि भारत में वैसा नहीं हो सकता. लेकिन भारत में समस्या यह है कि एक तो यहां जनता में जागरूकता का आभाव है, वहीं सरकारें भी बस खानापूरी ही करती हैं. नमामि गंगे और स्वच्छ भारत अभियान इसके जवलंत उदहारण हैं. करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कहानी वहीं की वहीं रुकी हुई है. इसलिए ज़रूरी है कि सरकारी कोशिशों के साथ-साथ लोगों को भी जागरूक किया जाए कि वे अपने परिवेश को साफ़ सुथरा रखें और सरकार पर भी उसे साफ़ रखने के लिए दबाव बनाएं.■

पर्यावरण संरक्षण के आसान उपाय

पर्यावरण संरक्षण का अर्थ विकास ही समझा जाना चाहिए और इस कार्य में ग्रामीण तथा शहरी सभी लोगों को सक्रिय होकर हिस्सा लेना चाहिए. भारतीय संस्कृति में वनों के महत्व को समझते हुए उनके संरक्षण को उचित मान्यता दी गई है. जनसाधारण को प्रदूषण से उत्पन्न ख़तरों से अवगत कराया जाना चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पर प्रदूषण कम से कम करने का हर सम्भव प्रयास ईमानदारी से करे. विस्तृत पैमाने पर उचित वृक्षारोपण कर प्रदूषण को कम किया जा सकता है. इसके लिए सरकार को चाहिए कि वह जगह-जगह कुछ ऐसी भूमि की व्यवस्था करे, जहां पर व्यक्ति अपने नाम से, यादगार व स्वास्थ्य के लिए कम से कम एक वृक्ष लगा सके. जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कर प्रदूषण को काफी हद तक कम किया जा सकता है. प्रदूषण से बचने के लिए यह आवश्यक है कि किसी भी परियोजना को तैयार किए जाने के समय ही पर्यावरण से सम्बंधित मसलों पर विचार कर, उन्हें परियोजना में शामिल कर लिया जाए. प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों, कूड़े-कचरे व अवांछित पदार्थों का नियोजित ढंग से प्रबंध कर तथा विषैले रसायनों का प्रचलन रोक कर किया जा सकता है.■

वार्ता से पहले कश्मीरियों का विश्वास जीतिए

सच्चाई है कि पिछले सात दशकों के दौरान जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खोखला करने के लिए जितने भी संविधान संशोधन हुए, वो सब कांग्रेस के कार्यकाल में हुए. 2010 में गठित की गई वार्ताकारों की टीम के सदस्य राधा कुमार ने हाल ही में कहा है कि अगर यूपीए सरकार ने उनकी रिपोर्ट को रद्द नहीं किया होता, तो कश्मीर में 2016 जैसे विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिलते.

हारून रेशी

कश्मीर में अलग अलग हितधारकों के साथ बातचीत करने के लिए केन्द्र की तरफ से भेजे गए वार्ताकार दिनेश्वर शर्मा ने जम्मू–कश्मीर में अपना पहला दौरा पूरा कर लिया है. वे तीन दिन तक श्रीनगर में रहे और दो दिन तक जम्मू में. यहां उन्होंने अलग–अलग विचारधारा के 85 प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की. अपना दौरा खत्म कर दिल्ली वापस लौटते हुए उन्होंने कहा कि लोगों के साथ उनकी बातचीत सार्थक रही. उन्होंने कहा कि वे लगातार राज्य का दौरा करेंगे और हुर्रियत के नेताओं से मिलने की कोशिश करेंगे. गौरतलब है कि हुर्रियत नेताओं, खासतौर से सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाईज़ उमर फारूक और यासिन मलिक ने साफ तौर पर उनसे मिलने से इंकार कर दिया. इन हुर्रियत नेताओं ने बातचीत की इस प्रक्रिया को वक्त की बर्बादी करार दिया.

पूर्व के वार्ताकार और उनकी रिपोर्ट्स

हकीकत यह है कि पिछले दो दशकों के दौरान केन्द्र ने जम्मू–कश्मीर में जितने भी वार्ताकार भेजे उनकी रिपोर्ट्स हमेशा बेनतीजा साबित हुईं. कश्मीर में सरकार की तरफ से वार्ताकारों को नियुक्त करने का सिलसिला 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में शुरू हुआ था. वाजपेयी ने योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष केसी पंत को वार्ताकार की हैसियत से कश्मीर भेजा था. पंत यहां कई महीनों तक अलग–अलग राजनीतिक दलों, स्वयंसेवी संगठनों, व्यापारियों और मजहबी नेताओं से मिलकर बातचीत करते रहे. उसके

बाद सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में उन्होंने अन्य बातों के अलावा जम्मू–कश्मीर को व्यापक स्वायतता देने की भी बात कही थी. सुरक्षा बलों की कार्रवाई के दौरान मानवाधिकार पर खास ध्यान देने की भी सिफारिश उन्होंने की थी. लेकिन उनकी सिफारिशों पर कोई अमल नहीं हुआ.

इसके एक साल बाद वाजपेयी सरकार ने ही जम्मू–कश्मीर को विशेष अधिकार दिए जाने की संभावना पर विचार करने के लिए तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी. उसी साल राम जेठमलानी की अध्यक्षता में भी कश्मीर कमेटी के नाम से एक समिति गठित की गई थी. उस आठ सदस्यीय समिति में मशहूर वकील अशोक भान, पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण, विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी वी के ग्रोवर, पत्रकार एम जे अकबर और दिलीप पडगांवकर शामिल थे. इस समिति ने अलगाववादियों से कई दौर की बातचीत के बाद अपनी सिफारिशें केन्द्र सरकार को पेश की. उस समिति को बातचीत के दौरान शायद यह अहसास हुआ था कि अलगाववादी विधानसभा चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं. लिहाजा उन्होंने केन्द्र को मशविरा दिया कि 2002 के विधानसभा चुनाव को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए. लेकिन केन्द्र सरकार ने इस समिति की सिफारिश को रद्द कर दिया.

उसके एक साल बाद यानि 2003 में राज्य के मौजूदा गर्वनर एनएन वोहरा को वार्ताकार बनाकर कश्मीर भेजा गया. उन्होंने भी अलग–अलग वर्ग के लोगों से बातचीत के बाद तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को अपनी रिपोर्ट पेश की. उन्हीं की सिफारिश के बाद 2004 में नई दिल्ली में हुर्रियत नेताओं के साथ बातचीत की गई. हुर्रियत के उदारवादी पक्ष से कई नेता नई दिल्ली में आडवाणी से मिले. इन हुर्रियत नेताओं ने जनवरी 2004 और मार्च 2004 के दौरान कई एनडीए नेताओं से भी मुलाकात की. लेकिन उसी साल हुएआम चुनाव में एनडीए चुनाव हार गई और कांग्रेस वाली यूपीए सरकार सत्ता में आ गई. नए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुर्रियत नेता मीरवाइज़ उमर फारूक की अध्यक्षता में एक हुर्रियत प्रतिनिधिमंडल से मिले. इसी मुलाकात के बाद हुर्रियत ने कश्मीर में हड़ताल न बुलाने की बात मान ली थी. उन्होंने बातचीत की प्रक्रिया को सफलता पूर्वक आगे बढ़ाने के लिए हर तरह के बंदूकों को खामोश करने की अपील की थी. वर्ष 2006 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने श्रीनगर में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई. इस कॉन्फ्रेंस के बाद जम्मू–कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सगीर अहमद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई. उस समिति ने भी कश्मीर को स्वायतता देने की सिफारिश की थी, लेकिन केन्द्र सरकार ने उसपर ध्यान नहीं दिया. साल 2010 में दिलीप पडगांवकर, एमएम अंसारी और राधा कुमार जैसे वार्ताकारों की एक टीम जम्मू–कश्मीर भेजी गई. उस टीम ने जम्मू–कश्मीर में विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्ध रखने वाले 5 हजार प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की और अक्टूबर 2011 में अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंप दी. इस रिपोर्ट में भी जम्मू–कश्मीर को स्वायतता देने की सिफारिश की गई थी. लेकिन यूपीए सरकार ने उस रिपोर्ट को भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पूर्व के वार्ताकारों की रिपोर्ट्स के साथ केन्द्र सरकार के रवैये के कारण नई दिल्ली के प्रति कश्मीरियों के अविश्वास की खाई गहरी हो गई है. पिछले तीन दशकों के दौरान कश्मीर में सिर्फ सरकारी वार्ताकार ही नहीं आए बल्कि निजी और सामूहिक स्तर पर भी बातचीत की कोशिशें हुई हैं. कुलदीप नैयर, जस्टीस तारकंडे, तपन बोस, वजाहत हबीबुल्लाह, यशवंत सिन्हा जैसे लोग यहां आ चुके हैं. लेकिन केन्द्र सरकार ने किसी भी बातचीत की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने की कोशिश नहीं की. ऐसी स्थिति में दिनेश्वर शर्मा के लिए अपनी विश्वसनीयता बनाए रखना और जनता का भरोसा जीतना एक बहुत बड़ी चुनौती है. केवल पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नेताओं एवं कुछ व्यापारिक संगठनों से बातचीत कर दिनेश्वर शर्मा कुछ भी हासिल नहीं कर सकते.■

feedback@chauthiduniya.com

बेवक्त का राग है कांग्रेस की पहल

दिलचस्प बात यह है कि जब केन्द्र सरकार ने दिनेश्वर शर्मा को वार्ताकार की हैसियत से कश्मीर भेजा, तभी कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में जम्मू–कश्मीर के लिए एक पॉलिसी प्लानिंग ग्रुप बनाया. इस ग्रुप में पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम, राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस महासचिव अंबिका सोनी शामिल हैं. इस ग्रुप ने पिछले दो महीनों के दौरान दो बार जम्मू–कश्मीर का दौरा किया और यहां अलग–अलग विचारधारा के लोगों से मुलाकात की. आने वाले दिनों में यह ग्रुप एक बार फिर राज्य का दौरा कर सकता है. कांग्रेस का कहना है कि इस ग्रुप का गठन राज्य की मौजूदा स्थिति को समझने और कश्मीर समस्या के हल की संभावनाओं का जायजा लेने के मकसद से किया गया है. हालांकि विश्लेषकों का साफ कहना है कि कांग्रेस अपने पतन के इस दौर में कश्मीर के बारे में क्या कर पाएगी, जब उसने सत्ता में रहते हुए कुछ नहीं किया.

यह एक अटल सच्चाई है कि पिछले सात दशकों के दौरान जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खोखला करने के लिए जितने भी संविधान संशोधन हुए, वो सब कांग्रेस के कार्यकाल में हुए. 2010 में गठित की गई वार्ताकारों की टीम के सदस्य राधा कुमार ने हाल ही में कहा है कि अगर यूपीए सरकार ने उनकी रिपोर्ट को रद्द नहीं किया होता, तो कश्मीर में 2016 जैसे विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिलते. हालांकि कांग्रेस नेताओं का कश्मीर का दौरा और यहां की स्थिति पर बातचीत करना शायद दिनेश्वर शर्मा की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि कश्मीरी जनता के मन में यह बात बैठ चुकी है कि बातचीत के नाम पर उनके साथ मजाक होता रहा है.

मदरसों में आधुनिक शिक्षा समय की ज़रूरत है

वसीम अहमद

उत्तर प्रदेश सरकार मदरसों में एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना बना रही है. इसके साथ ही इस बात का आश्वासन दे रही है कि धार्मिक पाठ्यक्रम से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और अंग्रेजी व हिन्दी के अलावा तमाम पुस्तकें उर्दू में उपलब्ध कराई जाएंगी. ये योजना एक 40 सदस्यीय कमेटी की सिफारिशों के बाद तैयार की गई है. जाहिर है कि ये योजना मदरसों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मेन स्ट्रीम में लाने के मकसद से बनायी गई है. अगर इस योजना को लागू कर दिया जाता है तो पूरे राज्य में 19143 रजिस्टर मदरसों में से 560 पूर्ण सहायता प्राप्त, 8521 नवीकरण योजना के तहत सहायता पाने वाले मदरसे, जिनमें विज्ञान कंप्यूटर जैसे विषयों की शिक्षा हो रही है. 140 में आईटीआई स्कीम के तहत उद्योग और व्यवसायिक की शिक्षा दी जा रही है और बोर्ड से मान्यता प्राप्त 3867 मदरसे, जहां बोर्ड का पाठ्यक्रम चलता है, को अपने यहां विशेष पाठ्यक्रम के साथ साथ एनसीईआरटी की पुस्तकों को भी शामिल करना होगा. इसके अलावा लगभग 1298 ऐसी मदरसे हैं, जो दारुल उलूम देवबंद या नदवातुल उलमा से संबद्ध है और सरकार के रिकॉर्ड में रजिस्टर नहीं हैं. फिलहाल इन मदरसों में एनसीईआरटी की पुस्तकों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है.

राज्य सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 17 सौ करोड़ रुपए आवंटित किए हैं तथा मान्यता प्राप्त मदरसों और प्राइमरी स्कूलों में आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए 394 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं. सरकार चाहती है कि इस फंड का बेहतर इस्तेमाल करते हुए अल्पसंख्यको में पिछड़े तबके को आधुनिक शिक्षा से जोड़कर उनके पिछड़ेपन को दूर किया जाए. मुख्य रूप से मदरसों के विद्यार्थी, जो धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने में उम्र का एक अच्छा खासा हिस्सा गुजार देते हैं और धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब वो व्यवहारिक दुनिया में कदम रखते हैं तो उनके लिए रोजगार के अवसर सिमटे हुए होते हैं, को आधुनिक शिक्षा दी जाए ताकि उनके सामने अवसरों की कमी न रहे और वो भी दूसरे स्कूलों और कॉलेजों के बच्चों की तरह विभिन्न मैदानों में अपना भविष्य तलाश कर सकें.

सरकार का ये फैसला अपने आप में एक बेहतर कदम है. बेशक मदरसे के विद्यार्थियों को इससे रोजगार की तलाश में राहत मिलेगी. यही कारण है कि उलमा का एक वर्ग, जो मदरसों में आधुनिक शिक्षा का समर्थक हैं और इसकी जरूरत भी महसूस करता है, चाहते हैं कि धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी न सिर्फ एक आलिम बने बल्कि वो सांसारिक ज्ञान लें. मगर इसके साथ ही एक ऐसा ग्रुप भी है, जो इस फैसले का विरोध कर रहा है. इस ग्रुप का मानना है कि मदरसों की स्थापना धार्मिक ज्ञान के उद्देश्य से हुई है. इसलिए इसे आधुनिक ज्ञान विज्ञान से जोड़ना इसके उद्देश्य के खिलाफ होगा. इसके अलावा एक वर्ग ऐसा भी है जो इस फैसला को शक की निगाह से देख रहा है. उसका मानना है कि योगी जैसे हिंदुत्व के अलंबरदार से मुस्लिम बच्चों की कल्याण की उम्मीद नहीं की जा सकती.

अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या योगी सरकार अपने इस योजना को अमलीजामा पहनाने और मदरसों में एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को शामिल करने में सफल हो पाएगी? दरअसल इसमें कुछ अड़चने हैं, जिस पर सरकार को गौर करना होगा. जबतक इन अड़चनों को दूर नहीं किया जाता, ये योजना दूसरे विकास योजना की तरह दफ्तर की शोभा

बनी रहेगी. सबसे पहली दिक्कत यह है कि कमेटी ने अपनी सिफारिश में ये कहा है कि हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा सारे विषय उर्दू में उपलब्ध कराए जाएं. ये एक अच्छी सिफारिश है और सरकार ने इसको माना भी है. मगर सवाल ये पैदा होता है कि सरकार इन विषयों को पढ़ाने वाले उर्दू अध्यापक कहां से लाए? उत्तर प्रदेश में उर्दू शिक्षा बहुत कम है. ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में उर्दू अध्यापकों को तलाशना बहुत मुश्किल काम होगा.

मदरसों में आधुनिक शिक्षा के संबंध में पड़ोसी देश पाकिस्तान के मुफ्ती आजम और दारुल उलूम कराची के संस्थापक मुफ्ती मोहम्मद शफी के लेख से पता चलता है कि मदरसों के पाठ्यक्रम में बदलाव समय का तकाजा है. वो अपनी पुस्तक 'जवाहरुल फिका' में लिखते हैं कि दरस निजामी जो अब तक हमारे मदरसों में प्रचलित है, धार्मिक शिक्षा की हिफाजत व इशाअ के लिए बिलाशुबा काफी है मगर मुल्की, दफ्तरी जरूरतें बिल्कुल बदली हई है. इनमें हमारी कदीम मंतिक व फलसफा और कदीम

रियाजी (कोर्स) और फारसी जुबान काम नहीं देती. अगर आज इस हकीकत को समझकर हमारे उलमा फारसी जुबान की जगह अंग्रेजी को और यूनानी फलसफे की जगह आधुनिक विज्ञान और दर्शन को तरजीह दें तो बेहतर होगा. खतरनाक साधन से परहेज करते हुए अंग्रेजी जुबान और आधुनिक शिक्षा व कला को हासिल किया जाए तो फायदा होगा.

आधुनिक शिक्षा को मदरसों में शामिल करने का रुझान मिस्र की अजहर यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले अपनाया. जामिया अजहर के विभागों को देखें तो अंदाजा होता है कि प्राइमरी से लेकर ऊपर तक आधुनिक शिक्षा का खास तौर से ध्यान रखा गया है. यहां तक कि तफसिरे कुरान में और विषयों के साथ फ्रांसिसी, अंग्रेजी के अलावा यहुदी व ईसाई पुस्तकों के अंश उन्हीं के जुबानों में पढ़ाए जाते हैं. इसी तरह मुस्लिम देश इंडोनेशिया के अंदर भी मदरसों में आधुनिक शिक्षा को आगे बढ़ाने के रुझान में बढ़ोतरी हो रही है. अभी हाल ही में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता की अजहर मस्जिद में मुस्लिम उलमा कौंसिल के सरबराह डायरेक्टर अहमद तैयब ने बयान दिया है कि मदरसों में धार्मिक पुस्तकों के बजाय आधुनिक शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए.

फिलीस्तीन का मामला इस सिलसिले में कुछ अलग है. वहां आधुनिक शिक्षा के तहत इजराइल के द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रम को मदरसों में हराम के दर्जे में रखा जाता है. अभी हाल ही में मस्जिद अक्सा के इमाम और खतीदुल शेख अकरमा सबरी ने अपने एक बयान में कहा है कि जो शख्स यहूदी राज्य के पाठ्यक्रम को फिलीस्तीनी स्कूलों में पढ़ाएगा वो गुनहगार होगा.

सत्ताधारी फिलीस्तीनी तंजीमों फतह और हमास आधुनिक शिक्षा के खिलाफ नहीं हैं. उनका स्टैंड है कि वो अपने तैयार किए हुए ऐसे पाठ्यक्रम के हक में है, जिसमें धार्मिक और आधुनिक विषय शामिल हैं. इन हालात में मुस्लिम मुल्कों में प्रचलित शिक्षा प्रणाली को देखते हुए अगर भारत में मदरसों के विद्यार्थियों के लिए आधुनिक शिक्षा को अनिवार्य करार दिया जा रहा है तो इससे परहेज करने के बजाय संयम का रास्ता अख्तियार करना मुनासिब होगा, ताकि बच्चे जब मदरसों से पढ़ाई करके व्यवहारिक दुनिया में कदम रखें तो उनके सामने रोजगार के अवसर खुले हुए हो.■

feedback@chauthiduniya.com

निजी क्षेत्र में आरक्षण

बात निकली है तो दूर तक जाएगी

सरोज सिंह

इतिहास अपने आप को दोहराने की दहलीज पर है. ऐसा इसलिए कि अब यह नए रंग व ढंग में एक बार फिर हर किसी की जुबान पर चढ़ने लगा है. कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने आउटसोर्सिंग की नौकरियों में आरक्षण की बात कर इस बहस का आगाज किया था. बात बढ़ी, तो इसमें नीतीश कुमार ने निजी क्षेत्र को भी लपेट लिया. ऐसा नहीं है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग कोई नई है. राजनेता गाहे-बगाहे अपनी राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से इसे उठाते रहे हैं. आरक्षण को पचास फीसदी से बढ़ाकर कहीं साठ तो कहीं पैंसठ फीसदी करने की कवायद भी होती रही है. शुक्र मनाइए अदालतों का, जिसने बार-बार राजनेताओं को यह अहसास दिलाया कि सीमा मत लांघिए. लेकिन सत्ता और इससे जुड़े खेल इतने निराले हैं कि कुछ दिनों में नेता अदालतों के आदेश को भूल जाते हैं और एक नया अध्यादेश लाकर अपना वोट बैंक बढ़ाने की कवायद में जुट जाते हैं.

इस बार आगाज नीतीश कुमार ने किया है. चर्चा है कि नई सरकार की चाल-ढाल कुछ ठीक नहीं है. भाजपा और जदयू की नई दोस्ती का रंग उस तरह चढ़ नहीं रहा है जैसा पिछली बार चढ़ा था. वजह क्या है इस पर विश्लेषण जारी है, लेकिन इतना कहा ही जा सकता है कि नीतीश कुमार पहले की तरह इस बार बहुत कम्फर्टेबल नहीं लग रहे हैं. जानकार बताते हैं कि अपनी इसी बैचेनी को दूर करने के लिए उन्होंने आरक्षण का तीर चलाना शुरू किया है. पहला तीर आउटसोर्सिंग का छोड़ा गया. नीतीश कुमार ने साफ कहा कि आउटसोर्सिंग की नौकरियों में भी तो पैसा सरकार का ही लगता है, इसलिए इसमें भी आरक्षण के प्रावधान लागू होने चाहिए. नीतीश कुमार के इस तीर से कई घायल हुए और पहली प्रतिक्रिया सी पी ठाकुर की आई. उन्होंने कहा यह ठीक नहीं है. ऐसा होगा तो फिर रोड पर चलने पर भी आरक्षण लागू कर देना चाहिए. भाजपा के युवा कार्यकर्ताओं ने कई स्थानों पर इसे लेकर विरोध जताया और इसे वापस लेने की मांग की. कई स्थानों पर अब धीरे-धीरे निजी हैसियत से भी नेता लोग आरक्षण की इस आग को सुलगाने में लग गए हैं. आउटसोर्सिंग से बात आगे निकली, तो इसके बाद नीतीश कुमार ने राय दी कि निजी क्षेत्र में आरक्षण को लागू कर देना चाहिए. नीतीश कुमार के इस बयान पर पहली प्रतिक्रिया लालू प्रसाद की आई. उन्होंने कहा कि जब बिहार में निजी क्षेत्र में कोई कल कारखाने हैं ही नहीं, तो नीतीश कुमार आरक्षण कहां लागू करेंगे. लालू ने कहा कि दरअसल नीतीश कुमार भाजपा की जाल में फंस चुके हैं और जनता को बेमतलब के मुद्दे में उलझा देना चाहते हैं. कहा गया कि अगर सही मन है, तो फिर इसमें बहस की जरुरत कहां है. केंद्र में एनडीए की सरकार है, जिसके साथ नीतीश की पार्टी का गठबंधन है. इस पर चर्चा अभी गर्म ही हो रही थी कि नीतीश कुमार ने महिला आरक्षण का तीर चला दिया.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश किया जाना चाहिए. जदयू अपनी सीमित ताकत में भी इसका समर्थन करेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस समय शरद यादव जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस समय भी राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक का हमारी पार्टी ने समर्थन किया था. इस बिल को अब लोकसभा में पेश किया जाना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों को यह भ्रम रहता है कि महिला आरक्षण बिल में पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान नहीं होने पर वंचित तबके के साथ भेदभाव होगा. बिहार में हमारी सरकार ने वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं में और वर्ष 2007 में नगर निकायों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण दिया था. इससे सभी वर्ग की महिलाओं को लाभ मिल रहा है. पिछड़ी जाति की महिलाओं को भी इसका लाभ मिल रहा है. यह नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

नीतीश कुमार का मानना है कि गुजरात में पाटीदार समुदाय द्वारा आरक्षण की मांग कृषि संकट से जुड़ा मुद्दा है. न सिर्फ पाटीदार बल्कि जाट, मराठा और अन्य समुदाय जो कृषि से जुड़े हुए हैं, हम उनके आरक्षण की मांग का समर्थन करते हैं. इसका पॉलिटिकल लेना देना नहीं है.

नीतीश कुमार का मानना है कि गुजरात में पाटीदार समुदाय द्वारा आरक्षण की मांग कृषि संकट से जुड़ा मुद्दा है. न सिर्फ पाटीदार बल्कि जाट, मराठा और अन्य समुदाय जो कृषि से जुड़े हुए हैं, हम उनके आरक्षण की मांग का समर्थन करते हैं. इसका पॉलिटिकल लेना देना नहीं है. नीतीश कुमार कहते हैं कि आउटसोर्सिंग के जरिए सरकार अपने काम के लिए लोगों को बहाल कर रही है. इसके लिए राजकोष से कंपनी को धन मुहैया कराया जाता है. स्वाभाविक है कि सरकारी धन के उपयोग पर रिजर्वेशन एक्ट को मानना पड़ेगा, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो या आउटसोर्स, दोनों में आरक्षण लागू करना पड़ेगा. दरअसल नीतीश कुमार के आरक्षण को लेकर ताबड़तोड़ बयानों ने राजनीतिक गलियारों में गर्मी ला दी है.

नीतीश कुमार कहते हैं कि आउटसोर्सिंग के जरिए सरकार अपने काम के लिए लोगों को बहाल कर रही है. इसके लिए राजकोष से कंपनी को धन मुहैया कराया जाता है. स्वाभाविक है कि सरकारी धन के उपयोग पर रिजर्वेशन एक्ट को मानना पड़ेगा. चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो या आउटसोर्स, दोनों में आरक्षण लागू करना पड़ेगा. दरअसल नीतीश कुमार के आरक्षण को लेकर ताबड़तोड़ बयानों ने राजनीतिक गलियारों में गर्मी ला दी है. उनके राजनीतिक विरोधी भी मान रहे हैं कि आरक्षण को लेकर नीतीश अभी सबसे आगे चल रहे हैं. लालू प्रसाद को भी इसका पूरा अहसास है. इसलिए उन्होंने दूसरे तरीके से इस मुद्दे को उठाने का प्रयास शुरू कर दिया है, ताकि नीतीश की जगह पर पूरा लाभ राजद को मिल सके. लालू प्रसाद ने अपनी राजनीतिक बाजीगरी का जौहर दिखाते हुए एक बयान दिया कि कहलगांव में जो तटबंध टूटा, उसके लिए 'भूरे चूहे' जिम्मेदार थे. गौरतलब है कि जिस समय यह घटना हुई थी, उस समय जल संसाधन मंत्री ने यह बयान दिया था कि चूहों ने अंदर की जमीन को खोखला कर दिया था, जिससे तटबंध को नुकसान पहुंचा. ललन सिंह के इस बयान पर इस समय लालू प्रसाद ने पूरी चुटकी ली थी और कहा था कि लगता है अब चूहों पर भी सरकार का वश नहीं रहा. इस घटना के महीनों बाद लालू प्रसाद ने ललन सिंह के इसी बयान को भूरे चूहों से जोड़ दिया. गौरतलब है कि जब आरक्षण का आंदोलन बिहार में चरम पर था, उस समय लालू प्रसाद ने कथित तौर पर 'भूरा बाल साफ करो' का नारा दिया था. उस समय इसे लेकर भारी बवाल हुआ था, पर इसका राजनीतिक फायदा लालू प्रसाद को मिला था. लालू ने एक बार फिर 'भूरे चूहों' की बात कर नीतीश की पूरी पटकथा को ही बदलने की कोशिश की है. इसलिए जदयू ने इसका कड़ा प्रतिकार भी किया है.

राजद-जदयू की ज़ुबानी जंग

प्रदेश जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद ने समाज में फूट डाल कर ही राज किया है. वे कभी लोगों को मिलजुल कर नहीं रहने देते हैं. पहले लालू ने 'भूरा बाल साफ करो' की बात कर समाज को तोड़ा था, अब वे भूरा चूहा की बात कर रहे हैं. लालू ने राजनीति में इससे ज्यादा कुछ सीखा ही नहीं है. वे जब भी बात करेंगे तो मारने-पीटने की ही बात करेंगे. यही सीख वे अपने बच्चों को दे रहे हैं. लेकिन लालू को समझ लेना चाहिए कि उनका दौर कुछ और था, आज का दौर अलग है. बिहार की जनता अब जातिवाद के चक्कर में नहीं पड़ने वाली है. लोग जागरूक हैं और इसका मुंहतोड़ जवाब वर्ष 2019 और 2020 के चुनाव में देंगे. लालू और इनका पूरा कुनबा चारों खाने चित हो जाएगा. लालू को गाली-गलौज में भी महारत हासिल है. इनको पता नहीं है कि घर में कैसे रहा जाता है? जहां इनका पूरा परिवार रहता है वहां भी वे गाली-गलौज ही करते होंगे. इसका असर इनके परिवार पर भी दिखता है. जदयू के दूसरे प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद को राजनीति के भू-पिल्लू ने काट लिया है. इसी वजह से इनके शरीर में खुजली हो रही है. इसका नतीजा इनकी भाषा में दिख रहा है. लालू इतने अधिक बेचैन हैं कि अनाप-शनाप बोलते चले जा रहे हैं. लालू की तकदीर को भू-पिल्लू ने ऐसा काटा है कि आज राजनीतिक कारावास की सजा भुगत रहे हैं. जिस सामाजिक समूह में उन्होंने जन्म लिया है, उसी सामाजिक समूह के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना ही लालू का राजनीतिक कुसंस्कार है. एक सजायाफ्ता, जिसका परिवार दागी हो चुका है, वह बिहार को जातीय उन्माद में झोंकने का प्रयास कर रहा है. जदयू की ऐसी प्रतिक्रिया से साफ है कि लालू का तीर सही निशाने पर लगा है. यह सिलसिला लगता नहीं कि लोकसभा चुनाव से पहले थमेगा. आरक्षण के मुद्दे को लेकर नीतीश ने भी कमर कस ली है और आगामी संसद सत्र में इसे लाने के लिए वह काफी दबाव भी डालने वाले हैं. देखना दिलचस्प होगा कि लालू प्रसाद अब आगे नीतीश कुमार के तीर को कैसे राजनीतिक तौर पर भौथरा करते हैं, लेकिन निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात करके नीतीश कुमार ने एक तीर से कई निशानें साधने की कोशिश की है. नीतीश की यह मांग कल केंद्रीय राजनीति में भी एक अहम मुद्दा बन सकती है, क्योंकि कई दलित एवं पिछड़े समुदाय से आने वाले नेता वक्त वेवक्त निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात उठाते रहे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी
पूरे हफ्ते ख़बरों का ख़ज़ाना
जुड़िए...
Editor's Take
में देश के सबसे निर्भीक पत्रकार संतोष भारतीय से
Fourth Dimension में
छप क्या रहा चौथी दुनिया के नए अंक में
Crime Time में हर दिन अपराध की पड़ताल
हम ख़बरें बनाते ही नहीं दिखाते भी हैं

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

मोदी जी, कांग्रेस से सीखिए लंबे समय तक शासन कैसे करते हैं

कमल मोरारका

www.kamalmorarka.com

एक और संकेत यह है कि गुजरात चुनाव में प्रचार के लिए अचानक प्रधानमंत्री जी की 30 सभाओं की घोषणा कर दी गई है. पहली बात तो गुजरात बहुत छोटा राज्य है. यह दूसरी बात है कि वे वहां के मुख्यमंत्री रहे हैं और यह समृद्ध राज्य है.

गुजरात में चुनाव अभियान जोरों पर है. 22 साल से वहां भाजपा राज कर रही है. नरेन्द्र मोदी, जो वहां के मुख्यमंत्री थे, अब प्रधानमंत्री बन गए हैं और कई राज्य उनके हाथ में आ गए हैं. यह तो कभी सोचा ही नहीं जा सकता था कि गुजरात में कभी कोई कड़ा मुकाबला होगा. सब मान कर चल रहे थे कि केवल उम्मीदवार का चयन करना है, बहुमत आराम से मिल जाएगा. अमित शाह छाती ठोक कर कह रहे थे कि 150 प्लस लाना है. लेकिन तेजी से स्थिति बदल गई, जैसा हर चुनाव में होता है. लोगों का क्या मन है, उनके मन में उत्साह है या निरुत्साह है, वो सब चुनाव अभियान के दौरान मालूम पड़ता है. राहुल गांधी, जिनके बारे में नहीं कहा जा सकता कि वो बहुत प्रभावशाली वक्ता हैं या जो अपने भाषणों से बहुत प्रेरणा देते हैं. गुजरात में उनकी मीटिंग में अचानक इतनी भीड़ आई कि लोगों को आश्चर्य हुआ. सर्वविदित है कि उनकी सभा में आई भीड़ भाजपा की लोकप्रियता का कम होने का संकेत है. जब एंटी इंकमबेंसी होती है, तो नाराज होकर आदमी वहां जाता है, जहां दूसरा ऑप्शन हो. गुजरात में तो ऑप्शन नहीं है. भाजपा और कांग्रेस दो ही विकल्प हैं. इतनी बातें तो सबको दिखेंगी. अब विश्लेषण क्या है? विश्लेषण यह है कि चार बड़े शहरों बड़ौदा, अहमदाबाद, राजकोट और सूरत की जो स्थिति है, वो दिलचस्प है. ये भाजपा के गढ़ थे. अगर यहां भाजपा कमजोर पड़ती है, तो इनको भारी धक्का लग सकता है. अमित शाह और इनकी टीम का पूरा जोर शहरों की तरफ है. चुनाव के दौरान सब पार्टियां अपने अच्छे-अच्छे उम्मीदवार को टिकट देती है. पहले दौर में 89 सीट का चुनाव है और अब भाजपा देख रही है कि उसे कुछ सीटिंग एमएलए का टिकट भी काटना पड़ेगा, क्योंकि वो जीतने की स्थिति में नहीं हैं. इतनी बारीकी से प्रधानमंत्री खुद सब देख रहे है. वे और अमित शाह एक-एक उम्मीदवार का विश्लेषण करने बैठे हैं. इससे साफ हो जाता है कि उनको खुद भी अंदाजा है कि मुकाबला कड़ा हो गया है, जो पहले नहीं के बराबर था.

दूसरा संकेत यह है कि पटेल समुदाय के, दलित समुदाय के और पिछड़ा वर्ग के तीन नौजवानों ने अपना मोर्चा निकाल लिया है और कहा है कि हम भाजपा के विरुद्ध किसी और पार्टी को समर्थन देंगे. हार्दिक पटेल, पटेल समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. वे खुद चुनाव में खड़ा नहीं हो रहे हैं और ना ही कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं. लेकिन पटेल पाटीदारों की सभा में काफी भीड़ हो रही है और वे काफी लोकप्रिय नजर आ रहे हैं. हार्दिक पटेल 24 साल के हैं. उनके खिलाफ भाजपा वालों ने एक वीडियो क्लिप जारी की, जिसमें उनके साथ एक महिला को दिखाया गया है. इससे स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा डरी हुई है. जब पॉलिटिकल पार्टी इस तरह का काम करने लगे तो समझना चाहिए कि वो कहीं न कहीं डरी हुई है. जब पार्टी लोकप्रिय होती है, तो उसे ये सब करने की जरूरत नहीं होती है. इससे ज्यादा आश्चर्य की बात है, सीडी को मिला पब्लिक रिस्पॉन्स. कोई नहीं कह रहा है कि यह सच्ची है या झूठी है, असली है या नकली है. इसकी प्रतिक्रिया वैसी ही है, जैसी वीपी सिंह के समय सेंट किट्स आईलैंड को ले कर आई थी. एक पर्चा जारी कर के बताया गया था कि सेंट किट्स में उनका बैंक अकाउंट है. लोगों को पांच मिनट भी नहीं लगा समझने में कि ये सब वीपी सिंह के खिलाफ साजिश किया गया है. ये पर्चा, ये आरोप बोगस है, झूठा आरोप है. वो मामला वहीं खत्म हो गया. ऐसा ही हाल इस सीडी का होने जा रहा है. हार्दिक पटेल कौन है, मैं नहीं जानता. उसकी विश्वसनीयता क्या है, मैं नहीं जानता. लेकिन गुजरात के लोगों में भाजपा की विश्वसनीयता काफी गिर गई है, ये इस बात से नजर आता है.

एक और संकेत यह है कि गुजरात चुनाव में प्रचार के लिए अचानक प्रधानमंत्री जी की 30 सभाओं की घोषणा कर दी गई है. पहली बात तो गुजरात बहुत छोटा राज्य है. यह दूसरी बात है कि वे वहां के मुख्यमंत्री रहे हैं और यह समृद्ध राज्य है. लेकिन राजनीतिक तौर पर इतना दांव लगाने की जरूरत नहीं है. गुजरात न यूपी है, न बिहार है, न महाराष्ट्र है, न आंध्र प्रदेश है. यहां तो लोकसभा की सीटें भी बहुत कम हैं. लेकिन ये डर रहे हैं कि यदि गुजरात इनके खिलाफ चला गया, तो इससे ये संकेत जाएगा कि 2019 में क्या होगा. ये भी गलत विश्लेषण है. ये सही बात नहीं है कि गुजरात हारने से 2019 में हारेंगे. अगर इनको परिपक्वता दिखानी है कि हम देश में लंबे समय तक राज करने के योग्य हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी थी, तो इन्हें ये छोटी-छोटी हरकतें छोड़नी पड़ेंगी. चिंता छोड़िए, एक राज्य हारा तो हारा. अपनी मर्यादा रखिए. मर्यादा छोड़कर, सारे नियम तोड़कर चुनाव आयोग से चुनाव के तारीख की घोषणा नहीं होने दी और आयोग की विश्वसनीयता गिरा दी. अब ये असमंजस में हैं कि पटेल कहां जाएंगे. क्या करें, न करें. ये स्थिति मोदी जी और अमित शाह जी की खुद पैदा की हुई है. भारत 125 करोड़ लोगों का देश है. इसको अमेरिका और इंग्लैंड की नजर से देखेंगे तो गलत ही नतीजें आएंगे. इज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में थोड़ा सुधार हुआ, तो भाजपा हल्ला करने लगी कि इससे बहुत फायदा हो गया. कैसे फायदा हुआ या कैसे फायदा होगा इसका विश्लेषण नहीं किया गया. रैंकिंग में इसलिए सुधार हुआ, क्योंकि भाजपा सरकार ने दिवालिया घोषित करने का कानून ला दिया. दिवालिया घोषित करना पश्चिम का रिवाज है. यहां दिवालिया बहुत खराब माना जाता है. लेकिन इन्होंने यह बहुत गलत कानून पास किया है. इस देश के मिजाज के हिसाब से यह कानून नहीं है. हालांकि अमेरिकन इससे बहुत खुश हैं कि इंडिया बहुत अच्छी कंट्री हो गई. जिस दिन हमारे ज्यादा उद्योग दिवालिया हो जाएंगे, उस दिन वे भारत को बहुत ऊंचा देश समझेंगे. अमेरिका और इंग्लैंड की नजरों से इंडिया को देखने की गलती कांग्रेस ने कभी नहीं की. ये लोग चाहे जितना कांग्रेस को गाली दें और बोलें कि वे मुसलमानों के पक्ष में और हिन्दुओं के खिलाफ थे, लेकिन ऐसी गलती कांग्रेस ने नहीं की. देश में मुसलमानों के पक्ष में कौन हैं? अगर होते तो मुसलमानों का भला नहीं हो जाता. लेकिन अभी तक क्या हुआ उनका? कांग्रेस ने मुसलमानों का क्या किया? हां, उनके हक, उनके अधिकारों को रक्षा की. ये सब कांग्रेस ने नहीं किया कि कोई बीफ खाए तो उसको मार दो, कोई गाय लेकर जाए तो उसको मार दो. लेकिन मुसलमान इससे समृद्ध नहीं हुए, कोई भला नहीं हुआ उनका. अगर ये सरकार लंबे दौर तक राज करना चाह रही है, तो इन्हें चाहिए कि ये कांग्रेस का अध्ययन करें. लेकिन इनका शॉर्ट व्यू है. इनकी सोच है कि पांच साल राज करेंगे, मुसलमानों को दबा देंगे, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म कर देंगे, आर्मी चीफ को खुला छोड़ देंगे कि रोज सार्वजनिक बयान दें और जज का इस्तेमाल करें. चीफ जस्टिस भी सुप्रीम कोर्ट की गरिमा गिरा रहे हैं. ये सब भाजपा को सूट करता है. मोदी अगर दीपक मिश्रा, विपिन रावत और चुनाव आयोग को मिलाकर देश की ये हालत करना चाहते हैं, तो जरा देखें कि पिछले सप्ताह जिम्बाब्वे में क्या हुआ. वहां 25 साल से एक ही आदमी राज कर रहा था. चुनाव हार कर भी बोल देता था कि मैं जीत गया हूं. वहां की सेना उसको सपोर्ट कर रही थी. पब्लिक से कोई मतलब नहीं था. फिर क्या हुआ? वहां आर्मी तंग आ गई. आर्मी ने प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर लिया. वे अपने घर में कैद हैं. अब आर्मी सोच रही है कि वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना दें. अगर यही करना है तो करिए.

आप सोच रहे हैं कि नेहरू को, नेहरू खानदान को बदनाम करके देश का उत्थान करेंगे, तो ये नहीं होगा. नेहरू ने अपने शासन में परंपरा स्थापित कर दी. सेना को बीच में नहीं आने दिया. सिविल सर्विसेज अपना काम करती रही. चुनाव हार गए तो सरकार अपोजिट पार्टी को दे दी, फिर हार गए तो फिर दे दी. वो लोकतंत्र स्वस्थ लोकतंत्र है, जहां हर पांच-दस साल में बिना किसी संकट के सरकार बदलती रहे. 1975 में इंदिरा गांधी ने गलती की, तो वे 1977 में हार गईं. 1980 में फिर उन्हें सत्ता मिल गई. अटल जी की सरकार आई, 10 साल कांग्रेस रही, फिर भाजपा की सरकार आ गई. राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि प्रेस लोकतंत्र का चौथा खंभा है. आज प्रेस लगभग खत्म ही हो गया है. चौथा खंभा सबसे पहले बिक गया, क्योंकि प्रेस एडिटर के हाथ में है नहीं, मालिकों के हाथ में है. मालिक पूंजीपति हैं और पूंजीपति तो सरकार से ऐसे ही डरता है. धीरे-धीरे हमलोग ऐसे अंधेरे में जा रहे हैं, ऐसी अंधेरी गुफा में जा रहे हैं, जिसके आखिर में उजाला नहीं दिख रहा है. मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं. अपनी पार्टी के अलावा देश के प्रति भी उनका उत्तरदायित्व है. यही समझ कर इंदिरा गांधी ने मोरारजी भाई को सरकार दे दी थी कि कांग्रेस नहीं, देश का मामला है. इनको भी समझना चाहिए कि जो रिजल्ट आए, उसे स्वीकार करें. कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया है, भाजपा भी करे. इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन ये सब सहिष्णुता, शिष्टाचार और मर्यादाएं रखते हुए मान्यताओं और संविधान के दायरे में उस भारतीय संस्कृति के साथ होना चाहिए, जिसकी बात आरएसएस वाले करते हैं. इसे ही रामराज्य कहते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का बयान और कश्मीर की हक़ीक़त

शुजात बुख़ारी

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने यह बयान देकर कि 'आज़ाद' जम्मू-कश्मीर का विचार हकीकत पर आधारित नहीं है, एक तरह से मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ दिया है. उनके बयान पर जम्मू-कश्मीर के प्रतिरोधी पक्ष ने हंगामा नहीं किया. गौरतलब है कि यह पक्ष कश्मीर समस्या का वहां के लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं अनुसार हल के लिए संघर्षरत है. लगभग 30 वर्षों से जो लोग इस समस्या के समाधान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वे स्वतंत्र जम्मू और कश्मीर के मौजूदा विचार पर खामोश हैं.

प्रधानमंत्री अब्बासी ने लंदन में हो रहे एक कांफ्रेंस के दौरान कहा कि इस आजाद कश्मीर के विचार को अक्सर बहस में लाया जाता है, लेकिन इसकी कोई हकीकत नहीं है. आज़ाद कश्मीर की मांग को लोगों का समर्थन हासिल नहीं है. यह पहला मौक़ा नहीं है, जब किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर अपने सरकार का रुख रखा हो. स्वर्गीय प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो ने भी इस विचार को ख़ारिज किया था. लेकिन उस बयान से उपजे विवाद के बाद उन्होंने खामोशी अख्तियार कर लिया था.

पाकिस्तान ने यह धारणा इस बुनियाद पर कायम की है कि जम्मू-कश्मीर का आखिरी हल संयुक्त राष्ट्रसंघ के उस प्रस्ताव की बुनियाद पर होगा, जिसमे यहां के लोगों को भारत और पाकिस्तान में से किसी के विकल्प को चुनने के लिए आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाएगा. हालांकि जब आजाद कश्मीर के विचार की ओर ध्यान दिलाया जाता है, तो पाकिस्तान का अक्सर यही पक्ष रहता है कि जो भी होगा आवाम की इच्छा के अनुसार होगा. यहां तक कि सैयद अली शाह गिलानी जैसे हार्डलाइनर (इस मुद्दे पर) ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि वे जम्मू-कश्मीर का पाकिस्तान के साथ विलय चाहते हैं. लेकिन यदि लोग इसके अलावा कुछ और चाहते हैं, तो वे उसका स्वागत करेंगे. हालांकि तहरीक-ए-हुर्रियत द्वारा हाल ही में आयोजित एक सेमिनार में गिलानी और उनके नायेब अशरफ सरराई ने कहा कि दो राष्ट्र का सिद्धांत सही साबित हुआ है.

यदि जम्मू-कश्मीर मसले के हल पर पाकिस्तान के संविधान को देखा जाए, तो उसमे स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया है. उस लिहाज़ से प्रधानमंत्री अब्बासी का बयान गलत नहीं है. जम्मू-कश्मीर से संबंधित पाकिस्तान के संविधान का अनुछेद 257 कहता है, जब जम्मू-कश्मीर राज्य के लोग पाकिस्तान के साथ विलय पर फैसला ले लेंगे, तो पाकिस्तान और उस राज्य के बीच के रिश्तों को वहां के लोगों की इच्छाओं के अनुसार निर्धारित किया जाएगा. इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जम्मू-कश्मीर पहले पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा और फिर उसके साथ संबंध निर्धारित किया जाएगा.

इसी तरह, पाकिस्तान शासित जम्मू-कश्मीर का संविधान यह स्पष्ट करता है कि जम्मू-कश्मीर का भविष्य संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों की बुनियाद पर तय किया जाएगा. जहां जम्मू-कश्मीर राज्य के भविष्य की स्थिति वहां के लोगों की इच्छाओं के अनुरूप अभी तक तय नहीं हुई है. इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने समय-समय पर पारित अपने यूएनसीआईपी प्रस्तावों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और लोकतांत्रिक जनमत संग्रह करवाने की बात की है (एजेके संविधान 1974).

इन स्पष्ट स्थितियों के बावजूद, पाकिस्तान की सरकारें पिछले 30 वर्षों के दौरान उन पर प्रतिबद्ध नहीं रही हैं और जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक और मिलिटेंट दोनों तरह के संघर्षों का समर्थन किया है. या तो इस्लामाबाद अपनी नीति उस समय तक छिपा कर रखना चाहता है, जबतक वो जम्मू-कश्मीर हासिल न कर ले, या फिर पिछले तीन दशकों की नई वास्तविकताओं को देखते हुए उसके पास कोई विकल्प नहीं है. यह उल्लेखनीय है कि 1989 के अंत में जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के तत्वाधान में कश्मीर में सशस्त्र बगावत शुरू हुई थी. जेकेएलएफ के पास भी स्वतंत्र जम्मू-कश्मीर का कोई स्पष्ट चार्टर नहीं था.

बहरहाल पाकिस्तान ने सशस्त्र संघर्ष के लिए जेकेएलएफ की सहायता की. हालांकि यह बिल्कुल अलग बात है कि जैसे ही पाकिस्तान ने अपने समर्थक संगठन खड़े कर लिए, उसके लिए जेकेएलएफ की वो अहमियत नहीं रही और वही स्थित अबतक बनी हुई है. हालांकि इस्लामाबाद में उसकी मौजूदगी बनी रही और सरकार ने समय-समय पर उसे परामर्श का हिस्सा भी बनाया. जेकेएलएफ सुप्रीमो अमानुल्लाह खान का पाकिस्तान के साथ प्यार और नफरत का रिश्ता उनकी मृत्यु तक जारी रहा. पाकिस्तान सरकार ने अपने कानून के पालन में रियायत नहीं दी, जब 1990 में पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा (एलओसी) पार करते 11 जेकेएलएफ कार्यकर्ताओं को मार गिराया था. प्रधानमंत्री अब्बासी के बयान पर श्रीनगर से जेकेएलएफ की प्रतिक्रिया आई, जो हल्की और अस्पष्ट थी. पूर्व में जेकेएलएफ के अध्यक्ष ने 2003 में अपने सफ़र-ए-आजादी के दौरान आजादी के पक्ष में 1.5 मिलियन हस्ताक्षर एकत्र किए थे.

पाकिस्तान ने यह धारणा इस बुनियाद पर कायम की है कि जम्मू-कश्मीर का आखिरी हल संयुक्त राष्ट्रसंघ के उस प्रस्ताव की बुनियाद पर होगा, जिसमे यहां के लोगों को भारत और पाकिस्तान में से किसी के विकल्प को चुनने के लिए आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाएगा. हालांकि जब आजाद कश्मीर के विचार की ओर ध्यान दिलाया जाता है, तो पाकिस्तान का अक्सर यही पक्ष रहता है कि जो भी होगा आवाम की इच्छा के अनुसार होगा.

लोगों की इच्छा दीवार पर लिखी इबारत की तरह स्पष्ट है. इसमें कोई शक नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रस्ताव भारत और पाकिस्तान का दो विकल्प देता है, क्योंकि 1948 में केवल यही दो विकल्प मौजूद थे. लेकिन 1990 के बाद से आज़ाद जम्मू-कश्मीर का मुद्दा बड़ा मुद्दा बन गया. पिछले कुछ सालों में हुए परिवर्तनों की वजह से पाकिस्तान या आईएसआईएस के झंडे प्रदर्शनों के दौरान नज़र आने लगे हैं. लेकिन इसके बावजूद, जनता की अंतर्धारा वही है जो पहले थी. पाकिस्तान द्वारा ईद की घोषणा के बाद कश्मीरियों के ईद मानाने की घोषणा या भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच, पाकिस्तान के साथ यहां के लोगों के भावनात्मक लगाव को ज़ाहिर करते हैं. लेकिन जब जनता की बात आती है, तो यहां राजनीति अलग हो जाती है.

भले ही वे लोग, जो इस मुद्दे के समर्थक हैं और जिन्होंने लोगों को हिंसा के लिए प्रेरित किया है, वे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर चुप्पी साध लें, लेकिन इससे जमीनी राजनीतिक वास्तविकताओं को नहीं बदला जा सकता है. शायद यही वास्तविकताएं थीं, जिन्होंने तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों को ताक पर रख कर आउट-ऑफ-द-बॉक्स समाधान पर विचार करने पर मजबूर किया था. संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव इस बात के सबूत हैं कि समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन जहां तक विकल्पों का सवाल है, तो वास्तविकताएं बदल गई हैं. आउट-ऑफ-द-बॉक्स का मतलब कुछ भी हो सकता है.

सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज़ उमर फारूक और यासीन मलिक के संयुक्त प्रतिरोध नेतृत्व ने अपने संयुक्त मंच से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. ऑल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस का संविधान, जो प्रतिरोध आंदोलन के नेतृत्व का दावा करता है, ने तीसरा विकल्प चुना. एपीएचसी संविधान के अध्याय-2 के अनुच्छेद-2 में दर्ज हुर्रियत के उद्देश्यों के अंतर्गत कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर राज्य के लोगों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर और प्रस्तावों के अनुरूप आत्म-निर्णय के अधिकार के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष करना है. हालांकि आत्मनिर्णय के अधिकार के प्रयोग में स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल होगा. संयुक्त नेतृत्व को अपना रुख स्पष्ट करना होगा.

पाकिस्तान कश्मीर के पक्ष का समर्थन कर रहा है, लेकिन यह इसकी ईमानदारी का भी इम्तेहान होगा. प्रधानमंत्री अब्बासी के बयान का ध्येय कि आज़ाद कश्मीर के विचार को कोई समर्थन नहीं है, तथ्यों पर आधारित नहीं है. खास तौर पर ऐसे में जब यहां की हावी राजनीतिक विचारधारा है. हालांकि अब्बासी ने अपने बयान से पाकिस्तान की स्थिति को सरल बनाया है और सिर्फ संविधान की व्याख्या की है. लेकिन कश्मीर के नेतृत्व के लिए यह एक चुनौती है कि वे बिना लागलपेट इस क्षेत्र के लोगों को आश्वस्त करे कि आत्मनिर्णय का मुद्दा धर्म पर आधारित नहीं है. ■ **-लेखक राइजिंग कश्मीर के संपादक हैं.**

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

गुजरात चुनाव में प्रधानमंत्री की तीस सभाओं के मायने क्या हैं

गुजरात चुनाव लोगों की जुबान पर है. कांग्रेस ने वहां पूरी ताकत झोंक दी है और भाजपा भी अपनी संपूर्ण शक्ति चुनाव में लगाने जा रही है. कांग्रेस के प्रचार ने भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा तो परेशान कर ही दिया है. भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ताबड़तोड़ 30 सभाओं की तैयारी की है. गुजरात चुनाव में सरकार के काम, मंत्रिमंडल या मुख्यमंत्री मुद्दा नहीं है, वहां पर पहला बड़ा मुद्दा है नरेन्द्र मोदी जी की छवि. अगर गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें मिलीं या ये चुनाव हार गए या करीब 10 सीटों के मार्जिन से जीत पाए तो सारे देश में नरेन्द्र मोदी की भद्द पिटेगी. भारतीय जनता पार्टी के हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इसी वजह से अमित शाह ने नरेन्द्र मोदी जी को 30 सभा करने के लिए तैयार किया है. मतलब गुजरात के एक जिले में वे दो से तीन बार जाएंगे. ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में अपने काम पर भरोसा नहीं रहा? भारतीय जनता पार्टी को दूसरा झटका चुनाव आयोग ने दिया है. कांग्रेस के खिलाफ प्रचार अभियान के लिए भाजपा ने बड़ी मात्रा में ऐसी प्रचार सामग्री छपवा रखी थी, जिसमें पप्पू शब्द का इस्तेमाल किया गया था. चुनाव आयोग ने कहा है कि आप पप्पू शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. इससे भाजपा की वो पूरी प्रचार सामग्री बेकार हो गई है. उस पैसे का हिसाब भी चुनाव आयोग लेगा. अब गुजरात भारतीय जनता पार्टी जल्दी-जल्दी नई प्रचार सामग्री तैयार करने की कोशिश कर रही है.

मजेदार बात यह है कि गुजरात का चुनाव इस मुद्दे पर नहीं हो रहा है कि कांग्रेस क्या काम करेगी या भाजपा ने अब तक क्या काम किए हैं और आगे क्या करेगी? गुजरात का चुनाव हो रहा है, सेक्स सीडी को लेकर. हालांकि इस सेक्स सीडी में सेक्स है ही नहीं, सिर्फ सीडी है. लेकिन भाजपा ने इसे मीडिया के जरिए सेक्स सीडी कह कर प्रचारित किया. सीडी में अगर हार्दिक पटेल लड़कियों के साथ हैं, किसी होटल के कमरे में या किसी रेस्टोरेंट में बैठ कर बातें कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? साथ में और भी लोग है. किसी ने कपड़े नहीं उतारे, कोई अश्लील हरकत नहीं की, फिर भी उसे सेक्स सीडी कहकर प्रचारित किया जा रहा है. जानकार बताते हैं कि आज जैसी टेक्नोलॉजी है, उससे इस तरह का क्लिप बनाना बहुत आसान काम हो गया है. मैंने गुजरात के साधारण लोगों से पूछा कि क्या गुजरात चुनाव में इसका कोई असर पड़ेगा. लोगों कहना है कि इसका असर तो तब पड़ता, जब वो सच होती. हार्दिक पटेल पहले ही इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी मेरा चरित्र हनन भी कर सकती है और पाटीदार समाज से कुछ लोगों को भटकाने की कोशिश कर सकती हैं. लोग भटके भी हैं. मेरी जानकारी के अनुसार, लगभग 12 से 16 प्रतिशत लोग हार्दिक पटेल की इस सीडी से थोड़े परेशान हुए हैं और इसे लेकर वे पसोपेश में पड़ गए हैं कि हार्दिक पटेल को वोट दें या न दें. सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी यह चुनाव सेक्स सीडी के आधार पर लड़ना चाहती है. मैं ये सोच रहा था कि ये सेक्स सीडी क्यों आती है?

भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता के खिलाफ जयपुर में एक सेक्स सीडी आई थी. उस सीडी की सरकार ने जांच कराई. जांच में पता चला कि वो सेक्स सीडी नकली थी. बड़ी होशियारी से किसी एक्सपर्ट ने उसे बनाया था. लेकिन कब पता चला, जांच के बाद. इस बीच में क्या हुआ? उस अतिवरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता का करियर चौपट हो गया, उनसे इस्तीफा ले लिया गया. आप समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं. ये वहीं नेता हैं, जिनकी वजह से मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी मुंबई में होने वाली भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल नहीं हो रहे थे. उन्होंने शर्त रखी थी कि जब तक वो नेता मुंबई में रहेगा या अधिवेशन में रहेगा, मैं अधिवेशन में नहीं आऊंगा. उसके बाद उस नेता को वहां से हटाया गया. वे पार्टी में संगठन सचिव थे. लेकिन जब जांच के बाद यह पता चल गया कि सेक्स सीडी झूठी है, तब भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की हिम्मत नहीं हुई कि उस व्यक्ति को दोबारा संघ में या भारतीय जनता पार्टी में उसी पद पर वापस लाए. संघ प्रमुख और संघ के नेता चोरी-चोरी उस नेता से मिलते तो हैं, लेकिन उसे कोई पद या कोई विशेष काम देने की हिम्मत अभी नहीं जुटा पा रहे हैं. लेकिन आज भी वो नेता जहां जाता है, हजारों की भीड़ हो जाती है. जब उसका जन्मदिन होता है, तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, सांसद, विधायक और कार्यकर्ताओं का हुजूम उनके घर नॉर्थ ऐवेन्यू पहुंच जाता है.

हार्दिक पटेल को लेकर के दो सीडी आई हैं. मैं सीडी से सम्बन्धित तकनीकी सवाल की बजाय राजनीतिक सवाल उठाना चाहता हूं. इस सीडी ने हार्दिक पटेल को देश में मशहूर कर दिया है. जो हार्दिक पटेल एक राजनीतिक नेता के तौर पर जाने जाते थे, वो अब एक ऐसे नौजवान के तौर पर भी लोगों के सामने आए हैं, जिनकी तस्वीर प्लेबॉय की है. भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा ही करना चाह रही होगी, लेकिन इसका फायदा नहीं हुआ. हमारे यहां जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, एक नई चीज शुरू हुई है कि आप किसी का चेहरा जोड़कर किसी का भी चरित्र हनन कर सकते हैं. चौथी दुनिया के 2010 के अंक में हमने मोसाद को लेकर के दो-तीन बड़ी स्टोरी की थी. उसी दौरान मेरे पास कुछ खबर आई. मीडिया के कुछ समझदार पत्रकारों के अपने सम्पर्क होते हैं और उन्हें यह मालूम होता है कि कौन जासूस क्या कर रहा है. हमारे पास खबर आई कि मोसाद के लोग हमें फंसाने का प्लान बना रहे हैं. पता चला कि चूंकि चौथी दुनिया ने इस देश में मोसाद की गतिविधियों का खुलासा किया था, इसलिए वे लोग हमें सेक्स स्कैंडल में फंसाने की योजना बना रहे थे. मैंने सोचा कि फौरन ये स्टोरी करनी चाहिए और हमने वो स्टोरी की भी और शायद इसी वजह से उनका प्लान थम गया. आज टेक्नोलॉजी के जरिए लोग बड़े-बड़े अपराध और पाप कर रहे हैं. हमने एक स्टोरी की थी पोनोग्राफी को लेकर कि यह कैसे समाज में रिश्तों को तार-तार कर रहा है और लोग उसको देख रहे हैं. हमने अपने यहां रिसर्च कराई, तो पता चला कि यह तो बहुत मजे की दुनिया है. बहुत पैसा भी है, लेकिन उसमें रिश्ता नाम की कोई चीज नहीं है. लोगों के दिमाग को कनवर्ट करने में और दूषित करने में इन पोर्न वेबसाइट्स का बहुत बड़ा योगदान है. यह काम वहीं लोग कर रहे हैं, जो सेक्स सीडी के नाम पर योजना बनाते हैं कि कैसे किसी का करियर और कैसे किसी के रिश्ते को खत्म कर दिया जाए. ये गंभीर बात है. हालांकि गुजरात चुनाव में इस सेक्स सीडी का कोई असर नहीं होने वाला है.

> मजेदार बात यह है कि गुजरात का चुनाव इस मुद्दे पर नहीं हो रहा है कि कांग्रेस क्या काम करेगी या भाजपा ने अब तक क्या काम किए हैं और आगे क्या करेगी? गुजरात का चुनाव हो रहा है, सेक्स सीडी को लेकर. हालांकि इस सेक्स सीडी में सेक्स है ही नहीं, सिर्फ सीडी है. लेकिन भाजपा ने इसे मीडिया के जरिए सेक्स सीडी कह कर प्रचारित किया. सीडी में अगर हार्दिक पटेल लड़कियों के साथ हैं, किसी होटल के कमरे में या किसी रेस्टोरेंट में बैठ कर बातें कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है?

यशवंत सिन्हा ने 14 नवंबर को गुजरात के एक हॉल में भाषण दिया. उन्हें सुनने के लिए भारी भीड़ आई थी. यशवंत सिन्हा के उस भाषण को सबको सुनना चाहिए. आप सबको सुनना चाहिए कि कैसे एक समझदार भूतपूर्व वित्त मंत्री स्थितियों का विश्लेषण करता है. उन्होंने किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया. बस स्थितियां सामने रखी. उन्होंने कहा कि ये कैसा लोकतंत्र है, जहां पर अगर कोई अपनी बात कहना चाहे, तो वो आदमी देशद्रोही हो जाता है. लोकतंत्र में तो सबकी आवाज उठती है. ये कैसा लोकतंत्र है. उन्होंने कहा कि हमारे यहां लोकशाही होनी चाहिए. उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी की सच्चाई सामने रखी. हालांकि उनका भाषण कहीं टेलीविजन पर प्रसारित नहीं हुआ. एक चीज मैं अपने पाठकों के ध्यान में लाना चाहता हूं. हमने आज से पांच महीने पहले राफेल सौदे के ऊपर लीड स्टोरी की थी. फ्रांस से जो राफेल हवाई जहाज आ रहा है, उसे लेकर वो स्टोरी थी. तब किसी नेता ने कोई सवाल नहीं उठाया. आज खबर आ रही है कि उस राफेल डील के भीतर क्या-क्या है. कांग्रेस आज तिलमिला कर बोल रही है. लेकिन छह महीने पहले अगर बोलती, तो शायद असर होता. पांच महीने के बाद आज जाकर राफेल डील को लेकर खुलासे हो रहे हैं. यह है हमारे देश के विपक्ष का दिमागी दिवालियापन, जिन्हें विषय ही समझ में नहीं आता. बहरहाल, हम फिर गुजरात पर आते हैं और गुजरात पर ही अपनी बात खत्म करते हैं. प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ 30 सभाएं बताती हैं कि गुजरात में कांग्रेस ने कुछ करने की कोशिश की हो या नहीं, लेकिन गुजरात की जनता जरूर हिल गई है. उसने जिस प्यार और हिम्मत के साथ 2012 का चुनाव जिताया था, वो इस समय उस मूड में नजर नहीं आ रही है. जनता फिर से 2012 वाले मूड में आए, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ताबड़तोड़ 30 सभाओं की योजना बना चुके हैं. आखिरी पड़ाव कैसा होगा, यह तो जब वोट पड़ेगा तभी पता चलेगा लेकिन अभी कुछ स्पीड ब्रेकर जरूर नजर आ रहे हैं. ■

editor@chauthiduniya.com

बैंकों में पूंजी लगाने का सरकारी निर्णय से जुड़े सवाल

24 अक्टूबर को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 2.11 लाख करोड़ रुपए की पूंजी डालने की घोषणा की. इनमें से 1.35 लाख करोड़ रुपए बॉन्ड जारी करके जुटाए जाएंगे, बाकी के 76,000 करोड़ रुपए बजट से और बाजार उधारी के जरिए आएंगे. बैंकों में गैर निष्पादित संपत्तियों, यानि एनपीए की समस्या को देखते हुए इस सरकारी निर्णय का कुछ लोगों ने स्वागत किया. कई बैंकों की शेयरों की कीमतों में उछाल आया.

सरकार के इस निर्णय से दो चीजें जुड़ी हुई हैं. पहली बात तो यह कि बैंकों के कर्ज की गुणवत्ता बेहद खराब हुई है. रिजर्व बैंक ने अपने सालाना रिपोर्ट में बताया कि मार्च, 2017 के अंत तक बैंकों के कुल कर्ज का 12.1 फीसदी मुश्किल में है. इसमें एनपीए और पुनर्संगठित कर्ज दोनों शामिल हैं. सरकारी बैंकों को 2016-17 में भी नुकसान हुआ. बैंकों की यह बुरी स्थिति 2009 की वैश्विक आर्थिक संकट के समय से ही बनी हुई है. नियामकों के निर्णय

और अन्य वजहों से बुनियादी ढांचा क्षेत्र से संबंधित कई परियोजनाएं लटक गईं और बैंकों का एनपीए बढ़ता गया. दूसरी बात यह है कि बैंकों के कर्ज के विकास दर में 2014-15 से लगातार कमी आ रही है. 2016-17 में यह 8.2 फीसदी रही. कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों में तो कर्ज में और कमी आई है. साल भर पहले जहां ऐसे कर्जों की विकास दर 15.9 फीसदी थी, वहीं सितंबर, 2017 में यह 5.8 फीसदी रही. सेवा क्षेत्र में भी यही स्थिति है.

अब सवाल उठता है कि ये दोनों चीजें आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं और कर्ज की विकास दर में कमी के लिए क्या सिर्फ एनपीए जिम्मेदार है. सरकारी दावों के बावजूद पिछले छह तिमाही में विकास दर नीचे आया है. अप्रैल-जून 2017 में जीडीपी 5.7 फीसदी रही. यह पिछले तीन साल में सबसे कम है. नोटबंदी और बगैर तैयारी के जीएसटी लागू करने से आर्थिक स्थिति और खराब हुई. ऐसी स्थिति में बैंकों में पूंजी डालने के बावजूद निजी कंपनियां बैंकों के पास नए कर्ज के लिए आएं, इसकी संभावना कम है. कुछ लोग सरकार के इस निर्णय की तुलना किसानों की कर्जमाफी से कर रहे हैं. हमें पहले बताया गया कि कर्ज माफी से ईमानदारी की संस्कृति खराब होगी. कर्ज नहीं चुका पाने वाले लोगों की सूची सार्वजनिक करने को लेकर अनिच्छा देख चुके हैं. ऐसे समय में जब बड़ी कंपनियां कर्ज नहीं चुका पा रही हैं और कर्ज वसूली की प्रक्रिया बेहद धीमी है तो फिर सरकार क्या संकेत दे रही है? क्या बैंकों में सरकार द्वारा पैसा लगाए जाने में कोई नैतिक समस्या नहीं आई? इसे लेमन समाजवाद कहा जाता है. जहां नुकसान को समाजवादी बना दिया जाता है और लाभ को पूंजीवादी. ये बॉन्ड कौन खरीदेगा और अगर बैंक ही खरीदेंगे तो इससे क्या निजी उधारी हतोत्साहित नहीं होगी? इन सवालों के जवाब अभी आने हैं.

बैंकिंग संकट को सुलझाने के प्रति लोगों की उम्मीद अलग रही है. इन्सॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड से लोगों को काफी उम्मीदें थीं. लेकिन स्टील, बिजली और दूरसंचार क्षेत्र की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. 2017-18 का बजट बैंकिंग क्षेत्र को लेकर बहुत प्रभावी नहीं था. तो फिर अब बैंकों में पूंजी लगाने का निर्णय क्यों लिया गया? अब दो राज्यों में चुनाव हैं और अर्थव्यवस्था बुरी हालत में है, तो क्या यही वह आर्थिक पैकेज है, जिसकी बात चल रही थी? बैंकों को पुनर्संगठित करने की योजना का क्या हुआ? सरकार का यह निर्णय जितने जवाब देता है उससे अधिक सवाल खड़े करता है और यह इस निर्णय की बहुत बड़ी खामी है. ■

(साभार : इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली)

feedback@chauthiduniya.com

एफआईआर कराने की सज़ा : बलात्कार पीड़िता को अग़वा कर फिर किया सामूहिक बलात्कार

बलात्कारियों की 'मित्र-पुलिस'

सामूहिक बलात्कार का शिकार लड़की

बलात्कार पीड़िता की मां

- सरकार किसी की हो, ऊंचाहार में चलती है सपा नेता की
- बलात्कारियों को मिल रहा है पूर्व मंत्री का सीधा संरक्षण
- लड़की को थाने में बंधक रखा, नहीं कराई मेडिकल जांच
- दोषियों के बजाय पीड़िता के भाई को ही भेज दिया जेल
- न्याय के लिए भटक रही बलात्कार पीड़िता और परिवार
- नेता-पुलिस-अपराधी गठजोड़ के आगे लाचार है क़ानून

लूफी यायावर

भाजपा की सरकार में भी सपाई नेताओं का शासन और प्रशासन पर दबदबा कायम है. पुलिस की भी पुरानी आदत गई नहीं है. योगी सरकार की पुलिस सपा सरकार में मंत्री रहे मनोज पांडेय के इशारे पर अपराधियों को बचाने और भुक्तभोगियों को फंसाने के काम में लगी है और योगी सरकार की साख पर बट्टा लगा रही है. किसी न किसी वजह से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले रायबरेली के ऊंचाहार में अभी कुछ ही दिनों पहले भंगी जाति की नाबालिग लड़की के साथ सपा नेता के गुर्गों ने सामूहिक बलात्कार किया. पुलिस ने अपहरण और बलात्कार की शिकायत करने थाने पहुंची लड़की को बंधक बना लिया और उसके भाई समेत दो लोगों को उल्टा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. पुलिस ने सामूहिक बलात्कार की भुक्तभोगी लड़की की मेडिकल जांच भी नहीं होने दी. काफी हील-हुज्जत के बाद एफआईआर लिखी, लेकिन उसकी कॉपी भुक्तभोगी परिवार को नहीं दी. पुलिस में शिकायत करने के जुर्म में लड़की को अगवा कर उसे दोबारा सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाया गया. लेकिन आज तक कोई कारगर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई. बलात्कारियों की तरह पुलिस ने भी वैसा ही चरित्र दिखाया और केस में फाइनल रिपोर्ट लगा दी. भुक्तभोगी लड़की को साथ लेकर उसकी मां शोभा और पिता मेवालाल दरवाजे-दरवाजे भटक रहे हैं, लेकिन न्याय कहीं हो तब तो मिले! ऊंचाहार थाने के प्रभारी परशुराम त्रिपाठी ऊंची पहुंच रखते हैं, इसीलिए कानून को ठेंगे पर रखते हैं. स्थानीय लोग कहते हैं कि ऊंचाहार में तो कानून नेताओं और अपराधियों के ठेंगे पर ही रहता है.

आरोप है कि रायबरेली के अकूढ़िया थानान्तर्गत (ऊंचाहार कोतवाली के तहत) सलीमपुर भैरों गांव के दलित मेवालाल की नाबालिग बेटी के साथ 24 फरवरी को ही धीरू मिश्रा (पुत्र राजेंद्र मिश्रा) और उसके साथियों ने सामूहिक बलात्कार किया था. इस सनसनीखेज वारदात का कोई असर स्थानीय पुलिस पर नहीं पड़ा और कोई कार्रवाई नहीं हुई. तब प्रदेश में सपा सरकार का आखिरी दौर था. सपा सरकार में मंत्री मनोज पांडेय बलात्कारियों की मदद में खुलेआम मैदान में थे. भुक्तभोगी लड़की और उसका परिवार थाने में बंधक बना रहा और थाने से लेकर कोतवाली और रायबरेली के पुलिस अधीक्षक के दफ्तर तक बलात्कारियों के पैरोकार जमे बैठे रहे. पत्रकार व समाजसेवी अल्लामा जमीर नकवी द्वारा सूचना दिए जाने के बाद जब अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग के सहायक निदेशक तरुण खन्ना ने राज्य पुलिस मुख्यालय से सम्पर्क साधा और कानून व्यवस्था (लॉ एंड ऑर्डर) के अपर पुलिस महानिदेशक (कानून/व्यवस्था) दलजीत चौधरी ने रायबरेली के एसपी को फोन पर हड़काया तब जाकर घटना के तीन दिन बाद 27 फरवरी 2017 को बलात्कार का मुकदमा (संख्या-112/2017, धारा-376/323/506 भा.दं.वि. और (2) 5 एससी/एसटी एक्ट) दर्ज हो पाया. तीन दिन तक बलात्कार पीड़ित लड़की को पुलिस ने थाने पर बंधक बनाए रखा और उसकी मेडिकल जांच नहीं होने दी, ताकि प्रमाण नहीं मिल सके. इतना सब होने के बाद भी थाना प्रभारी परशुराम त्रिपाठी ने केस हल्का करने के लिए नाबालिग लड़की को बालिग लिख दिया, जबकि लड़की के परिवार वालों ने लड़की को नाबालिग साबित करने वाले दस्तावेज और आधार कार्ड वगैरह प्रस्तुत किए, लेकिन थाना प्रभारी ने उसे नहीं माना, दस्तावेज की कॉपियां फाड़ डालीं और एफआईआर में पीड़िता को बालिग लिख दिया.

बलात्कारियों की मदद में लगी पुलिस ने भुक्तभोगी परिवार को एफआईआर की कॉपी भी नहीं दी. पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का नतीजा यह निकला कि बलात्कार के आरोपियों ने चार महीने बाद भुक्तभोगी लड़की का अपहरण कर लिया और इलाहाबाद ले जाकर तीन दिनों तक उसके साथ बलात्कार किया. सामूहिक बलात्कार की पहली घटना सपा सरकार के कार्यकाल में घटी. उसी लड़की के साथ अपहरण और सामूहिक बलात्कार की दूसरी घटना भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुई. दोनों सरकारों की असलियत यही है. सपा की सरकार में भी गुंडों का राज था, भाजपा की सरकार बनने के बाद भी गुंडों का ही दबदबा कायम है. उन्हीं गुंडों ने नाबालिग दलित लड़की को योगी सरकार बनने के चार महीने बाद अगवा किया और तीन दिन तक उसके साथ बलात्कार किया. इस घटना की एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी, जबकि सरकार बदल चुकी थी. लेकिन थानेदार की सपाई-भक्ति बरकरार थी. आखिरकार अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग को फिर सीधा हस्तक्षेप करना पड़ा, तब जाकर 21 जुलाई 2017 को ऊंचाहार कोतवाली में एफआईआर (मुकदमा संख्या-300/2017, धारा-364/ 376/डी /342 /452/ 507/506/323/504 भादंवि एवं 3/4 पाक्सो एक्ट और 3 (2) 5 दलित उत्पीड़न निषेध अधिनियम) दर्ज हो सकी. विडंबना यह है कि प्रथम घटना की पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट (अंतिम आख्या) भी लगा दी और केस बंद कर दिया. इस संवेदनशील प्रकरण में अपराधियों को संरक्षण देने वाले थाना प्रभारी परशुराम त्रिपाठी और क्षेत्राधिकारी पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें बचाने की ही कोशिशें हो रही हैं. भुक्तभोगी लड़की की मां शोभा का कहना है कि सामूहिक बलात्कार की घटना के दोषी अपराधियों को उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया होता, तो दूसरी वीभत्स घटना नहीं होती. लड़की की मां कहती हैं कि थाने में बंधक बनाए रखने के दरम्यान परशुराम त्रिपाठी ने कुछ सादे कागजात पर लड़की से हस्ताक्षर कराए थे. सपा सरकार में मंत्री रहे मनोज पांडेय ने ही परशुराम त्रिपाठी की तैनाती ऊंचाहार कोतवाली में कराई थी. शोभा कहती हैं कि वे अपनी बिटिया को लेकर ऊंचाहार कोतवाली पहुंचीं, तब त्रिपाठी ने उन्हें गालियां दीं और बलात्कारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनके बेटे रंजीत कुमार और रंजीत के एक दोस्त सोनू यादव को गिरफ्तार कर उन्हें ही जेल भेज दिया. तीन दिन तक उन्हें और उनकी बिटिया को थाने में बंधक बनाए रखा. आयोग और मुख्यालय के दबाव पर मुकदमा (112/2017) दर्ज भी हुआ तो पुलिस ने पाक्सो एक्ट और अन्य जरूरी धाराएं नहीं लगाईं. लड़की को नाबालिग साबित करने वाले जन्मतिथि प्रमाण-पत्र और आधार कार्ड वगैरह की छाया प्रतियां फाड़ डालीं. एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने बलात्कार मामले में कोई कार्रवाई नहीं की. पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक मनोज पांडेय का प्रशासन पर इतना दबाव है कि उन्होंने बलात्कारियों को बचाने वाले चहेते दारोगा का काम हो जाने के बाद अन्यत्र तबादला करा दिया और जब चुनाव आया, तब वापस उसी थाने में उसकी तैनाती करा दी. उसके बाद फिर उसे लखनऊ स्थानांतरित करा दिया. नाबालिग दलित लड़की से दो-दो बार हुए सामूहिक बलात्कार की घटना का मामला अधर में लटका हुआ है. राजनीतिक प्रतिशोध लेने के लिए कराई गई गंभीर आपराधिक घटना प्रशासनिक शोहदेपन के कारण कानूनी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है. ■

feedback@chauthiduniya.com

ऊंचाहार में आपराधिक दबाव ही राजनीतिक वर्चस्व की पहचान है

ऊंचाहार के सपा विधायक व पूर्व मंत्री मनोज पांडेय कभी सपा के लिए ब्राह्मणों को जुटाने तो कभी सपा के लिए अपराधियों को जुटाने के लिए हमेशा चर्चा में रहे. विधानसभा में विस्फोटक पदार्थ रखवाने के मामले में भी पिछले दिनों मनोज पांडेय काफी सुर्खियों में रहे. यहां तक कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) तक ने पांडेय से पूछताछ की. पांडेय सपा का कम अपना हित अधिक साधते रहे हैं. यही वजह है कि उनका सीधा कनेक्शन भाजपा से भी है, इसीलिए प्रशासन पर उनका दबदबा बना रहता है. दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार का जघन्य मामला हो या राजनीतिक हित साधने के लिए इलाके में होने वाली हत्याओं का मामला, कानून का हाथ मनोज पांडेय और उनके गुर्गों तक नहीं पहुंच पाता. योगी सरकार विवश है. कुछ अर्सा पहले ऊंचाहार क्षेत्र में पांच ब्राह्मण युवकों के जन-पिटाई के दौरान मारे जाने के मामले में खूब बवाल मचा. यहां तक कि योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और पूर्व मंत्री मनोज पांडेय आमने-सामने आ गए और तीखी टिप्पणियां जारी कीं. पिछड़े समुदाय के लोगों ने मनोज पांडेय के खिलाफ लखनऊ में धरना-प्रदर्शन भी किया. स्वामी प्रसाद मौर्य ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि मारे गए पांच युवक अपराधी (शूटर) थे और वे मनोज पांडेय के इशारे पर इटौरा बुजर्ग गांव के प्रधान रामश्री यादव की हत्या करने आए थे. मौर्य ने कहा कि पूर्व मंत्री मनोज पांडेय ने पूरा खेल रचा था. ग्रामीणों ने प्रधान को मारने आए हत्यारों को सजा दी. इस घटना से क्षेत्र में काफी तनाव बढ़ गया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मरने वाले लोगों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपए का मुआवजा देकर पिछड़ों को नाराज करने का ही काम किया. हालांकि मनोज पांडेय ने 20 लाख का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की थी. ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र के लोग ही कहते हैं कि आपराधिक वर्चस्व से राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने का ऊंचाहार बिल्कुल सटीक उदाहरण है. यहां के लोग आपराधिक दबदबे और आतंक को ही राजनीतिक प्रभाव समझने लगे हैं.

योगी सरकार ने लिखा केंद्र को पत्र, जन-भावनाओं का ख्याल रखे सेंसर बोर्ड

'पद्मावती' पर यूपी भी गर्म

चौथी दुनिया ब्यूरो

फिल्म 'पद्मावती' को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने कड़े तेवर अख्तियार किए हैं. योगी सरकार ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा है कि 'पद्मावती' फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों से की गई छेड़छाड़ के कारण प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, लिहाजा फिल्म की रिलीज रोक दी जाए. गृह विभाग के प्रमुख सचिव अरविंद कुमार ने केंद्र को भेजे पत्र में लिखा है कि एक दिसम्बर को उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के नतीजे आने हैं और मुस्लिमों का पर्व बाराव्फात भी है. फिल्म के कारण प्रदेश में बवाल होने की आशंका है, इसलिए फिल्म का प्रदर्शन टाल दिया जाए. गृह विभाग के प्रमुख सचिव अरविंद कुमार ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव एनके सिन्हा को पत्र भेजा है और कहा है कि ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करते हुए अतिरंजित, असत्य एवं काल्पनिक कथाओं वाली फिल्में सामाजिक विद्वेष उत्पन्न करने के साथ ही कानून व्यवस्था के लिए भी गंभीर चुनौती पैदा करती हैं. 9 अक्टूबर को फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से विभिन्न संगठनों में फिल्म के खिलाफ खासा आक्रोश है. फिल्म में जो दिखाया गया है, ऐतिहासिक तथ्य उससे उलट हैं. विभिन्न संगठनों ने फिल्म का प्रदर्शन होने पर सिनेमाघरों में तोड़फोड़, आगजनी और आंदोलन करने की चेतावनी दे रखी है. उत्तर प्रदेश सरकार ने सेंसर बोर्ड से भी अपील की है कि फिल्म के प्रमाणन के दौरान वह लोगों की भावनाओं का आदर करे. उधर, सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी का कहना है कि उन्होंने अभी फिल्म नहीं देखी है. फिल्म को हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पास भेजा गया है और इसके लिए तय प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

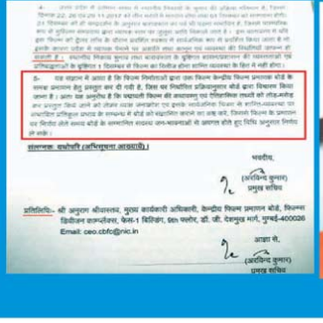

फिल्म 'पद्मावती' को लेकर व्याप्त तनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया है. 17 नवम्बर को 'द बर्निंग लव', एक दिसम्बर को 'पद्मावती' और 8 दिसम्बर को 'गेम आफ अयोध्या' फिल्म की रिलीज निर्धारित है. इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश में पुलिस को खास चौकसी बरतने का निर्देश दिया गया है. खुफिया एजेंसियों ने भी सरकार को सूचना दी है कि इन फिल्मों को लेकर विभिन्न संगठन प्रदर्शन और हिंसा पर उतारू हो सकते हैं. खुफिया सूचनाएं मिलने के बाद ही पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को जरूरी निर्देश भेजे गए. सिनेमाघरों और पीवीआर के आसपास कड़े सुरक्षा इंतजाम बनाए रखने के लिए कहा गया है. ■

feedback@chauthiduniya.com

चीनी मिल बिक्री-घोटाले की एक और जांच : 'बलि का बक़रा' तलाश रहा केंद्र

ताकि आंच और जांच से बची रहें मायावती

प्रभात रंजन दीन

चीनी मिल बिक्री घोटाले की आंच और सीबीआई जांच से मायावती को बचाने के लिए केंद्र सरकार नए-नए पैंतरे आजमा रही है. मायावती के कार्यकाल में कुछ खास पूंजी घरानों को प्रदेश की 21 चीनी मिलें कौड़ियों के भाव बेचे जाने के मामले में अब फिर से नया मोड़ आ गया है. इस नए मोड़ की खास वजहें हैं. इसे जानने के लिए पहले हम यह रुटीन सूचना प्राप्त करते चलें कि दो उन कंपनियों के खिलाफ पिछले दिनों लखनऊ के गोमती नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया, जो चीनी मिलों की खरीद में शामिल थीं. जबकि चीनी मिलें खरीदने में सबसे अधिक धांधली विवादास्पद पूंजीपति पींटी चड्ढा (अब दिवंगत) की कंपनियों ने प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व और नौकरशाहों से साठगांठ कर मचाई थी. अब आप याद करें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता-ग्रहण के बाद ही चीनी मिल खरीद घोटाले की सीबीआई से जांच कराने की मंशा जाहिर की थी. इसके फौरन बाद अरुण जेटली के कॉरपोरेट अफेयर मंत्रालय ने इस मामले में कानूनी बाधा डालने की कोशिश की. जेटली के मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग (कम्पीटीशन कमीशन ऑफ इंडिया) ने मायावती को फौरन क्लीन-चिट दे दी और कहा कि यूपी की चीनी मिलों की बिक्री में कोई गड़बड़ी नहीं हुई. आयोग ने अपने ही डीजी (इन्वेस्टिगेशन) की जांच रिपोर्ट दबा दी और 'दबाव' में मायावती को बेदाग करार देते हुए चरित्र-प्रमाण-पत्र जारी कर दिया. 'चौथी दुनिया' ने आयोग के डायरेक्टर जनरल (इन्वेस्टिगेशन) की वह जांच रिपोर्ट छाप दी, जिसमें चीनी मिलों की बिक्री में घनघोर अनियमितताएं किए जाने की आधिकारिक पुष्टि की गई थी. 'चौथी दुनिया' में रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद आयोग की घिघ्घी बंध गई और इस प्रकरण में केंद्र सरकार के राजनीतिक तिकड़म और केंद्र व राज्य के राजनीतिक विरोधाभास की कलई खुल गई.

शीर्ष राजनीतिक स्तर से मायावती को 'छत्र' देने की कोशिशें उजागर होते ही केंद्र सरकार को अपने पैर पीछे खींचने पड़े. फिर केंद्र ने एक नया कानूनी पैंतरा अख्तियार किया. इस नई पैंतरेबाजी का भी मजा देखिए... अरुण जेटली के जिस कॉरपोरेट अफेयर मंत्रालय के एक महकमे 'सीसीआई' ने मायावती को बेदाग बताया, उसी मंत्रालय के एक अन्य विभाग 'सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस' (सीआईएफओ) को चीनी मिलों की बिक्री की जांच सौंप दी गई. मंत्रालय के ही अधिकारी कहते हैं कि यह जांच 'बलि का बकरा' तलाशेगी और मायावती को बचाएगी. आप यह जानते हैं कि चीनी मिलों की बिक्री में बरती गई अनियमितताएं महालेखाकार (कैग) की जांच में पहले ही पकड़ी जा चुकी हैं. इसके बाद कम्पीटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक (अनुसंधान) ने भी अपनी जांच में अनियमितताएं पकड़ीं. यह अलग बात है कि आयोग ने अपने महानिदेशक (अनुसंधान) की जांच रिपोर्ट का ध्यान नहीं रखकर मायावती का ध्यान रखा. जब दो-दो जांचें चीनी मिलों की बिक्री में घोटाले की पुष्टि कर चुकी थीं, फिर तीसरी जांच की क्या जरूरत थी? इस सवाल का जवाब देते हुए आयोग के ही एक अधिकारी ने कहा कि सीबीआई से मामले की जांच न हो, इसके लिए सारी पेशबंदियां की जा रही हैं. मायावती भविष्य की भाजपाई सियासत का तुरुप का पत्ता बनने वाली हैं, केंद्र सरकार की इन हरकतों से यही साबित हो रहा है. मायावती सीबीआई जांच के चपेटे में न आ जाएं, इसके लिए जांच, प्रति-जांच और प्रति-प्रति-जांच का नियोजित घनचक्कर चलाया जा रहा है. चीनी मिलों की बिक्री प्रकरण की सीबीआई से जांच कराने के बजाय उसकी जांच कॉरपोरेट अफेयर मंत्रालय के 'सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस' को क्यों और कब दी गई? सरकार ने इस पर गोपनीयता क्यों बरती? जब कॉरपोरेट अफेयर मंत्रालय के ही कम्पीटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मायावती को क्लीन-चिट दे दी थी, फिर उसी मंत्रालय के दूसरे विभाग को जांच क्यों दी गई? अगर सीसीआई की क्लीन-चिट गलत थी तो केंद्र सरकार ने उसके चेयरमैन और अन्य सम्बद्ध सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? इन बेहद जरूरी सवालों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अपने मुंह पर पट्टा बांधे हुई है.

- शासन का लक्ष्य है अरबों के घोटाले को हमेशा के लिए ठिकाने लगाना
- चड्ढा की कंपनियों को छोड़ कर केवल दो कंपनियों पर साधा निशाना
- सीसीआई की भौंडी लीपापोती से उड़ गए मोदी की नैतिकता के चीथड़े
- सीएफआईओ की फूहड़ रफूगीरी से दरारें ढंकने की कोशिश में सरकार

चीनी मिल बिक्री-घोटाले की एक और जांच का 'सीरियस-फ्रॉड'

दिलचस्प यह है कि 'सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस' (सीएफआईओ) ने अपनी जांच में दो कम्पनियों को फर्जी पाया. चीनी मिल बिक्री प्रकरण का यह अपने आप में 'सीरियस-फ्रॉड' है. मायावती के शासनकाल के दरम्यान वर्ष 2010-11 में 10 चालू चीनी मिलें और 11 बंद पड़ी चीनी मिलों की बिक्री प्रक्रिया में शामिल अधिकतर कंपनियों ने सिंडिकेट बना कर घपला किया. लेकिन सीएफआईओ ने केवल नम्रता मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड और गिरियाशो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को अलग (सिंगल आउट) किया. नम्रता मार्केटिंग ने देवरिया, बरेली, लक्ष्मीगंज (कुशीनगर) और हरदोई की चीनी मिलें खरीदने का दावा किया था और गिरियाशो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने रामकोला, छितौनी और बाराबंकी की चीनी मिलों को खरीदने का दावा पेश किया था. इन दोनों कम्पनियों के निदेशकों की ओर से हस्ताक्षरित बैलेंस शीट दावे के साथ संलग्न की गई थी. उसी आधार पर सरकार ने दोनों कंपनियों को नीलामी प्रक्रिया में शामिल होने के योग्य घोषित किया था. इसके बाद बिक्री प्रक्रिया पूरी हुई और कंपनियों को चीनी मिलें बेच दी गईं. अब 'सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस' ने अपनी जांच में इन दो कंपनियों की धांधली पकड़ी. यानि, 'बलि का बकरा' किसे बनाया जाएगा, यह तय हो रहा है. इस जांच के आधार पर राज्य चीनी निगम लिमिटेड के प्रधान प्रबंधक एसके मेहरा ने आनन-फानन गोमतीनगर थाने जाकर एफआईआर दर्ज करा दी. मेहरा ने नम्रता मार्केटिंग कंपनी के निदेशक दिल्ली के रोहिणी निवासी राकेश शर्मा, गाजियाबाद के इंदिरापुरम निवासी धर्मेंद्र गुप्ता, सहारनपुर के साउथ सिटी निवासी सौरभ मुकुंद, सहारनपुर के मिर्जापुर पोल-3 निवासी मोहम्मद जावेद, दिल्ली के रोहिणी निवासी सुमन शर्मा, सहारनपुर के तहसील बेहट निवासी मोहम्मद नसीम अहमद और मोहम्मद वाजिद अली के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया.

आप जैसे-जैसे खबर के विस्तार में जाएंगे, 'सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस' की जांच के पीछे के नियोजित षडयंत्र की परतें अपने आप खुलती दिखेंगी. महालेखाकार से लेकर सीसीआई के डीजी (अनुसंधान) की जांच में भी यह तथ्य खुल कर सामने आ चुका है कि चीनी मिलों की बिक्री प्रक्रिया में शामिल तमाम कंपनियां पूंजीपति पींटी चड्ढा से ही जुड़ी थीं. कुछ अन्य कंपनियां भी एक-दूसरे से जुड़ी छद्म कंपनियां थीं. लेकिन 'सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस' के जांच अधिकारियों को केवल दो कंपनियों का ही फर्जीवाड़ा दिखा. नम्रता और गिरियाशो जैसी दो कंपनियों के खिलाफ गोमती नगर थाने में जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई, वैसे ही पूर्व आईएएस अफसर सूर्य प्रताप सिंह ने बेसाख्ता कहा कि यह एफआईआर ही धोखा है. सरकार को अगर ठोस कार्रवाई करनी है तो उन नौकरशाहों पर करे, जिन्होंने चीनी मिलों की बिक्री प्रक्रिया में 'सक्रिय' भूमिका निभाई थी.

सत्ता की हांडी, सीसीआई की खिचड़ी और सीएफआईओ का रायता

मायावती के कार्यकाल में चीनी मिलों को औने-पौने भाव में बेचे जाने के मामले की जांच की घोषणा योगी सरकार ने सत्तारूढ़ होने के महीनेभर बाद ही अप्रैल महीने में कर दी थी. अगले ही महीने चार मई 2017 को कम्पीटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) ने मायावती सरकार को बेदाग बता दिया. जबकि महालेखाकार (सीएजी) की जांच रिपोर्ट पहले ही यह कह चुकी थी कि चीनी मिलों की बिक्री में घनघोर अनियमितताएं की गईं. सीसीआई के डायरेक्टर जनरल (इन्वेस्टिगेशन) नितिन गुप्ता ने भी अपनी छानबीन में पींटी चड्ढा की कंपनी के साथ नीलामी में शामिल अन्य कंपनियों की साठगांठ की पुष्टि की थी. गुप्ता ने जांच में यह पाया कि नीलामी में शामिल कई कंपनियां पींटी चड्ढा की ही मूल कंपनी से जुड़ी हैं, जबकि नीलामी की पहली शर्त ही थी कि एक मिल के लिए एक ही कंपनी निविदा-प्रक्रिया में शामिल हो सकती है. राज्य चीनी निगम लिमिटेड की 10 चालू चीनी मिलों की बिक्री प्रक्रिया में पहले 10 कंपनियां शरीक हुईं, लेकिन आखिर में केवल तीन कंपनियां वेव इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड, पीबीएस फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और इंडियन पोटाश लिमिटेड ही रह गईं. 10 चालू चीनी मिलों को खरीदने के लिए आखिर में बची तीन कंपनियों में 'गजब' की समझदारी पाई गई. जिन मिलों को खरीदने में पींटी चड्ढा की कंपनी 'वेव' की रुचि थी, वहां अन्य दो कंपनियों ने कम दर की निविदा (बिड-प्राइस) भरी और जिन मिलों में दूसरी कंपनियों को रुचि थी, वहां 'वेव' ने काफी कम दर की निविदा दाखिल की. इस तरह की मिलीभगत से पांच चीनी मिलें इंडियन पोटाश लिमिटेड ने और चार चीनी मिलें वेव इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदीं.

दसवीं चीनी मिल की खरीद में और रोचक खेल हुआ. बिजनौर की चांदपुर चीनी मिल की नीलामी के लिए इंडियन पोटाश लिमिटेड ने 91.80 करोड़ की निविदा दर (बिड प्राइस) कोट की. पीबीएस फूड्स ने 90 करोड़ की प्राइस कोट की, जबकि इसमें 'वेव' ने महज 8.40 करोड़ की बिड-प्राइस कोट की थी. बिड-प्राइस के मुताबिक चांदपुर चीनी मिल खरीदने का अधिकार इंडियन पोटाश लिमिटेड को मिलता, लेकिन ऐन मौके पर पोटाश लिमिटेड नीलामी की प्रक्रिया से खुद ही बाहर हो गई. लिहाजा, चांदपुर चीनी मिल पीबीएस फूड्स को मिल गई. नीलामी प्रक्रिया से बाहर हो जाने के कारण इंडियन पोटाश की बिड राशि जब्त हो गई, लेकिन पीबीएस फूड्स के लिए उसने पूर्व-प्रायोजित-शहादत दे दी. सीसीआई की जांच में यह भी तथ्य खुला कि पींटी चड्ढा की कंपनी वेव इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड और पीबीएस फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, दोनों के निदेशक त्रिलोचन सिंह हैं. त्रिलोचन सिंह के वेव कंपनी समूह का निदेशक होने के साथ-साथ पीबीएस कंपनी का निदेशक और शेयरहोल्डर होने की भी आधिकारिक पुष्टि हुई. इसी तरह वेव कंपनी की विभिन्न सम्बद्ध कंपनियों के निदेशक भूपेंद्र सिंह, जुनैद अहमद और शिशिर रावत पीबीएस फूड्स के भी निदेशक मंडल में शामिल पाए गए. मनमीत सिंह वेव कंपनी में अतिरिक्त निदेशक थे तो पीबीएस फूड्स में भी शेयर होल्डर थे. इस तरह वेव कंपनी और पीबीएस फूड्स की साठगांठ और एक ही कंपनी का हिस्सा होने का दस्तावेजी तथ्य सामने आया. यहां तक कि वेव कंपनी और पीबीएस फूड्स द्वारा निविदा प्रपत्र खरीदने से लेकर बैंक गारंटी दाखिल करने और स्टाम्प पेपर तक के नम्बर एक ही क्रम में पाए गए. आयोग के डीजी ने अपनी जांच रिपोर्ट में लिखा है कि दोनों कंपनियां मिलीभगत से काम कर रही थीं. चालू हालत की 10 चीनी मिलों की बिक्री प्रक्रिया में शामिल होकर आखिरी समय में डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लक्ष्मीपति बालाजी शुगर एंड डिस्टिलरीज़ प्राइवेट लिमिटेड, पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड, त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एसबीईसी बायोइनर्जी लिमिटेड और तिकौला शुगर मिल्स लिमिटेड जैसी कंपनियों के भाग खड़े होने का मामला भी रहस्य के घेरे में है.

सत्ता अलमबरदारों के होठ सिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं

चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड की बंद पड़ी 11 चीनी मिलों की बिक्री प्रक्रिया में भी यही हुआ. नीलामी में कुल 10 कंपनियां शरीक हुईं, लेकिन आखिरी समय में तीन कंपनियां मेरठ की आनंद ट्रिपलेक्स बोर्ड लिमिटेड, वाराणसी की गीतम रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड और नोएडा की श्रीसिद्धार्थ इस्पात प्राइवेट लिमिटेड मैदान छोड़ गईं. जो कंपनियां रह गईं उनमें पींटी चड्ढा की कंपनी वेव इंडस्ट्रीज के साथ नीलगिरी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, नम्रता, त्रिकाल, गिरियाशो, एसआर बिल्डकॉन व आईबी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड शामिल थीं. इनमें भी खूब समझदारी थी. नीलगिरी फूड्स ने बैतालपुर, देवरिया, बाराबंकी और हरदोई चीनी मिलों के लिए निविदा दाखिल की थी, लेकिन आखिर में बैतालपुर चीनी मिल के अलावा उसने बाकी पर अपना दावा छोड़ दिया. इसमें उसे जमानत राशि भी गंवानी पड़ी. बैतालपुर चीनी मिल खरीदने के बाद नीलगिरी ने उसे कैनयन फाइनैंशियल सर्विसेज लिमिटेड के हाथों बेच डाला. इसी तरह त्रिकाल ने भटनी, छितौनी और घुघली चीनी मिलों के लिए निविदा दाखिल की थी, लेकिन आखिरी समय में जमानत राशि गंवाते हुए उसने छितौनी और घुघली चीनी मिलों से अपना दावा हटा लिया. वेव कंपनी ने भी बरेली, रामकोला और शाहगंज की बंद पड़ी चीनी मिलों को खरीदने के लिए निविदा दाखिल की थी. लेकिन उसने बाद में बरेली और रामकोला से अपना दावा छोड़ दिया और शाहगंज चीनी मिल खरीद ली. बाराबंकी, छितौनी और रामकोला की बंद पड़ी चीनी मिलें खरीदने वाली कंपनी गिरियाशो और बरेली, हरदोई, लक्ष्मीगंज और देवरिया की चीनी मिलें खरीदने वाली कंपनी नम्रता में वही सारी संदेहास्पद-समानताएं पाई गईं, जो वेव इंडस्ट्रीज़ और पीबीएस फूड्स लिमिटेड में पाई गई थीं. यह भी पाया गया कि गिरियाशो, नम्रता और कैनयन, इन तीनों कंपनियों का दिल्ली के सरिता विहार में एक ही पता है. बंद पड़ी 11 चीनी मिलें खरीदने वाली सभी कंपनियां एक-दूसरे से जुड़ी हुई पाई गईं, खास तौर पर वे पींटी चड्ढा की वेव इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड से सम्बद्ध पाई गईं. 'सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस' ने अपनी जांच में इन सारे तथ्यों की अनदेखी कर केवल दो कंपनियों नम्रता मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड और गिरियाशो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड पर निशाना साधा. यह सारा प्रहसन केवल मायावती को बचाने के लिए खेला जा रहा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

सीतामढ़ी

चुनावी तैयारी को लेकर जातीय गोलबंदी शुरू

वाल्मीकि कुमार

आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. दलगत जिला सम्मेलनों के अलावा अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से वोटों की जातिगत गोलबंदी की कवायद भी शुरू हो गई है. कोई पार्टी हित में कार्यकर्ताओं से कार्य करने की अपील करने में लगा है, तो कोई महापुरुषों को जातीय बंधन में जकड़ कर अपना चुनावी राह आसान करने की फिराक में है. वहीं दूसरी ओर कुछ पार्टियों की नजर युवा व महिलाओं पर टिकी है, जो युवा हित की बात कर अपने दल के राजनीतिक भविष्य को मजबूत करने में लगे हैं. भारत-नेपाल सीमा पर अवस्थित उत्तर बिहार के सीतामढ़ी जिले में कुछ ऐसी ही सियासी बिसातें बिछने लगी हैं.

12 नवंबर को राजेंद्र भवन में लोजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन में आयोजित हुआ. इस मौके पर पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सह जमुई सांसद चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति में युवाओं की भागीदारी की बात कही. उन्होंने कहा कि विकसित बिहार के सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी युवाओं की है. युवाओं को सोचना होगा कि बिहार पिछडा क्यों है और इसके जिम्मेदार कौन-कौन हैं. उन्होंने कहा कि हमें राज्य को पिछड़ा बनाने के लिए जिम्मेदार नेताओं की पहचान करनी है और उन्हें सबक सिखाना है. चिराग पासवान ने कहा कि बेरोजगारी की समस्या को लेकर हमने वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की थी. हमने राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन करने की मांग की है. चिराग पासवान ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पुन: एनडीए की सरकार बनाना लोजपा का लक्ष्य है. कार्यकर्ताओं को अभी से 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाना चाहिए. इस मौके पर युवा सांसद ने प्रधानमंत्री की खूब तारीफ की. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता की और इसके लिए उज्जवला योजना को लागू किया. राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की जनता जब बाढ़ से कराह रही थी, तो वे पटना में महारैली करने में मशगुल थे. हम हर कदम पर जनता के साथ खड़े हैं.

इधर रालोसपा का अरुण गुट भी अभी से सक्रिय हो गया है. 28 अक्टूबर को शहर के राजेंद्र भवन में रालोसपा के अरुण गुट का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था. इस कार्यक्रम में जहानाबाद के सांसद अरुण कुमार सिंह ने कार्यकर्ताओं से पार्टी हित में बेहतर कार्य करने की अपील की. इस सम्मेलन में चिनारी विधायक ललन पासवान, विनोद कुमार निषाद, राम पुकार सिन्हा, दिनकर नारायण सिंह व प्रवीण कुमार शाही समेत कई नेताओं की मौजूदगी रही.

सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं, आम लोग भी जातिगत संगठनों के बैनर तले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी मांग बुलंद करने लगे हैं. लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल की 142वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्थानीय श्री राधा कृष्ण गोयनका कॉलेज के क्रीडा मैदान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया. आयोजित कार्यक्रम में खासतौर से पटेल बिरादरी के लोगों की भागीदारी ज्यादा रही. इसमें सीतामढ़ी के अलावा अन्य जिलों के पटेल समाज के नेता व कार्यकर्ताओं ने शिरकत की. कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह आमंत्रित थे. विधायक डॉ रंजू गीता, उमेश कुशवाहा, पूर्व सांसद नवल किशोर राय, राणा रंधीर सिंह चौहान, देवेंद्र साह, नागेंद्र प्रसाद सिंह, राम अशीष पटेल, पप्पू पटेल, राज कुमार पटेल, रामजी मंडल, बबलू मंडल, किरण गुप्ता समेत अन्य नेता भी इस मौके पर मौजूद थे. कार्यक्रम के दौरान पटेल सेवा संघ नामक संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने अपने समुदाय को बिहार की राजनीति में समुचित भागीदारी नहीं मिलने को लेकर रोष व्यक्त किया. इस मौके पर बेलसंड विधायक प्रतिनिधि राणा रणधीर सिंह चौहान ने तीन प्रखंड बेलसंड, तरियानी व परसौनी में लौहपुरुष के नाम पर चौक के नामकरण के साथ ही पटेल छात्रावास निर्माण हेतु विधायक कोष से राशि दिलाने की घोषणा की. वहीं पूर्व सांसद नवल किशोर राय ने भी अपना एक माह का अपना पेंशन लौहपुरुष के आदमकद प्रतिमा निर्माण हेतु देने की घोषणा की.

28 अक्टूबर को शहर के राजेंद्र भवन में रालोसपा के अरुण गुट का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था. इस कार्यक्रम में जहानाबाद के सांसद अरुण कुमार सिंह ने कार्यकर्ताओं से पार्टी हित में बेहतर कार्य करने की अपील की. इस सम्मेलन में चिनारी विधायक ललन पासवान, विनोद कुमार निषाद, राम पुकार सिन्हा, दिनकर नारायण सिंह व प्रवीण कुमार शाही समेत कई नेताओं की मौजूदगी रही.

कुल मिलाकर देखा जाए, तो सीतामढ़ी जिले में आगामी चुनावी संग्राम को लेकर राजनीतिक स्तर पर झंडा बुलंद होने लगा है. एक तरफ जमीनी स्तर पर शराबबंदी, बाल विवाह पर रोक व दहेज उन्मूलन को लेकर राज्य सरकार के कदमों पर चर्चा है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार की नोटबंदी व जीएसटी भी लोगों पर असर डाल रहा है. चौक- चौराहों से लेकर गांव की गालियों तक राजनीति की चर्चा के साथ ही वोटों की जातीय गोलबंदी की कवायद भी जोर पकड़ने लगी है. वैसे चुनाव में काफी वक्त है, लेकिन सम्भावित प्रत्याशियों की बेचैनी अभी से शुरू हो गई है. बिहार की सरकार में गठबंधन के समीकरण बदलने के बाद से नेताओं में और भी बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि पिछली बार गठबंधन सहयोगी रहे दल इस बार विरोधी हैं. उनके साझा उम्मीदवार और भी चिंतित हैं. राजनीतिक दलों का शीर्ष नेतृत्व सम्भावित प्रत्याशियों को किस तराजू पर तौलने की तैयारी में है, इसे लेकर भी चर्चा जारी है.■

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के नाम पर करोड़ों की ठगी

सुबील सौरभ

फर्जी कंपनी के सहारे लोगों को लालच देकर ठगी करने का धंधा आज भी बिहार में खूब फल-फूल रहा है. सरकार के लाख प्रयास के बाद भी चिटफंड के नाम पर कंपनी बनाकर लोगों को झांसे देकर ठगने का कारोबार चल रहा है. लालच में लोग फंस भी रहें हैं. मामला जब फंसता है, तो लोग पुलिस-प्रशासन को कोसते हैं. जबकि ऐसे लोग खुद लालच में फंसते हैं. ऐसी ही एक कंपनी ने बिहार के गया जिला मुख्यालय में महिलाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का लाभ देने और लोन दिलाने के नाम पर एक करोड़ से अधिक की राशि वसूल ली. इस राशि को वसूलकर मुख्य संचालक फरार हो गया जबकि इसके चार कर्मी गिरफ्तार हो गए. गिरफ्तार हुई सात युवतियों को पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया.

गया जिला मुख्यालय में डेल्हा थाना क्षेत्र के संजय नगर में जीआईजी मल्टी सर्विसेज फाइनेंस नाम की कंपनी ने महिलाओं से हजार-हजार रुपए वसूले. महिलाओं को आश्वासन दिया गया कि इसके बदले उन्हें 25 हजार का कर्ज मिलेगा और साथ ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का लाभ भी दिलाया जाएगा. महिलाओं के करीब पांच सौ से अधिक स्वयं सहायता समूह इस कंपनी के झांसे में आ गए. शुरुआती जांच में पता चला है कि उस कम्पनी ने महिलाओं से एक करोड़ से अधिक की राशि जमा कराई थी. लेकिन जब उन्हें ऋण देने की बारी आई, तो कम्पनी की तरफ से कोई न कोई बहाना बनाया जाने लगा. कई बार खाली हाथ लौटने के बाद कुछ महिलाएं ऋण सहित पैसे लेने के लिए अड़ गईं. तब कम्पनी के संचालक ने उन्हें चेक थमा दिया. जब वे चेक लेकर बैंक पहुंचीं, तो पता चला कि चेक फर्जी है. जब महिलाएं आश्वास्त हो गईं कि उनके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है, तो 6 नवम्बर को सभी महिलाओं ने एकसाथ उस कम्पनी के कार्यालय में पहुंचकर हंगामा किया. हंगामे की सूचना मिलने पर डेल्हा थाने की पुलिस वहां पहुंची. पुलिस ने जब पूरे मामले की जानकारी ली, तो ये भी पता चला कि वो कम्पनी अनुबंधित नहीं है. उसके बाद पुलिस द्वारा की गई छापेमारी में चार युवकों एवं सात युवतियों को हिरासत में लिया, जो सभी उस कम्पनी के कर्मचारी थे. लेकिन कम्पनी का मुख्य संचालक धर्मेन्द्र कुमार गिरफ्तार नहीं हो सका, वो फरार हो गया. गया शहर के धनिया बागीचा की मीना देवी ने कम्पनी पर महिलाओं को झासा देकर बड़ी राशि वसूलने का मामला दर्ज कराया है.

डेल्हा थानाध्यक्ष ने बताया कि जीआईजी मल्टी सर्विसेज फाईनेंस नाम की फर्जी कंपनी द्वारा महिलाओं को लोन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की वसूली की गई है. यह भी सूचना मिली है कि विभिन्न जगहों पर इस कंपनी के 52 अन्य सेंटर चल रहे हैं. हम उनके बारे में भी पता कर रहे हैं. इस फर्जीवाड़े का शिकार हुई धनिया बगीचा की संगीता कुमारी, निर्मला देवी, मीना देवी आदि ने चौथी दुनिया को बताया कि उस कम्पनी की तरफ से हमें फोन करके लोन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत नौकरी दिलाने की बात कही गई. हम चूंकि जरुरतमंद हैं, इसलिए हमने उनपर विश्वास कर लिया और पैसे जमा करा दिए. लेकिन जब समय पूरा होने पर हम पैसे लेने पहुंचे, तो हमें बरगलाया जाने लगा. फिर हमने हो-हल्ला किया और पुलिस में मामला पहुंचा.

गौरतलब है कि शहर के स्लम एरिया या ग्रामीण क्षेत्रों में कई संगठनों द्वारा स्वयं सहायता समूहों का गठन कर इन्हें बैंकों से रोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने का काम किया जाता है. इससे बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार भी मिलता है. लेकिन कुछ लोग अनपढ़ और भोलीभाली महिलाओं को ऋण, रोजगार या फावदे का झांसा देकर ठगी करने का काम करते हैं. अनपढ़ महिलाएं ऐसे लोगों के झासें में आकर फर्जीवाड़े का शिकार हो जाती हैं. पिछले दो दशक में गया शहर में ही दो दर्जन से अधिक ननबैंकिंग तथा फर्जी फाइनेंस कंपनियां गरीब महिलाओं के करोड़ों रुपए लेकर भाग चुकी हैं. इनसे जुड़े केस पुलिस में भी दर्ज हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया है. इसके बाद भी ठगी करने का धंधा बदस्तुर जारी है.■

हृदय योजना में शामिल हुआ बोधगया

क्या बहुरेंगे पुरातात्विक व धार्मिक स्थलों के दिन?

चौथी दुनिया ब्यूरो

बिहार में कई पर्यटन स्थल हैं, लेकिन पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिहाज से देखें, तो इनमें बोधगया का नाम सबसे ऊपर है. यह न केवल हिन्दू, बल्कि बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए भी पवित्र भूमि है. गया जहां हिन्दुओं के लिए मोक्षभूमि है, वहीं बोधगया तथागत की ज्ञानभूमि है. यही कारण है कि इन दोनों शहरों को पूरी दुनिया के लोग सम्मान, आस्था और श्रद्धा की नजर से देखते हैं. हालांकि पर्यटन और दर्शनार्थियों की सुविधा के लिहाज से बोधगया की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है. ऐसे तो यहां धार्मिक व पुरातात्विक स्थलों की भरमार है, लेकिन इनमें से ज्यादातर जीर्णशीर्ण हालत में हैं. लेकिन अब इनके दिन बहुरने की आहट सुनाई दे रही है. कहा तो यही जा रहा है कि अब इन इपेक्षित स्थलों का न सिर्फ कायाकल्प होगा, बल्कि यहां तक पर्यटकों की पहुंच को आसान बनाने की दिशा में भी काम किया जाएगा.

दरअसल, पुरातात्विक व धार्मिक स्थलों को विकसित करने के लिए भारत सरकार ने हृदय योजना की शुरुआत की है और इस योजना में गया-बोधगया को भी शामिल किया गया है. इस योजना के तहत चयन के बाद अब यहां विभिन्न पर्यटन स्थलों की सेहत को सुधारने की कवायद शुरू कर दी गई है. पहले चरण में अक्षयवट, रुक्मिणी और ब्रह्मसत सरोवरों की दशा दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है. इन स्थलों को विकसित करने के लिए 7.47 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है. इसके तहत पहले फेज में 1 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से अक्षयवट में चार यात्री शेड, तीन प्रवेश द्वार, एक डीलक्स शौचालय तथा दो प्याऊ का निर्माण किया जाना है. अक्षयवट के बाद अगले चरण में रुक्मिणी और ब्रह्मसत सरोवरों के विकास का कार्य शुरू किया जाएगा. इसके लिए 5 करोड़ 86 लाख रुपए का बजट निर्धारित है.

हृदय योजना के तहत गया-बोधगया को शामिल किए जाने के बाद अब स्थानीय लोगों व व्यापारियों में इसे लेकर आशा जगी है. लोगों में ऐसी उम्मीद है कि शायद अब उपेक्षित स्थलों की सेहत सुधरेगी और पर्यटकों का रूझान बढ़ेगा. यह सच है कि पर्यटन की असीम संभावनाओं के बाद भी गया-बोधगया को इसका लाभ नहीं मिल पाया है. पर्यटक यहां घूमने आते हैं और चले जाते हैं. लेकिन यहां की सुविधाएं पर्यटकों पर कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाती हैं. यदि यहां पर्यटकीय दृष्टिकोण से सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, तो गया-बोधगया का विकास तो होगा ही, इसके आसपास भगवान बुद्ध से जुड़े अन्य ऐतिहासिक स्थलों के भी दिन बहुरेंगे. लेकिन अब तक यही देखने को मिला है कि इन स्थलों के विकास की दिशा में सरकारी महकमा फिक्रमंद नहीं है. भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी अन्य घटनाओं का साक्षी रहे प्राक्बोधि पहाड़ (ढुंगेश्वरी), सुजाता स्तूप, मुचलिंद सरोवर जैसे स्थलों पर पर्यटको का पहुंचना काफी परेशानी भरा है. नतीजतन, बोधगया आने वाले अधिकतर देशी-विदेशी पर्यटक महाबोधि मंदिर तथा इसके आसपास बने विभिन्न देशों के बौद्धमठ और मंदिर को देखकर ही लौट जाते हैं. स्थानीय लोगों की मानें, तो यदि बिहार सरकार भगवान बुद्ध से जुड़े स्थलों पर सुविधाएं उपलब्ध करा दे, तो यहां पर्यटकों की संख्या में जरूर इजाफा होगा और इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे. भूरहा, गुनेरी और कुर्किहार जैसे स्थान भी भगवान बुद्ध की यादों को संजोए हुए है, जिनका विकास जरूरी है. कुर्किहार गढ़ का अवलोकन तो सूबे के मुखिया ने भी किया है, लेकिन अब तक इसका मुकम्मल विकास नहीं हो पाया है. एक तरफ तो स्थानीय लोग हृदय योजना में गया-बोधगया को शामिल किए जाने को लेकर खुश हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके मन में इसे लेकर सवाल भी है कि कहीं इस योजना का हश्र भी पूर्व की योजनाओं जैसा तो न होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

मखाना अनुसंधान केंद्र ने किया 'स्वर्ण वैदेही' का आविष्कार

अब खेतों में भी होगा मखाना का उत्पादन

ओनम

मिथिला की विशिष्ठ पहचानों में से एक मखाने का उत्पादन अब सिर्फ मिथिलांचल ही नहीं बल्कि देश के कोने-कोने में होगा. इसके लिए कृषि वैज्ञानिकों ने एक ऐसे बीज का आविष्कार किया है, जिसके माध्यम से मखाना का उत्पादन अब खेतों में भी संभव हो सकेगा. इससे मखाना उत्पादन के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी. अभी तक मखाना का उत्पादन तालाबों में ही किया जाता रहा है. दरभंगा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने 4-5 साल की कड़ी मेहनत के बाद स्वर्ण वैदेही नामक मखाना बीज का आविष्कार किया है. इसके जरिए खेतों में एक फीट पानी में भी मौजूदा पैदावार से दो गुना से ज्यादा मखाना का उत्पादन किया जा सकेगा.

वर्तमान में मिथिलांचल के दरभंगा, मधुबनी आदि इलाकों में तालाबों में मखाना की खेती पारंपरिक रूप से की जा रही है. मखाना की खेती के लिए तालाब में कम से कम 10 से 12 फीट पानी की आवश्यकता होती है. लेकिन स्वर्ण वैदेही बीज के जरिए खेतों में कम पानी में ही अच्छा उत्पादन किया जा सकता है. पूर्णिया, सुपौल, कटिहार, सहरसा आदि इलाकों में किसान इस बीज के सहारे मखाना का उत्पादन कर रहे है. बताया जाता है कि पारंपरिक रूप से तालाबों में मखाना का उत्पादन बहुत ही कम होता है. इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मखाना का बीज जब फूटता है, तो इसके दाने पानी की सतह पर फैल जाते हैं. पानी की सतह पर बैठकर इसको निकालना काफी कठिन कार्य है. ऐसे में उत्पादन का मात्र 40 से 50 प्रतिशत बीज ही निकल पाता है. नई विधि से खेतों में हो रहे उत्पादन से सौ फीसदी तक प्राप्त हो रहा है और गुणवत्ता में भी कोई अंतर नहीं है.

24 एकड़ में फैले मखाना अनुसंधान केंद्र में कई तालाब हैं, जिनमें मखाना का उत्पादन किया जाता है. शुरुआत में यह संस्था केंद्र सरकार की देखरेख में चल रही थी. लेकिन अब इसे पटना क्षेत्रीय कार्यालय से जोड़ दिया गया है. संस्थान के अध्यक्ष डॉ राजवीर शर्मा ने बताया कि कृषि वैज्ञानिकों को बीज की नई प्रजाति के शोध में चार से पांच साल लग गए. इस दौरान देश के उन कई क्षेत्रों से सैंपल इकट्ठा किया गया, जहां मखाना का उत्पादन हो रहा था और उन सैंपल्स पर शोध कार्य किया गया. जिसके बाद बीज की नई प्रजाति का आविष्कार हुआ. डॉ शर्मा बताते हैं कि अभी तक देश में मखाना की कोई अन्य दूसरी प्रजाति

नहीं है. लिहाजा कोई तय मापदंड नहीं होने के कारण इसके शोध में काफी वक्त लगा. उन्होंने बताया कि डॉ लोकेन्द्र कुमार और डॉ विनोद कुमार की अगुवाई में वैज्ञानिकों की टीम ने मखाना की इस नई प्रजाति का ईजाद किया. डॉ शर्मा के मुताबिक, नई प्रजाति के

डॉ राजवीर शर्मा, अध्यक्ष
मखाना अनुसंधान केंद्र

बीज से किसानों को एक ओर जहां उत्पादन में मदद मिलेगी, वहीं आर्थिक दृष्किोण से भी उन्हें फायदा मिलेगा. नए बीज से पौधों को तैयार कर नर्सरी में रखा जाता है. फिर इसके बाद तय समय के भीतर इन्हें रोपा जाता है. कृषि वैज्ञानिकों का दावा है कि इस नई प्रजाति की बीज से पूरे देश में मखाना का उत्पादन संभव है. फिलहाल अगर कोई किसान एक एकड़ वाले तालाब में मखाने का उत्पादन करता है, तो 15-20 हजार खर्च करने के बाद उसे 4 से 6 क्विंटल तक बीज मिलता है, यानि उसे खेती का केवल 35 से 42 प्रतिशत ही लावा मिल पाता है. लेकिन नए बीज की मदद से एक एकड़ क्षेत्रफल वाले खेत में उतने ही खर्च में 8 से 10 क्विंटल मखाना का उत्पादन संभव है. मखाना अनुसंधान केंद्र की ओर से इस वर्ष 100 रुपए प्रति किलो की दर से किसानों के बीच इस नई प्रजाति के बीज का वितरण किया जाएगा. दूसरी ओर, सबसे अहम बात यह है कि तालाबों की अपेक्षा खेतों में कम समय में ही फसल तैयार हो जाएगी. तालाबों में मखाना के उत्पादन में दस महीने का वक्त लगता है, जबकि खेतों में यह सीमा घटकर चार महीने हो जाएगी. मखाना अनुसंधान केंद्र की ओर से किसानों को इस नए बीज के बारे में जानकारी दी जा रही है. दरभंगा व आसपास के किसान खुद भी अनुसंधान केंद्र में जाकर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं.

वर्तमान में तकरीबन 40 हजार टन के आसपास मखाने का उत्पादन होता है, जिसे बढ़ाकर 2 लाख टन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. अभी कुल 15 हजार हेक्टेयर में इसकी खेती की जा रही है, जिसे बढ़ाकर 75 हजार हेक्टेयर किया जाना है. वहीं मखाना व्यवसाय में अभी कुल 40 हजार परिवार लगे हुए हैं, जिसे 2 लाख तक करने का लक्ष्य रखा गया है. नए बीज के आविष्कार के बाद इसके नाम को लेकर मतभेद उभर आया. काफी सोच विचार के बाद यह फैसला किया गया कि चूंकि मखाना मिथिला की मुख्य कीमती फसल है, जिसकी तुलना यहां सोने से की जाती है. इसलिए इसके नाम के आगे स्वर्ण लगाया गया और चूंकि मिथिला विदेह के नाम से विख्यात है. इसलिए दोनों नामों को जोड़कर इस बीज का नाम स्वर्ण वैदेही रखने का फैसला किया गया. ■

feedback@chauthiduniya.com

लेखकीय आत्मलज्जा का सवाल

अनंत विजय

हिंदी साहित्य के लिए फेसबुक और वहां चलने वाली बहसें काफी महत्वपूर्ण हो गई हैं. महत्वपूर्ण इस वजह से कि वहां साहित्य की नई-नई प्रवृत्तियों, रचनाओं पर तो संवाद होते ही हैं, साहित्यिक विवाद भी अक्सर अब पत्रिकाओं की बजाए फेसबुक पर उठने लगे हैं. कई बार विवाद सिले हुए पटाखे की तरह उठते ही फुस्स हो जाते हैं, तो बहुधा वो लंबे समय तक चलते हैं. समय के साथ-साथ इन विवादों का दायरा भी विस्तार लेता है. इन दिनों फेसबुक पर साहित्यिक चोरियों के आरोपों को लेकर घमासान मचा है. इस वक्त आरोपों के बवंडर में हैं हिंदी की कथाकार रजनी मोरवाल. रजनी मोरवाल पर आरोप है कि उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट की गई सामग्रियों का इस्तेमाल 'हंस' पत्रिका में प्रकाशित अपनी कहानी 'महुआ' में किया है. पुराने फेसबुक पोस्ट के साथ-साथ 'हंस' पत्रिका में प्रकाशित रजनी मोरवाल की कहानियों के अंश फेसबुक पर पोस्ट किए जा रहे हैं. तमाम तरह की बातें हो रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं. थाने, मुकदमे तक की बातें हो रही हैं. बौद्धिक संपदा की चोरी को लेकर कानूनची भी सक्रिय हैं. आरोपों के कोलाहल के बीच एक दिलचस्प मोड़ इस पूरे विवाद में आया. रजनी मोरवाल पर जिस फेसबुक पोस्ट को अपनी कहानी में उपयोग करने का आरोप लगा है, उसपर भी सवाल खड़े होने लगे हैं. फेसबुक पर सक्रिय चंद लोगों ने मूल फेसबुक पोस्ट को कुबेरनाथ राय जी के निबंध का हिस्सा बताकर पोस्ट करना शुरू कर दिया. स्तंभ लिखे जाने तक इस तरह की बात करने वाले लोग ये नहीं बता पाए हैं कि वो अंश कुबेरनाथ जी के किस निबंध का हिस्सा है. इसपर खामोशी है. कुछ लोगों का कहना है कि पूर्व में फेसबुक पर पोस्ट की गई साम्रगी और रजनी मोरवाल की कहानी के अंश दोनों गूगल बाबा की कृपा से अवतरित हुए हैं, इस कारण से दोनों में समानता है. अब सत्य क्या है इस बारे में तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा. फिलहाल तो रजनी मोरवाल पर संगीन आरोप हैं और साहित्य जगत में आम धारणा बनती जा रही है कि उन्होंने पूर्व में फेसबुक पर पोस्ट की गई सामग्री का उपयोग बगैर क्रेडिट दिए किया. फेसबुक पर सक्रिय लोग इसको साहित्यिक चोरी कह रहे हैं.

इस घटना के बाद कुछ उत्साही लोगों ने पुराने मामलों को उछालना शुरू कर दिया, गड़े मुर्दे उखाड़े जाने लगे. रजनी मोरवाल के मुद्दे के सामने आने के बाद जयश्री राय को लेकर भी लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी. उनपर भी आरोप लगाया जाने लगा कि उन्होंने अपनी कहानियों में विवेक मिश्र की नकल की, अपने उपन्यासों में मनीषा कुलश्रेष्ठ के उपन्यास के अंश का उपयोग कर लिया, कहीं मृदुला गर्ग के उपन्यास की पंक्तियां जस का तस उठाकर रख दी आदि आदि. जयश्री राय को लेकर इस तरह की चर्चा पुरानी रही है. इसके पहले हिंदी के जादुई यथार्थवादी कहानीकार उदय प्रकाश पर भी इस तरह के आरोप लगे थे. आलोचक रविभूषण के लेख से भी विवाद हुआ था. तब भी केस मुकदमे की बातें हुई थीं, लेकिन वो फेसबुक का दौर नहीं था. साहित्यिक चोरी को लेकर आजादी के पहले सरस्वती पत्रिका के अंकों में भी लेख आदि छपे थे, जो अब इतिहास के पन्नों में दर्ज है.

अभी दो साल पहले 2015 में भी साहित्यिक चोरी को लेकर फेसबुक पर काफी हो हल्ला मचा था. उस वक्त भी फेसबुक पर जारी चर्चा के आधार पर मैंने कुछ प्रवृत्तियों को रेखांकित किया था. दरअसल पिछले कुछ सालों में कुछ कवयित्रियां ऐसी आ गईं जो हैं जो पुराने कवियों की कविताओं की तर्ज पर शब्दों को बदलते हुए लोकप्रियता के पायदान पर ऊपर चढ़ना चाहती हैं. हिंदी साहित्य जगत में हमेशा से ऐसे लोग रहे हैं, जो इस तरह की प्रतिभाहीन लेखिकाओं की पहचान कर उनकी महात्वाकांक्षाओं को परवान चढ़ाते हैं. इसके कई फायदे होते हैं. उन फायदों की फेहरिश्त यहां गिनाने का कोई अर्थ नहीं है. 2015 में जब एक कवयित्री को लेकर विवाद उठा था, तब भी ये बात आई थी कि हिंदी के वरिष्ठ लेखक क्या कर रहे हैं, वो खामोश क्यों हैं. बयानवीर लेखक संगठन क्या कर रहे हैं. तब भी कुछ नहीं हो पाया था और आशंका है कि इस बार भी शायद ही कोई पहल हो या किसी प्रकार का ठोस कदम उठाया जा सके.

अभी दो साल पहले 2015 में भी साहित्यिक चोरी को लेकर फेसबुक पर काफी हो हल्ला मचा था. उस वक्त भी फेसबुक पर जारी चर्चा के आधार पर मैंने कुछ प्रवृत्तियों को रेखांकित किया था. दरअसल पिछले कुछ सालों में कुछ कवयित्रियां ऐसी आ गईं जो हैं जो पुराने कवियों की कविताओं की तर्ज पर शब्दों को बदलते हुए लोकप्रियता के पायदान पर ऊपर चढ़ना चाहती हैं. हिंदी साहित्य जगत में हमेशा से ऐसे लोग रहे हैं, जो इस तरह की प्रतिभाहीन लेखिकाओं की पहचान कर उनकी महात्वाकांक्षाओं को परवान चढ़ाते हैं. इसके कई फायदे होते हैं. उन फायदों की फेहरिश्त यहां गिनाने का कोई अर्थ नहीं है. 2015 में जब एक कवयित्री को लेकर विवाद उठा था, तब भी ये बात आई थी कि हिंदी के वरिष्ठ लेखक क्या कर रहे हैं, वो खामोश क्यों हैं. बयानवीर लेखक संगठन क्या कर रहे हैं. तब भी कुछ नहीं हो पाया था और आशंका है कि इस बार भी शायद ही कोई पहल हो या किसी प्रकार का ठोस कदम उठाया जा सके.

यहां चर्चा हो रही है हिंदी साहित्य में साहित्यिक चोरी के आरोपों की, जो कि एक बार फिर से उभर कर सामने आ गया है और इन दिनों हिंदी साहित्य जगत में विमर्श के केंद्र में है. साहित्यिक चोरी के आरोपों पर फेसबुक पर ही निंदा करके मामला शांत हो जा रहा है. क्या साहित्यिक चोरी का सवाल बड़ा साहित्यिक सवाल नहीं है, जिससे टकराने की कोशिश की जानी चाहिए. हद तो तब हो जा रही है, जब उन रचनाओं को पुरस्कृत भी कर दिया जा रहा है, जिनपर साहित्यिक चोरी का आरोप है. पुरस्कृत कर देने से रचनाओं को एक प्रकार की वैधता तो मिल ही जाती है. रघुवीर सहाय और पवन करण की कविताओं की छाया जिन कविताओं में दिखी थी, उनपर बहुत बातें हो चुकी हैं और उनको दोहराने का कोई अर्थ नहीं है. इस तरह की तिकड़म करने वाले लेखकों और लेखिकाओं को ये सोचना चाहिए कि साहित्य के पाठक इतने सजग हैं कि साहित्यिक चोरी करके कोई बचकर निकल नहीं सकता है. जब साहित्यिक चोरी पकड़ी जाती है, तो यह कहकर बचने और बचाने की कोशिश की जाती है कि दोनों रचनाकारों की जमीन एक रही होगी. इसके अलावा यह भी कहा जाने लगा है कि हिंदी में साहित्यिक चोरी के ज्यादतर आरोप लेखिकाओं पर क्यों लगते हैं. ऐसा हाल में देखा जाने लगा है, खासकर फेसबुक के लोकप्रिय होने के बाद से. लेकिन अगर बौद्धिक संपदा की चोरी है, तो चोरी है उसमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं किया जाना चाहिए.

फेसबुक पर जो साहित्य की दुनिया है, वो पत्र-पत्रिकाओं की साहित्यिक दुनिया से अलग है. फेसबुक के जरिए प्रसिद्धि हासिल करने वालों का एक पूरा गिरोह वहां सक्रिय है. फेसबुक ये साहित्यिक गिरोह अपने सदस्यों की रचनाओं की जमकर वाहवाही करने लग जाता है. लाइक्स और कमेंट की बौछार कर दी जाती है. आम और तटस्थ पाठकों को लगता है कि कोई बहुत ही क्रांतिकारी रचना आई है. फेसबुक पर सक्रिय इस साहित्यिक गिरोह के कर्ताधर्ता ये भूल जाते हैं कि ये आभासी दुनिया है और इसका फैलाव अनंत है. इसके दायरे में जो भी चीज आ जाती है वो बहुत दूर तक जाती है. सुदूर बैठा पाठक जो साहित्य के समीकरणों को नहीं समझता है और जो गंभीरता से साहित्य को घोंटता है, वह जब इस तरह की साहित्यिक चोरी को देखता है तो प्रमाण के साथ उजागर कर देता है.

अब अगर हम इस प्रवृत्ति के बढ़ते जाने की वजहों की पड़ताल करते हैं, तो सबसे बड़े दोषी के तौर पर मुझे तो गूगल बाबा ही नजर आते हैं. अपनी रचनाओं में अपने अनुभवों को और अपने ज्ञान को पिरोने की बजाए अब कुछ लेखकों ने शॉर्टकट रास्ता अपनाना शुरू कर दिया है. कहीं से किसी कथा का कोई प्लॉट दिमाग में आते ही सबसे पहले गूगल की शरण में जाते हैं. गूगल पर लगभग हर तरह की सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है. कई बार स्रोत के साथ तो कई बार बगैर किसी स्रोत के. लेखकों को अपने प्लॉट के हिसाब से जो सामग्री मिलती है, उसको उठा लेते हैं और उसको अपनी रचना में इस्तेमाल कर लेते हैं. जल्दी प्रसिद्धि की चाहत में स्रोत आदि की जांच करने या उसका उल्लेख करने का ध्यान नहीं रहता है. जिसका परिणाम यह होता है कि दो तीन लेखकों की रचनाओं में समानता दिखाई देती है. जिसकी पहले छपी होती है, उसकी बल्ले-बल्ले और जिसकी बाद में छपती है, उसपर साहित्यिक चोरी का आरोप.

साहित्यिक चोरी को लेकर हिंदी में गंभीर विमर्श की दरकार है और इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो इस बारे में संपादकों को भी सोचने की जरूरत है. जिन लेखकों पर आरोप लग रहे हैं उनको छापना बंद करना चाहिए या उनको अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका दिया जाना चाहिए. कायदे से तो हंस पत्रिका में रजनी मोरवाल की का पक्ष प्रकाशित होना चाहिए और संपादक को भी अपना पक्ष रखना चाहिए. पाठकों को पता तो लगे कि दोषी कौन है और दोषी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई. अन्यथा पत्रिका पर भी पाठकों का भरोसा कम हो सकता है. ■

anant.ibn@gmail.com

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

आरटीआई के माध्यम से कराएं अतिक्रमण पर कार्रवाई

चौथी दुनिया ब्यूरो

सरकारी भूमि का अतिक्रमण अब सामान्य अपराध बन गया है. अब तो ऐसा लगता है कि भूमि अतिक्रमण के प्रति आम लोगों के मन से प्रशासन का डर खत्म हो गया है. हर शहर और यहां तक कि गांवों से भी सरकारी जमीन के अतिक्रमण की खबरें आती हैं. कई जगह तो लोग अस्पताल, स्कूल और खेल के मैदान का भी अतिक्रमण कर लेते हैं. लम्बे समय से परती पड़ी जमीनों पर तो भूमाफिया कब्जा कर उसे मनमाने दाम पर बेचते हैं और खाली पड़ी सरकारी जमीन कुछ ही समय में रिहायसी इलाकों में बदल जाती है. ऐसा नहीं है कि इसमें सिस्टम की मिलीभगत नहीं होती, लेकिन जब मामला खुलकर सामने आता है और कार्रवाई की बात आती है, तो प्रशासन के हाथ-पांव फुलने लगते हैं, क्योंकि निर्मित भवनों और बसे हुए इलाकों को खाली कराना असंभव सा कार्य है. ऐसे कई मामले हाल में देखने को मिले हैं, जब अतिक्रमण खाली कराने गई पुलिस ही हमले का शिकार हो गई. ऐसे मामलों से बचने के लिए अतिक्रमण के समय ही कार्रवाई की जरूरत होती है. अगर आप अतिक्रमण का शिकार हो रही किसी जमीन को बचाना चाहते हैं, तो सूचना के अधिकार का सहारा ले सकते हैं. इसके लिए हम आपको उस आरटीआई आवेदन के बारे में बता रहे हैं.

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन.

महोदय,

निम्नलिखित निर्माणों में सरकारी भूमि का अतिक्रमण किया गया है:

कृपया इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं:

1. इन मामलों में से प्रत्येक में अतिक्रमित सरकारी भूमि का क्षेत्रफल बताएं.

2. ये अतिक्रमण किस प्रकार के हैं, विवरण दें?

3. क्या इन अतिक्रमणों के बारे में विभाग को पहले से पता है, यदि हां, तो बताएं:

क. पहली बार कब सूचना मिली?

ख. अभी तक उसको हटाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

ग. यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो क्यों?

घ. इन अतिक्रमणों को हटाने से सम्बन्धित सभी फाइलों तथा दस्तावेजों का मैं निरीक्षण करना चाहता हूं. कृपया मुझे दिन, समय तथा स्थान के बारे में सूचित करें, जब मैं निरीक्षण के लिए आ सकूं.

च. उन सभी अधिकारियों के नाम, पद तथा संपर्क का पूरा पता बताएं, जो इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए जिम्मेदार हैं.

छ. क्या ये अधिकारी कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई नहीं करने के कारण भ्रष्टाचार निवारण कानून की धारा 13(घ) तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 217 के उल्लंघन के दोषी हैं?

ज. इन अधिकारियों के खिलाफ कब तक कार्रवाई होगी?

झ. ये अतिक्रमण कब तक हटा दिए जाएंगे?

मैं आवेदन फीस के रूप में 10 रुपए अलग से जमा कर रहा/रही हूं.

या

मैं बीपीएल कार्ड धारी हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बीपीएल कार्ड नं..... है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से सम्बन्धित नहीं हो, तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों के समयावधि के अन्तर्गत हस्तान्तरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बताएं.

भवदीय
नाम:
पता:
फोन नं:
संलग्नक:
(यदि कुछ हो)

feedback@chauthiduniya.com

अगर आपके पास आरटीआई से संबंधित कोई ख़बर या सवाल है, तो हमें इमेल करें:
rti@chauthiduniya.com

जन्मदिन- 18 अगस्त 1900
पुण्यतिथि- 1 दिसम्बर 1990

पुण्यतिथि विशेष

संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष विजया लक्ष्मी पंडित

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यूं तो विजया लक्ष्मी पंडित नेहरू परिवार की सदस्य के रूप में जानी जाती हैं. लेकिन उनकी निजी उपलब्धियां तथा स्वतंत्रता आंदोलन व देश के विकास में उनके योगदान उन्हें वैश्विक पटल की एक महत्वपूर्ण शख्सियत के रूप में स्थापित करते हैं. ब्रिटिश राज के दौरान किसी कैबिनेट पद पर रहने वाली प्रथम महिला विजया लक्ष्मी पंडित ही थीं. 1937 में उनका निर्वाचन यूनाइटेड प्रॉविंसेज के विधानमंडल में हुआ तथा उन्हें स्थानीय स्वप्रशासन एवं जन-स्वास्थ्य विभाग में मंत्री बनाया गया. पहले वे 1939 तक तथा बाद में 1946 से 1947 तक इस पद पर रहीं. भारत की स्वतंत्रता के पश्चात वे राजनयिक सेवाओं का हिस्सा बनीं और विश्व के अनेक देशों में भारत के राजनयिक के पद पर कार्य किया. 1946 से 1968 के मध्य उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी किया. इस दौरान 1953 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया. वे इस पद पर आसीन होने वाली विश्व की प्रथम महिला बनीं. 1962 से 1964 तक वे महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद पर रहीं. इसके बाद 1979 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया.

विजया लक्ष्मी पंडित का जन्म 18 अगस्त 1900 को एक सम्पन्न कश्मीरी ब्रह्मण परिवार में हुआ था. उनके पिता मोतीलाल नेहरू प्रसिद्ध बैरिस्टर थे, जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दो बार कांग्रेस अध्यक्ष रहे. वहीं उनकी मां स्वरूपरानी जाने-माने कश्मीरी ब्रह्मण परिवार से थीं. विजया लक्ष्मी पंडित अपने बड़े भाई जवाहर लाल नेहरू से 11 वर्ष छोटी थीं. उनकी शिक्षा-दीक्षा मुख्य रूप से घर पर ही हुई. 1921 में काठियावाड़ के सुप्रसिद्ध वकील रणजीत सीताराम पंडित से उनका विवाह हुआ. रणजीत सीताराम पंडित ने कल्हण की ऐतिहासिक पुस्तक राजतरंगिणी का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया था. स्वतंत्रता आंदोलन का साथ देने के कारण अंग्रेजों ने सीताराम पंडित को गिरफ्तार कर लिया. 1944 में लखनऊ जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई. विजया लक्ष्मी पंडित तीन बेटियों चंद्रलेखा मेहता, नयनतारा सहगल और रीता धर की मां थीं. पति की मृत्यु के श्रीमती पंडित और

उनकी बेटियों को सम्पत्ति से बेदखल कर दिया गया और पूरी सम्पत्ति पर उनके पति के भाई ने कब्जा कर लिया. श्रीमती पंडित ने इसके लिए लड़ाई लड़ी. उन्होंने अपना हक तो पाया ही, उनके प्रयासों से ही आजादी के बाद महिलाओं को अपने पति और अपने पिता की सम्पत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ.

विजया लक्ष्मी पंडित की पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनैतिक थी और इसीलिए उनमें भी राजनीति के लिए उत्साह था. इस कारण वो राजनीति में शामिल हो गईं. 1919 में जब महात्मा गांधी आनन्द भवन में आकर रुके थे, उसी समय विजया लक्ष्मी पंडित उनसे मिली थीं और वे गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित हुईं. उसके बाद उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया. स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के दौरान विजया लक्ष्मी पंडित को 1932 में गिरफ़्तार भी किया गया था. जब देश में भारत सरकार अधिनियम, 1935 लागू हुआ और उसके तहत 1937 में कई प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनीं, उसी दौरान विजया लक्ष्मी पंडित को उत्तर प्रदेश (संयुक्त प्रांत) का कैबिनेट मंत्री बनाया गया. मंत्री स्तर का दर्जा पाने वाली वे भारत की वह प्रथम महिला थीं. द्वितीय विश्वयुद्ध आरम्भ होने के बाद मंत्रिपद छोड़ते ही विजया लक्ष्मी पंडित को फिर बन्दी बना लिया गया. जेल से बाहर आने पर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वे फिर से गिरफ़्तार की गईं, लेकिन बीमारी के कारण नौ महीने बाद ही उन्हें रिहा कर दिया गया. 1940 से 1942 तक वे ऑल इंडिया वुमेंस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के पद पर रहीं. 1945 में विजया लक्ष्मी पंडित अमेरिका गईं और अपने भाषणों के द्वारा उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में जोरदार प्रचार किया. 1946 में वे पुन: उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्य और राज्य सरकार में मंत्री बनीं. विजय लक्ष्मी पंडित ने रूस, अमेरिका, मैक्सिको, आयरलैण्ड और स्पेन में भारत के राजदूत और इंग्लैण्ड में हाई कमिश्नर के पद पर कार्य किया.

> ग्रामीण सभ्यता व संस्कृति से परिचय हेतु विजया लक्ष्मी पंडित ने 1952 में राजस्थान के बाडमेर जिले के सांस्कृतिक गांव बिसाणिया में मालाणी डेलूओं की ढाणी का ऐतिहासिक दौरा किया था. वे भारतीय संविधान सभा की सदस्य भी थीं. उन्होंने 1952 में चीन जाने वाले सद्भावना मिशन का नेतृत्व किया था. विजया लक्ष्मी पंडित आजादी के बाद 1962 से 1964 तक महाराष्ट्र की गवर्नर रहीं. 1964 में वे फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर लोकसभा में पहुंची. अंतिम दिनों में वे केन्द्र की कांग्रेस सरकार की नीतियों की आलोचना करने लगी थीं. उन्होंने इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गएउ आपातकाल का विरोध किया और जनता दल में शामिल हो गईं. द इवॉल्यूशन ऑफ इंडिया एवं द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस-ए-पर्सनल मेमोएर उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं.

ग्रामीण सभ्यता व संस्कृति से परिचय हेतु विजया लक्ष्मी पंडित ने 1952 में राजस्थान के बाडमेर जिले के सांस्कृतिक गांव बिसाणिया में मालाणी डेलूओं की ढाणी का ऐतिहासिक दौरा किया था. वे भारतीय संविधान सभा की सदस्य भी थीं. उन्होंने 1952 में चीन जाने वाले सद्भावना मिशन का नेतृत्व किया था. विजया लक्ष्मी पंडित आजादी के बाद 1962 से 1964 तक महाराष्ट्र की गवर्नर रहीं. 1964 में वे फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर लोकसभा में पहुंची. अंतिम दिनों में वे केन्द्र की कांग्रेस सरकार की नीतियों की आलोचना करने लगी थीं. उन्होंने इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गएउ आपातकाल का विरोध किया और जनता दल में शामिल हो गईं. द इवॉल्यूशन ऑफ इंडिया एवं द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस-ए-पर्सनल मेमोएर उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं. सक्रिय रूप से राजनीति से दूर होने के बाद भी वे सामाजिक गतिविधियों में भाग लेती रहीं. वे कई सामाजिक व महिला संगठनों से भी जुड़ी थीं. 1 दिसम्बर 1990 को देहरादुन के उत्तरी प्रात में उनका निधन हो गया. ■

दूसरा पहलू

जादू की छड़ी उर्फ़ सांप-नेवले का खेल

जादू की छड़ी का जिक्र आते ही आपके चेहरे पर एक सहज मुस्कराहट का आ जाना कोई असहज बात नहीं है. हो सकता है आपने अपने बचपन में किसी जादूगर को छड़ी के सहारे जादू के फ़न का मुज़ाहरा करते हुए न देखा हो, लेकिन जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर आपको इस छड़ी के कारनामों से दो चार होने का मौक़ा ज़रूर मिला होगा. इस छड़ी का उपयोग जादूगर हाथ ही सफ़ाई दिखाने के लिए करते हैं. जी नहीं! जान बूझ कर अंजान मत बनिए! हम जादू के खेल की बात कर रहे हैं. किसी जेब कतरे के हाथ की सफाई की नहीं. वैसे सच्चाई यह भी है कि दिल्ली के कई उस्ताद जेब कतरे इस फ़न में माहिर जादूगरों को पीछे छोड़ने की सलाहियत रखते हैं. यदि आपको दिल्ली की किसी खचा-खच भरी डीटीसी बस में सफ़र करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो, तो आप निश्चित रूप से हमारे इस बयान की तसदीक़ करेंगे. कहने का अर्थ यह है कि जादू की छड़ी की अनेकों विशेषताएं हैं, लेकिन उन में सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि जादूगर इसके सहारे चीज़ों को गायब कर सकते हैं या कोई नई चीज़ बना सकते हैं.

हमें लग रहा है कि आपको यह भूमिका कुछ ज़्यादा ही लम्बी और नीरस लगने लगी है. आपके चेहरे पर उकताहट की जो धुंधली लकीरें आ-जा रही हैं, उन्हें हम पढ़ सकते हैं. दरअसल बात राजनीति से जुड़ी हुई है और राजनीति में जनता कतरे की तरह होती है और नेता दरिया की तरह. यह एक सच्चाई है कि हमेशा क़तरा दरिया में नहीं समाता बल्कि कभी-कभी दरिया को भी क़तरे का सहारा लेना पड़ता है. इसलिए मुझे लगता है, बल्कि यक़ीन है कि आप हमारी स्थिति को समझ गए होंगे. हमारे पहले नेताजी (हालांकि वे पिछली बार चुनाव हारने के बाद से ही अगले चुनाव की तैयारी में जी-जान से लगे हुए हैं) ने जब चुनाव जीतने के बाद जादू की छड़ी की बात की थी, तो उस समय छड़ी का वास्तविक प्रतिरूप हमारे दिमाग़ में नहीं बन पाया था. हमें लगा था कि हमारे स्कूल के मास्टर साहब की छड़ी (जो बात-बे-बात बेक़ाबू होकर हम पे चलने लगती थी) के जैसी कोई चीज़ होगी. हम तो टीवी महाराज के शुक्रगुज़ार हैं, जिन्होंने इस रहस्य से पर्दा उठा कर हमें यह परम ज्ञान दिया कि जादू की छड़ी होती क्या है? हालांकि नेत-ाजी ने उस समय कहा था कि उनके पास जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन अब जबकि हम इस छड़ी की उपयोगिता समझ गए हैं, तो हमें लगने लगा है कि जादूगरों के बाद अगर किसी को इस छड़ी की सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो वह है हमारे खद्दर धारियों को. क्योंकि जनता के सवालों से बचने का, ख़ुद ही गायब हो जाने से सरल उपाय क्या हो सकता है? दरअसल हमारे नेताजी ने इस छड़ी की विशेषता इस सरलता से बताई थी कि हम स्वतः प्रवर्तित इस छड़ी की विशेषताओं के क़ायल हो गए थे.

साधारणतः किसी वस्तु की विशेषता उसके उपयोग या उपभोग में निहित होती है. यह आप भी जानते हैं और हम भी. लेकिन कभी-कभी उस वस्तु में निहित विशेषता के विपरीत उस से कुछ अतिरिक्त काम भी लिए जाते हैं, जिन्हें हम और आप आम बोलचाल की भाषा में जुगाड़ कहते हैं. जुगाड़ से कैसे काम चलाया जाता है, यह हम भारतीयों से ज्यादा कोई नहीं जानता. इस विद्या में हम से बड़ा विशेषज्ञ और ज्ञानी शायद ही दुनिया के किसी अन्य देश में मिले. यदि नोबेल पुरस्कारों में जुगाड़ से काम चलता तो कम से कम इस विद्या-विशेष में हर साल एक अदद नोबेल पुरस्कार का जुगाड़ कर लेने से हमें कोई माई का लाल नहीं रोक सकता था. इसीलिए जब हमारे नेताओं ने जादूगर की छड़ी को अपनी समस्याओं के हल या यूं कहूं कि समस्याओं से पीछा छुड़ाने का जुगाड़ बनाया, तो हमें कोई अचरज नहीं हुआ. क्योंकि वह हमारे नेता हैं और हम तो उनकी पैरवी मात्र करते हैं और जब हम इस फ़न के उस्ताद हैं तो उनकी महिमा तो अमरमपार है.

चूंकि हमारा सम्बन्ध देश के एक ऐसे गांव से है जहां उस समय (जब का क़िस्सा आपको सुनाने जा रहा हूं) सरकार की अनथक कोशिशों के बाद भी आधुनिक सुख-साधन की कोई सुविधा नहीं पहुंच पाई थी. ले दे के एक स्कूल था और बस एक हकीम जी थे, जो हर मर्ज़ का इलाज थे. उन्होंने अपने दादा जान की डायरी में दर्ज एक नुस्खे की मदद से एक माजून-ए-मुरक्कब तैयार किया था, जो ख़ुद हकीम जी की तरह हर मर्ज़ की दवा था. आपके पेट में दर्द है या दाढ़ में, इससे उनको कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता था. वे हर एक मर्ज़ का मुक़ाबला इसी दवा से करते थे. अब इस मुकाबले में जीत दवा की होती थी या मर्ज़ की, यह बताने के लिए एक अलग मज़मून की ज़रुरत होगी. बहरहाल इस दवा की ख़ासियत यह थी कि बस एक ख़ुराक लीजिए और दो तीन दिन के लिए दुनियादारी भूल जाइए. इसका ऐसा असर होता था कि आपने एक बार अपने ज़ेहन में जो बात सोच ली तो दवा का असर ख़त्म होने के बाद ही उस सोच से बहार निकल सकते थे. एक बार मैं गांव गया था, सर में हल्का सा दर्द था, मेरी शामत जो आई तो अम्मा से इसका ज़िक्र कर डाला. फिर क्या था फ़ौरन हकीम जी को बुलवा भेजा. मेरी लाख मिन्नतों का असर न तो अम्मा पर हुआ और न ही हकीम जी पर. दवा तो खानी पड़ेगी हकीम जी की लहक्दार आवाज़ एक नामालूम चैलेंज बन कर मेरे कानों पर टूट पड़ी थी. न चाहते हुए भी ज़हरमार करनी पड़ी. बस फिर क्या था, अभी-अभी आगरे से ताजमहल का नज़ारा कर के आया था, अब घर की दूसरी चीज़ों को कौन कहे मुर्ग़ी का दरबा तक ताजमहल लगने लगा और उनमें बंद मुर्ग़ियां नन्हीं-नन्हीं मुग़ल शहज़ादियां प्रतीत होने लगीं. देखिए फिर हम अपने विषय से भटकने लगे हैं. बात चूंकि जादूगर और उसकी छड़ी की चल रही है इसलिए बात यहीं तक सीमित रहे तो बेहतर है.

■ -क्रमशः

-शफीक आलम

feedback@chauthiduniya.com

भूल सुधार

चौथी दुनिया के 13 से 19 नवंबर के अंक में दूसरा पहलू कॉलम के तहत एक आर्टिकल 'कलयुग के अवतारी महाप्रभु' प्रकाशित हुआ था. इस आर्टिकल के लेखक नीलोत्पल मृणाल का नाम भूलवश नहीं दिया जा सका, जिसका हमें खेद है.

-चौथी दुनिया.

देशभर में विरोध झेल रही है पद्मावती

अक्सर देखा जाता है कि फिल्म निर्माता अपनी फिल्मों को लेकर रिलीज से पहले कई रियलिटी टीवी शो और दूसरी जगहों पर जाकर फिल्म का प्रामोशन करते हैं. ऐसे में पद्मावती का देशभर में विरोध जोरों पर चल रहा है. कुछ और हो या ना हो लेकिन इससे एक बात तो साफ है कि फिल्म को अच्छा खासा प्रमोशन मिल चुका है. इसलिए यह सोचना भी जरूरी है कि पद्मावती को लेकर सचमुच का विरोध हो रहा है या सिर्फ यह एक पब्लिसिटी स्टंट है!
फिल्म 1 दिसबंर को रिलीज होने वाली है. ऐसे में देशभर में फिल्म को लेकर जबरदस्त विरोध चल रहा है. लिहाजा फिल्म की रिलीज डेट भी टाली जा सकती हैं.

प्रवीण कुमार feedback@chauthiduniya.com

संजय लीला भंसाली की फिल्म हो और हंगामा ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता है. एक लंबे अरसे से देखा जा सकता है कि भंसाली की जब भी कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आती है तब-तब फिल्म को लेकर कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है. फिर वह चाहे उनकी फिल्म *हम दिल दे चुके सनम, गुजारिश, गोलियों की रासलीला: राम लीला* हो या फिर *बाज़ीराव मस्तानी*. ये सभी फिल्में कंट्रोवर्सी का हिस्सा रह चुकी हैं और बाद में बड़े पैमान पर हिट भी रही हैं. आप यूं भी कह सकते है कि फिल्म का कंट्रोवर्सियल होना अब घाटे का नहीं, मुनाफे का सौदा बन चुका है. देखा जाए तो आज के समय में किसी फिल्म का कंट्रोवर्सियल होना फिल्म का सबसे बड़ा पब्लिसिटी स्टंट माना जाता है. जहां फिल्म के कलाकार और डायरेक्टर्स फिल्म को हिट कराने के लिए कई टीवी शो और दूसरी तरह से फिल्म को प्रमोट करते हैं.

वहीं दूसरी ओर अगर किसी भी तरह फिल्म कंट्रोवर्सियल हो जाए तो समझो काम बन गया. क्योंकि फिल्म को प्रमोट करने का इससे अच्छा तरीका कोई और नहीं हो सकता.

पिछले कुछ सालों से हम देखते आ रहे हैं कि भंसाली ही नहीं कई ऐसी फिल्में भी हैं जो समय से पहले किसी ना किसी वजह से कंट्रोवर्सी का शिकार हुई और बाद में हिट भी. फिल्म *बैंडिट क्वीन, माई नेम इज खान, मर्डर, ओएमजी, डर्टी पिक्चर, हैदर, पीके, उड़ता पंजाब, राम लीला, बाज़ीराव मस्तानी, ऐ दिल है मुश्किल, दंगल* आदि फिल्मों को रिलीज से पहले लोगों का विरोध झेलना पड़ा. इतना ही नहीं जिन सिनेमाहॉल में ये फिल्में रिलीज हुईं, उन सिनेमाहॉल के बाहर प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़ फोड़ भी की. भंसाली की पिछली फिल्मों में *राम लीला* फिल्म के रिलीज होने से पहले ही बजरंग दल के सदस्यों ने कोर्ट में अर्जी दी थी कि राम लीला फिल्म में हिंदुओं के भगवान राम को लेकर काफी गलत इमेज प्रस्तुत की गयी है. दूसरी ओर फिल्म *बाज़ीराव मस्तानी* को लेकर बाज़ीराव के वंशजों ने इस फिल्म के कंटेंट पर आपत्ति जताई थी. हिंदू जनजागृति समिति के कार्यकर्ताओं ने फिल्म में इतिहास के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए कई जगह विरोध प्रदर्शन तक किया. बाद में कोर्ट ने कुछ बदलाव के साथ इन फिल्मों को रिलीज करने का ऑर्डर दिया.

हर बार की तरह इस बार भी भंसाली की फिल्म *पद्मावती* कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन चुकी है. फिल्म में दीपिका पादुकोण पद्मावती का किरदार निभाती नज़र आएंगी जबकि शाहिद कपूर राजा महारावल रतन सिंह और रणवीर सिंह अलाद्दीन ख़िलजी के रोल में दिखेंगे. जब से भंसाली ने पद्मावती पर फिल्म बनाने की सोची है तब से यह फिल्म कंट्रोवर्सी का हिस्सा रही है. शुरूआती दिनों से ही फिल्म का लगातार विरोध होता आ रहा है. जब पद्मावती की शूटिंग जयपुर के जयगढ़ किले में चल रही थी उसी दौरान राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने वहां जमकर हंगामा मचाया और तोड़-फोड़ की. इसी हंगामे के बीच किसी ने भंसाली पर हाथ तक छोड़ दिया. इस घटना के बाद बॉलीवुड के कई सितारों ने इसकी आलोचना की थी और संजय लीला भंसाली को अपना समर्थन दिया था. इसके बाद करणी सेना का कहना था कि उन्हें अलाउद्दीन ख़िलजी और रानी पद्मावती के बीच कथित रूप से फिल्माए जा रहे लव सीन पर आपत्ति है. लेकिन बात अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है. देशभर में फिल्म को लेकर अब आए दिन कुछ ना कुछ विरोध सामने आता जा रहा है. फिल्म देशभर में अब इतनी प्रसिद्ध हो चुकी है कि शायद ही किसी फिल्म को इतनी पब्लिसिटी मिली हो. इतना ही नहीं फिल्म का विरोध सड़कों पर पहुंच चुका है. बेंगलुरु में जुलुस निकालकर फिल्म को बैन करने की मांग की गई. राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने भारी-भरकम जुलुस निकाल कर भंसाली के खिलाफ जमकर गुस्सा निकाला. इससे पहले करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान के कोटा जिले में एक सिनेमाघर में तोड़फोड़ की. करणी सेना ने कहा, हम यह फिल्म नहीं देखना चाहते. किसने कहा कि हमें ये फिल्म देखनी है. हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे. हम अपनी जान दे देंगे. जब तक फिल्म पूरी तरह से बैन नहीं हो जाती, हम अपना विरोध जारी रखेंगे. यह हमारे राजपूत समाज की बेइज्जती है. इस फिल्म को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है.

इतना ही नहीं करणी सेना के लोगों ने पहले दीपिका की नाक काटने की और बाद में भंसाली का सिर काटने वाले को 5 करोड़ का इनाम देने तक की घोषणा कर दी हैं. करणी सेना की धमकी के बाद से भंसाली और दीपिका की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. बता दें कि फिल्म का विरोध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा हैं. इस बीच कई बॉलीवुड सितारों और अन्य लोगों ने भंसाली का समर्थन भी किया है. यह फिल्म एक दिसंबर को दुनियाभर में रिलीज होने वाली है लेकिन विरोध को देखते हुए लगता है कि पद्मावती की रिलीज डेट को आगे भी बढ़या जा सकता है. ■

बहुत हैं विरोध करने वाले

पद्मावती से जुड़ा विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. भंसाली की फिल्म पद्मावती अब सिर्फ फिल्म नहीं रह गई है, यह एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुकी है. जब से इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, यह विवादों में ही घिरी हुई है. जयपुर में फिल्म की शूटिंग के दौरान राजपूत करणी सेना के कुछ सदस्यों ने फिल्म के निर्देशक संजय लीला भंसाली को थप्पड़ मार दिया था. इसके बाद यह फिल्म और इससे जुड़ा मुद्दा सामाजिक और राजनीतिक रूप से देखा जाने लगा. इसके बावजूद राजस्थान से शुरू होते हुए फिल्म को बैन करने के लिए विरोध प्रदर्शन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र से होते हुए संसद के गलियारों तक पहुंच गया है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी फिल्म को बैन करने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जिम्मेदारी सेंसर बोर्ड की है और वो जो भी फैसला करेंगे, वो मान्य होगा.

- हरियाणा के दो मंत्री इस मुद्दे पर खुलकर सामने आए हैं. स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और उद्योग मंत्री विपुल गोयल का कहना है कि वो हरियाणा सरकार इस फिल्म पर बैन लगाने के लिए सेंसर बोर्ड से बात करेगी. अनिल विज ने कहा कि इतिहास से छेड़छाड़ करने वाली इस फिल्म को रिलीज होने नहीं दिया जाएगा. विपुल गोयल ने भी फिल्म रिलीज को रोकने के लिए स्मृति ईरानी को पत्र लिखा है.
- उदयपुर के मेवाड़ राजघराने के शाही सदस्य एमके विश्वराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी, स्मृति ईरानी और अन्य लोगों को एक पत्र लिखा है. इस पत्र में उन्होंने भंसाली की फिल्म पद्मावती को सर्टिफिकेशन देने से रोकने का निवेदन किया है.
- इन विरोधों से देशभर के सिंगल स्क्रीन मालिक बहुत घबराए हुए हैं. उन्हें डर है कि यदि फिल्म की रिलीज के बाद सिनेमा हॉल में तोड़-फोड़ की घटनाएं हुईं तो उनको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. इसीलिए उन्होंने तय किया है कि वो गृहमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग करेंगे. उनका कहना है कि यदि इसके बाद भी उनके सिनेमा हॉल्स को कुछ भी नुकसान हुआ तो उनकी भरपाई की जिम्मेदारी भी सरकार की ही होगी.
- महाराष्ट्र में पद्मावती को बैन करने की मांग की गई है. बीजेपी के विधायक सुजीत सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर राज्य में फिल्म को प्रदर्शित करने से रोकने की मांग की है. देवेन्द्र फडणवीस को लिखी चिट्ठी में उन्होंने कहा कि फिल्म में ऐतिहासिक तथ्य के साथ छेड़छाड़ की गई है. ऐसे में फिल्म को प्रदर्शित नहीं करने देना चाहिए.
- गुजरात के बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष आईके जडेजा ने सेंसर बोर्ड, केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग से फिल्म की रिलीज का विरोध किया था. जडेजा ने कहा था, गुजरात के 15-16 जिलों के राजपूत समाज ने पार्टी से इस फिल्म को बैन कराए जाने की मांग की थी. बीजेपी ने चुनाव आयोग, केंद्र सरकार और सेंसर बोर्ड को चिट्ठी भी लिखी, जिसमें कहा कि यह फिल्म क्षत्रीय समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है.
- फिल्म का विरोध सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस और दूसरे दलों ने भी की है. बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिंहा राव, मंत्री चिंतामणि मालवीय केंद्रीय मंत्री उमा भारती और साक्षी महाराज जैसे नेताओं ने इसका विरोध किया है. गुजरात केपूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने भी फिल्म की रिलीज का विरोध किया है.

सफाई दे चुके हैं भंसाली

जहां एक तरफ करणी सेना बार बार यह कह कर विरोध कर रही है कि पद्मावती को लेकर फिल्म में गलत धारणाएं प्रस्तुत की जा रही है वहीं दूसरी ओर भंसाली ने करणी सेना को भरोसा दिलाया है कि फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जाएगा जिससे किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचे. एक वीडियो जारी कर फिल्म के निर्देशक भंसाली ने साफ किया है कि फिल्म में खिलजी और पद्मावती के बीच कोई भी दृश्य नहीं है. ■

हर हाल में रिलीज होगी फिल्म: दीपिका

देशभर में विरोध प्रदर्शन के बाद दीपिका ने साफ कहा है कि फिल्म की रिलीज बहुत जरूरी है और इसे रिलीज होने से कोई नहीं रोक सकता. दीपिका ने आगे कहा, एक महिला के रूप में मैं इस फिल्म का हिस्सा बनकर और इस कहानी को दुनिया को बताने के लिहाज से बेहद गर्व महसूस कर रही हूं. ये एक ऐसी कहानी है जिसे लोगों को जानने को अधिकार है. दीपिका ने यह सवाल भी किया, हम एक राष्ट्र के रूप में कहां पहुंच गए हैं? ये डरावना है, ये बहुत डरावना है, हम आगे बढ़ने के बदले पीछे जा रहे हैं. हमारी अगर किसी को जवाबदेही है तो वह सिर्फ सेंसर बोर्ड को है और मैं जानती हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस फिल्म को रिलीज होने से कोई नहीं रोक सकता. ये सिर्फ पद्मावती से संबंधित नहीं हैं बल्कि हम एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं.■

सुब्रह्मण्यम स्वामी ने दीपिका को दिया जवाब

भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने दीपिका पादुकोण के पिछड़े होने के बयान पर निशाना साधा. स्वामी ने ट्वीट किया, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण हमें पिछड़े होने (रिग्रेशन) पर भाषण दे रही हैं. देश तभी आगे बढ़ सकता है, जब उनके परिपेक्ष्य से हम आगे बढ़ें.
उन्होंने यह टिप्पणी दीपिका द्वारा एक साक्षात्कार के बाद की है, जिसमें दीपिका ने अपनी आने वाली फिल्म पद्मावती पर उत्पन्न बवाल पर प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने कहा था, यह भयावह है, यह बिल्कुल भयावह है. इससे हमें क्या मिला और एक राष्ट्र के रूप में हम कहां पहुंच गए हैं? हम आगे बढ़ने के बदले पीछे गए हैं. जब एक ट्वीटर प्रयोगकर्ता ने स्वामी के ट्वीट पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि वह (दीपिका पादुकोण) नीदरलैंड की नागरिक हैं. स्वामी ने तब इस पर टिप्पणी करते हुए लिखा, अगर यह सही है, तो उन्हें अवश्य ही इसका खुलासा करना चाहिए. यह विशुद्ध रूप से केवल भारतीय बहस है. ■

शाहिद कपूर ने दिया भंसाली का साथ

सभी निर्देशक भंसाली का साथ दे रहे हैं. फिल्म में राजा रावल रतन सिंह की मुख्य भूमिका निभाने वाले शाहिद कपूर भी फिल्म के प्रमोशन में आगे आए हैं. हाल ही में एक रेडियो चैनल पर फिल्म को प्रमोट करने पहुंचे शाहिद ने कहा कि पद्मावती को एक मौका दीजिए. शाहिद ने कहा कि वो काफी समय से कह रहे हैं कि पहले फिल्म देख लीजिए, फिर कोई फैसला लीजिए. शाहिद ने कहा कि हम लोग सभी का सम्मान करते हैं और फिल्म को बहुत समझदारी और प्यार से बनाया गया है. इसीलिए इसे देखने से पहले कोई भी फैसला लेना गलत है.■

मुख्तार अब्बास नक़वी

फिल्म को लेकर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी इस मुद्दे पर कोई पक्ष लेते नहीं दिख रहे हैं. उनका कहना है कि इस फिल्म का विरोध करने वालों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये फिल्म सिर्फ एक फिल्म है. नक़वी ने कहा कि अगर आपको फिल्म में कुछ अच्छा लगता है तो देख लीजिए, वर्ना उसे वहीं छोड़ दीजिए. नक़वी ने यह भी कहा कि वो फिल्म देखना पसंद करते हैं लेकिन उसके पीछे के इतिहास-भूगोल पर ध्यान नहीं देते. लेकिन पद्मावती की रिलीज का साथ देने वाले मामले में उन्होंने कहा कि ना तो वो इसके विरोध में हैं ना ही इसके साथ.■

सलमान ने किया भंसाली का बचाव

पद्मावती को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. ऐसे में समर्थन के दो बोल भी फिल्म के लिए काफी अहम हो जाते हैं. अब हाल ही में बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान ने फिल्म को लेकर भंसाली का बचाव किया और अपनी राय रखी. सलमान ने कहा कि *जब आपके पास सेंसर बोर्ड है, तो सेंसर बोर्ड फैसला लेगा. यह सबसे बड़ा बोर्ड है. अगर सेंसर बोर्ड कहता है कि ये फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए तो आप आगे अपील करिए और देखिए फिर क्या होता है.*

सलमान ने आगे यह भी कहा, संजय बहुत ही ख़ूबसूरत फिल्में बनाते हैं. फिल्म की एक्ट्रेस भी बहुत अच्छी हैं. उनकी फिल्मों में कोई भी वल्गैरिटी नहीं होती. उनका पिछला ट्रेक रिकॉर्ड देखते हुए कहा जा सकता है कि वह कभी भी किसी चीज को उस तरीके से दर्शाएंगे नहीं जिससे लोगों की भावनाओं का ठेस पहुंचे. फिल्म देखे बिना भी मेरा विचार यही है. मुझे लगता है कि हमें सेंसर बोर्ड को फॉलो करना चाहिए. बिना फिल्म देखे किसी को कोई फैसला करने का हक नहीं है.■